

# अर्थव्यवस्था की स्थिति: विश्लेषणात्मक सिंहावलोकन और नीति संबंधी संभावनाएं

# 01

अध्याय

अपस्फीतिकारी संवेगों को लेकर मध्यावधिक संदर्भ में आशा और अल्पावधिक संदर्भ में बनी घबराहट दोनों एक साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर छायी हुई हैं। यह आशावाद ऐतिहासिक माल और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने, एयर इंडिया का निजीकरण करने का सिद्धांततः निर्णय लेने; दोहरे तुलनपत्र (टीबीएस) की चुनौतियों का सामना करने के लिए की गई कार्रवाई; और इस बढ़ते विश्वास से उपजा है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता मजबूत हो गई है। यह आशावाद, यहां तक कि इसे उल्लास भी कहा जा सकता है, वित्तीय बाजारों के बाण्ड, विशेषकर स्टॉकों के ऊंचे और बढ़ते मूल्यन में प्रकट हो रहा है। साथ ही, यह तनाव इस वजह से भी छाया है कि अनेक अपस्फीतिकारी संवेग एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रहे हैं जिसने अभी अपने विकास की पूरी रफ्तार हासिल नहीं की है और अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाई है। इन अपस्फीतिकारी संवेगों में ये शामिल हैं: कृषि आगम पर भार, क्योंकि अनाज-भिन्न खाद्य कीमतों में गिरावट हुई है; कृषि ऋण माफी और इसके परिणामस्वरूप बरती जाने वाली राजकोषीय कठोरता; तथा विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों की लाभ प्रदता में गिरावट जिनसे टीबीएस समस्या और बिगड़ी है। अब आगे के वर्ष के लिए, ढांचागत सुधार एजेंडा यह होगा कि वास्तविक कार्रवाई की जाए और किए गए वायदों को पूरा किया जाए-इनमें जीएसटी, एअर इंडिया और अति महत्वपूर्ण टीबीएस संबंधी कार्रवाई शामिल है। समष्टि आर्थिक चुनौती महत्वपूर्ण मौद्रिक, राजकोषीय और कृषि नीतियों के जरिए इन अपस्फीतिकारी संवेगों पर रोक लगाने की होगी। “अनुकूल परिस्थितियों” के जरिए पैदा हुए अवसरों, जिन पर हालिया आर्थिक समीक्षाओं में बल दिया गया था, को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

## I. प्रस्तावना

1.1 इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतरता की ऐसी प्रतिक्रियाओं से गुजर रही है जिन्हें बुनियादी आशावाद (अपने उमंगपूर्ण, उल्लसित रूप में) से लेकर मध्यावधि संदर्भ में कुछ तनावयुक्त और इससे आगे अल्पावधिक संदर्भ में अपस्फीतिकारी संवेगों का दौर कहा जा सकता है। इसलिए:

- ढांचागत सुधारों को लेकर पुनः आशा जगी है, जब माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया, जो लगभग डेढ़ दशक से तैयारी की प्रक्रिया से गुजर रहा था; एअर इंडिया का निजीकरण करने पर सिद्धांततः निर्णय लिया गया; ऊर्जा सब्सिडियों को और अधिक युक्तिसंगम बनाया गया और दोहरे तुलनपत्र (टीबीएस) की चुनौती का सामना करने

की कार्रवाई हुई;

- इस बात को लेकर विश्वास बढ़ा है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता अब मजबूत हो चुकी है जो अंशतः सरकार और आरबीआई की कार्रवाइयों के कारण और अंशतः इसलिए भी है कि तेल बाजार में हुए ढांचागत परिवर्तनों ने मूल्य वृद्धि का जोखिम कम कर दिया है, जो मुद्रास्फीति और भुगतान शेष को अस्थिर कर देती थी;
- वित्तीय बाजार में व्याप्त असाधारण आत्मविश्वास जो बाण्ड और विशेषकर स्टॉक के उच्च और बढ़ते मूल्यन में प्रतिबिंबित हो रहा है;
- विमुद्रीकरण की चुकाई गई अल्पकालिक कीमत को स्वीकारने के साथ इसके दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम;

- यह चिंता बढ़ रही है कि राज्य सरकारों के वित्त साधनों पर कृषि ऋण माफी का बुरा प्रभाव पड़ेगा; और
- यह अहसास कि अपस्फीतिकारी प्रवृत्तियां ऐसी अर्थव्यवस्था पर छाई हुई हैं जो अपने विकास की पूरी रफ्तार अभी हासिल नहीं कर पाई है और इसने अभी अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया है। इनमें शामिल हैं: (i) कृषि आगम पर भार क्योंकि अनाज-भिन्न खाद्यान्न कीमतों में तेजी से गिरावट हुई है; (ii) बजट घाटों पर रोक लगाने के लिए राज्यों द्वारा बरती गई राजकोषीय कठोरता-उत्तर प्रदेश इसका एक हालिया उदाहरण है जिसने ऋण माफी को समायोजित करने के लिए पूंजीगत व्यय में 13 प्रतिशत (उदय को छोड़कर) की कटौती कर दी है; (iii) विद्युत और दूरसंचार क्षेत्रों में गिरती लाभप्रदता जिनसे टीबीएस समस्या और बिगड़ी है; और (iv) जीएसटी के लागू होने से प्रारंभिक अड़चनें।

1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था की दीर्घावधिक आर्थिक चुनौतियों और प्राथमिकताओं पर आर्थिक समीक्षा 2016-17, खण्ड-1 में चर्चा की गई थी। अब आगे के वर्ष के लिए, ढांचागत और समष्टि आर्थिक एजेंडा अधिक स्पष्ट हो चुका है। यह ढांचागत सुधार संबंधी एजेंडा लिए गए निर्णयों और वचनबद्ध कार्रवाइयों (जीएसटी, टीबीएस और एयर इंडिया) को लागू करने का होगा।

1.3 देश भर के असंख्य प्रमाण यह बताते हैं कि ढांचागत सुधार बेहतर समष्टि आर्थिक संदर्भ में अधिक सफल होते हैं; वस्तुतः बेहतर समष्टि आर्थिक संदर्भ पूर्वापेक्षा ही हो सकते हैं। समष्टि आर्थिक गतिशीलता अपरिहार्य अड़चनों को कम करने और ढांचागत सुधारों को वित्तपोषित करने के लिए सहायता और संसाधन मुहैया कराती है। इसीलिए, अल्पावधिक संदर्भ में मांग संबंधी कमी पर काबू पाना बहुत जरूरी होगा। यहीं पर महत्वपूर्ण नीतिगत विकल्पों पर विचार करना होगा: मौद्रिक सुलभता की मात्रा और समय, की गई वचनबद्धताओं के संदर्भ में राजकोषीय समेकन की सीमा और संरचना; तथा अनाज-भिन्न कृषि क्षेत्र संबंधी कार्रवाई जहां इस वर्ष की स्थितियां-अच्छा मानसून और अधिक मांग-पिछले वर्ष की स्थितियों जैसी हो सकती हैं।

1.4 यह अध्याय तीन भागों में बांटा गया है: भाग-क में महत्वपूर्ण हालिया समष्टि आर्थिक घटनाक्रम पर

विश्लेषणात्मक चर्चा की गई है, जिसके बाद भाग-ख में 2017-18 के लिए आर्थिक संभावनाओं और उपयुक्त समष्टि आर्थिक नीति के दृष्टिकोण का मूल्यांकन किया गया है। भाग-ग में हालिया आर्थिक घटनाक्रम का वर्णन किया गया है।

## क. हालिया घटनाक्रम की विश्लेषणात्मक समीक्षा

1.5 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधिक संभावनाओं को लेकर जगी आशाएं अनेक ढांचागत सुधार कार्रवाइयों और घटनाओं से उपजी हैं और सबसे अधिक तो ये वित्तीय बाजार के विश्वास में दिखाई दे रही हैं।

## II. ऐतिहासिक कर सुधार: माल और सेवा कर ( जीएसटी )

1.6 जीएसटी की शुरुआत ऐतिहासिक आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धि की द्योतक है, और यह भारतीय कर और आर्थिक सुधारों के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। इसे नीचे दी गई सारणी-1 में सारबद्ध किया गया है और इस पर अध्याय-2 में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। यहां हम गलतफहमियों को दूर कर रहे हैं और भविष्य की बात करते हुए, अब तक अनदेखे रह गए कुछ लाभों पर प्रकाश भी डाल रहे हैं।

### 1. क्या कर ढांचे की जटिलता बढ़ गयी है?

1.7 अधिकांश टीकाओं में यह कहा गया है कि जीएसटी से कर ढांचा जटिल हो गया है जहां इस नयी व्यवस्था की आदर्श जीएसटी कर ढांचे से अव्यक्त तुलना की जाती है लेकिन असल में तुलना पिछली व्यवस्था से की जाती है। यह कहना ठीक नहीं है कि जीएसटी पिछली प्रतिस्थापित व्यवस्था से अधिक जटिल है। इसके दो संबद्ध कारण हैं।

1.8 पहले, प्रत्येक माल पर केंद्र द्वारा उत्पाद कर और राज्य का वैट लगाया जाता था। तब कम से कम 8-10 उत्पाद शुल्क दरें और राज्य के वैट की 3-4 दरें होती थीं, वैट-दरें सभी राज्यों में संभवतः भिन्न-भिन्न होती थीं। इस प्रकार, अनेक प्रकार की दरों (सिद्धान्ततः 29 राज्यों में कि 10 गुणा 4 गुणा) का ढांचा सिमट कर 6 प्रकार की दरों के ढांचे तक रह गया है।

1.9 सबसे जरूरी बात यह है कि एकरूपता या “एक वस्तु एक कर” का सिद्धांत पूरे भारत में अब हकीकत

## सारणी 1. जीएसटी के मुख्य लाभ

1. सहयोगपरक संघवाद को बढ़ावा देना	<ul style="list-style-type: none"> <li>घरेलू अप्रत्यक्ष कर संबंधी लगभग सभी निर्णय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाएंगे</li> </ul>
2. भ्रष्टाचार और हेराफेरी में कमी लाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्व-नियंत्रण; आदान कर क्रेडिट का दावा करने के लिए इन्वॉयस मैचिंग अन-अनुपालन को रोकेंगी और अनुपालन को बढ़ावा देगी। इससे पहले इन्वॉयस मैचिंग केवल अंतर-राज्यीय वैट लेन-देन के लिए होती थी और उत्पाद एवं सेवा कर तथा आयातों के लिए नहीं होती थी।</li> </ul>
3. जटिल कर संरचना को सरल बनाना और देशभर में कर दरों में एकरूपता लाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>8-10 केंद्रीय उत्पाद शुल्क दरें और 3-4 राज्य वैट दरें जो राज्यों में अलग-अलग लागू थी, जीएसटी की 6 दरों में विलयित की जाएंगी। सभी राज्यों में कर दरों में एकरूपता (एक वस्तु, एक कर)।</li> <li>राज्यों और केंद्र के अन्य कर और उपकर जीएसटी में मिला दिए जाएंगे।</li> </ul>
4. साझा बाजार बनाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>राज्यों के बीच व्यापार पर लगे हुए सभी कर और भौतिक प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाएंगे।</li> </ul>
5. आयात के नाम से होने वाले पक्षपात मिटाकर 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देना (नकारात्मक संरक्षण)	<ul style="list-style-type: none"> <li>आयात पर लागू घरेलू कर को अधिक कारगर और हेरा-फेरी की कम संभावना वाला बनाएगा (आईजीएसटी, जो पहले प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क का जोड़ होता था) जिससे घरेलू उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी हो सकेंगे।</li> </ul>
6. विनिर्माण के विरुद्ध कर पूर्वाग्रह मिटाना/ उपभोक्ता पर कर का बोझ घटाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध समाप्त करके और आदान कर क्रेडिट का प्रवाह सुसाध्य बनाकर जीएसटी प्रपाती प्रभाव (मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण पर कर-भुगतान और सभी पूर्ववर्ती चरणों पर कर जैसेकि केंद्रीय बिक्री कर) को काफी हद तक समाप्त कर देगा।</li> </ul>
7. राजस्व, निवेश, और मध्यकालिक आर्थिक संवृद्धि की गति में तेजी लाना	<ul style="list-style-type: none"> <li>निवेश बढ़ेगा क्योंकि पूंजी पदार्थों की खरीदारी पर आदान कर क्रेडिट का दायरा बढ़ेगा</li> <li>बेहतर अनुपालन से कर आधार का विस्तार होगा</li> <li>निर्यात सन्निहित कर समाप्त हो जाएंगे।</li> </ul>

बन गया है। पहले, भिन्न-भिन्न राज्यों में किसी खास उत्पाद पर अलग-अलग कर लग सकते थे और ये कर केंद्र द्वारा लगाए गए कर से भिन्न हो सकते थे।

1.10 अतः पिछली व्यवस्था की तुलना में, अब बहुलता के स्थान पर एकरूपता है तथा अब जटिलता भी काफी कम है।

### 2. अनुपालन का अतिरिक्त बोझ?

#### माल

1.11 यह सही है कि जो लोग अब जीएसटी व्यवस्था में शामिल हैं, उन सभी को अतिरिक्त प्रलेखीकरण अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी। परंतु विवरणी दाखिल करने की अपेक्षाओं में फार्मों का एक सेट (न कि तीन जैसाकि

कहा गया है क्योंकि पहले फार्म को भरने से अन्य दो अपने-आप भर जाते हैं) महीने में एक बार दाखिल किया जाना शामिल है। यह कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा क्योंकि पहले भी इसी प्रकार की, कभी-कभार अधिक दुरुह अपेक्षाएं राज्य के वैट और केंद्रीय उत्पाद की पिछली व्यवस्था में विद्यमान थी (सारणी 2)। मसलन, जैसाकि नीचे सारणी से पता चलता है, जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था में, तीन भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों को तीन पृथक विवरणियां उन तीन करों के मामले में दाखिल करना होती थीं, जो अब जीएसटी में सम्मिलित कर दिए गए हैं।

#### सेवाएं

1.12 पहले, चूंकि केवल केंद्र सेवा कर लगाता था,

और एजेंटों को केवल एक प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना होता था तथा इसलिए केवल एक के पास ही कर दाखिल करना होता था। अब एजेंटों को उन सभी राज्यों में पंजीकरण कराना होगा जिनमें वे कार्य करते हैं और प्रत्येक राज्य में इसे दाखिल करना होगा। जीएसटी परिषद् में हुई चर्चा के दौरान, यह प्रयास किए गए कि पहले वाली सरल व्यवस्था को बनाए रखा जाए, परंतु राज्य राजस्व में अपने उचित हिस्से की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में एकाधिक पंजीयन पर अड़े रहने में लगभग एकमत थे। इसके अलावा, बढ़ा हुआ बोझ कम एजेंट ही वहन करेंगे जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति हो और जिनकी पालन क्षमता भी इसके अनुरूप वृहत्तर होगी। भविष्य की बात करें तो अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए अधिक केंद्रीकृत प्रक्रियाओं की गुंजाइश मौजूद है।

**सारणी 2. दाखिल की जाने वाली विवरणियों की संख्या और बारंबारता: जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद**

जीएसटी से पहले		जीएसटी ढांचा
राज्य वैट	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक
सेवा कर	2 अर्ध वार्षिक	
केंद्रीय उत्पाद	1 प्रतिमाह + 1 वार्षिक	

**लघु व्यापारी**

1.13 लघु व्यापारियों और एजेंटों पर अतिरिक्त अनुपालन का बोझ पड़ने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इससे दूसरी दिशा में किए गए कुछ जरूरी परिवर्तनों की अनदेखी हो जाती है। जीएसटी ने कर व्यवस्था में समावेश के लिए कारोबार की आरंभिक सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की है जैसाकि सारणी 3 में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, पहले कर व्यवस्था में (राज्यों के वैट, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर) में आने वाले लगभग 87 लाख एजेंटों में से अब लगभग 70 लाख एजेंट ही जीएसटी व्यवस्था में रह गए हैं। 20 लाख रु० से कम कारोबार करने वाले काफी संख्या में छोटे व्यापारीगण जीएसटी के दायरे से बाहर चले गए हैं। इसके अलावा, यद्यपि नयी आरंभिक सीमा 20 लाख रु० है, तथापि, 75 लाख रु० तक का कारोबार करने वाले एजेंट अपने उस लेन देन पर (जो मूल्यवर्धित नहीं हो) मात्र थोड़ा कर चुकाने का विकल्प अपना सकते हैं, जिसे वे प्रत्येक महीने के बजाय प्रत्येक तिमाही में जमा किए जाने वाले

कम दस्तावेजों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

**सारणी 3. कर व्यवस्था में समावेश हेतु बिक्री की आरंभिक सीमा: जीएसटी से पूर्व और इसके बाद (रुपये में)**

जीएसटी से पूर्व		जीएसटी ढांचा
राज्य वैट	5-10 लाख रु०	• न्यूनतम 20 लाख रु० • 20-75 लाख रु० कम अनुपालन बोझ के अध्वधीन
सेवा कर	सेवा कर 10 लाख रु०	
केंद्रीय उत्पाद	1.5 करोड़ रुपये	

1.14 इस चिंता के चलते कि मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों के चलते प्रशासन अति उत्साही हो सकता है, सरकार ने यह संकेत दिया है कि इन प्रावधानों का बहुत कम प्रयोग किया जाएगा। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए समापन अवधि खंड (सनसेट क्लॉज़) लाया गया था कि ये प्रावधान अधिक से अधिक दो वर्ष बाद समाप्त हो जाएंगे।

**3. अलक्षित लाभ**

1.15 जीएसटी का एक महत्वपूर्ण अलक्षित लाभ यह है कि अब कपड़ा और परिधान क्षेत्र कर-व्यवस्था का पूर्ण रूप से हिस्सा है। पहले, मूल्य श्रृंखला के कुछ हिस्से, खासकर फेब्रिक्स, कर-व्यवस्था से बाहर थे, जिसकी परिणति अनौपचारिकता और कर-वंचना में होती थी। फेब्रिक्स के घरेलू उत्पादन की अपेक्षा आयात को तरजीह देने की कुछ विसंगतियां सुधारने की जरूरत है, परंतु समग्र कर आधार में विस्तार हुआ है।

1.16 इसी प्रकार, भूमि और भवन संपदा को कर-व्यवस्था में लाया गया है: अर्थात् “निर्माण कार्य सविदा” जो निर्मित किए जा रहे आवास के संदर्भ में हैं। इससे आगे चलकर अभी तक कर-व्यवस्था से बाहर रहे सीमेंट, इस्पात और अन्य बिक्रियों को औपचारिक रूप से कर-व्यवस्था में लाया जा सकेगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। औपचारिकरण इसलिए होगा कि बिल्डरों को कर-क्रेडिट का दावा करने के लिए इन आदान खरीदों के प्रलेखन की जरूरत होगी।

1.17 तीसरे, जीएसटी से आयातों पर लगाए जा रहे घरेलू करों की पिछली व्यवस्था—उत्पाद शुल्क कर को समायोजित करने के लिए प्रतिकारी शुल्क और राज्य वैट को समायोजित करने के लिए विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी)—की कमियां दूर हो जाएंगी। मसलन,

एसएडी 4 प्रतिशत की दर पर लगाया जाता था, यद्यपि अधिकांश राज्यों में मानक वैट 12.5 प्रतिशत था; जबकि सिद्धान्तः, आदान पर वैट अदा करने वाली फर्मों का दावा कर सकती थीं, लेकिन व्यवहार में कर क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाइयां थीं। जीएसटी में, केन्द्र और राज्यों द्वारा घरेलू बिक्री पर लगाए गए संपूर्ण कर (आईजीएसटी) लगाए जाएंगे जब श्रृंखला के नीचे तक उपलब्ध संपूर्ण कर क्रेडिट के साथ आयातित माल पहले देश में पहुंच जाएगा। इसकी परिणति आयात के संबंध में अधिक पारदर्शिता और अधिक प्रभावकारी कराधान के रूप में होगी।

1.18 शुरुआती लक्षण कर-आधार का विस्तार होने के हैं। जून और जुलाई 2017 के बीच, कर व्यवस्था से बाहर रहे 6.6 लाख नए एजेंटों ने जीएसटी में पंजीकृत किए जाने के लिए अनुरोध किया है। जैसे-जैसे इस व्यवस्था के औपचारिक कार्य के लिए प्रोत्साहन बढ़ेंगे, वैसे-वैसे, अनुमानतः इसमें लगातार वृद्धि ही होगी। आरंभिक अनुमान इंगित करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप कर-आधार में संभवतः भारी वृद्धि होगी।

1.19 दूसरा लाभ जीएसटी के प्रभाव और प्रत्यक्ष कर संग्रहण के संबंध में इसके द्वारा दी गई जानकारी का होगा। यह बहुत विशाल हो सकता है। विगत में, केंद्र के पास छोटे विनिर्माताओं और खपत से संबंधित मामूली आंकड़े होते थे (क्योंकि उत्पाद शुल्क विनिर्माण अवस्था में लगाया जाता था), साथ ही राज्यों के पास अपनी सीमाओं से बाहर कार्य कर रही फर्मों के कार्यकलाप विषयक आंकड़े भी अपर्याप्त होते थे। जीएसटी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य दोनों के ही आंकड़ों के सामान्य समूह का अपरिमित प्रवाह और उपलब्धता होगी, जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रहण अधिक प्रभावी होगा।

1.20 दीर्घावधिक लाभों में, वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाला जीएसटी का प्रभाव शामिल है। छोटे कारोबारी डिजिटल रूप से कर संदाय का एक वास्तविक समय ट्रेकर रिकार्ड बना सकते हैं और इसका उधारदाता संस्थाओं द्वारा क्रेडिट रेटिंग और उधार देने के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता है। फिलहाल, छोटे व्यवसायी ऋण की कमी से परेशान हैं, क्योंकि वे अपने वित्तीय सामर्थ्य को विश्वसनीय रूप से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं।

1.21 अंततः जीएसटी लागू होने पर पहले कुछ दिनों के भीतर ही, अंतरराज्यीय जांच-चौकियों को समाप्त करने की रिपोर्टें मिली हैं। अभी तक 24 राज्य ये जांच-चौकियां समाप्त कर चुके हैं, जबकि अन्य राज्य उन्हें समाप्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो परिवहन लागतों, ईंधन के उपयोग और भ्रष्टाचार में उल्लेखनीय कमी हो सकती है।

1.22 यह कहने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि भारत के भीतर संभार-तंत्र संबंधी लागतें अधिक हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन यह बताता है कि भारत में ट्रक एक दिन में अमेरिकी ट्रकों द्वारा तय की गई दूरी (800 किमी. की तुलना में 280 किमी.) की एक तिहाई दूरी ही तय कर पाते हैं। इससे प्रत्यक्ष लागतें (समय पर सुपर्दगी के संदर्भ में) बढ़ती हैं, अप्रत्यक्ष लागतें (अधिक इन्वेंटरी रखने वाली फर्मों) बढ़ती हैं, स्थान के विकल्प (उत्पादन के श्रेष्ठ स्थान की बजाय आपूर्तिकर्ताओं/ग्राहकों के लिए अपेक्षाकृत निकट स्थान रखने के संदर्भ में) बढ़ते हैं। इसके अलावा, वाहन चलाने में, लगने वाले कुल यात्रा समय का लगभग 40 प्रतिशत समय ही लगता है; जबकि जांच चौकियों और अन्य आधिकारिक ठहराव स्थलों पर कुल यात्रा समय का लगभग एक चौथाई समय लगता है। जांच चौकी समापन से चलने वाले ट्रक प्रतिदिन लगभग 6 घंटे अधिक, प्रतिदिन 164 किमी. अतिरिक्त के समतुल्य दूरी तय कर सकते हैं—इससे भारत वैश्विक औसत से ऊपर की ओर बढ़ सकता है और ब्राजील के स्तर तक पहुंच सकता है।

1.23 कुल मिलाकर, संभार-तंत्र लागतें (मोटे तौर पर परिभाषित, और जिसमें बिक्री में हानि को लेकर फर्मों के अनुमान शामिल हैं) अंतरराष्ट्रीय मानकों से तीन-चार गुना अधिक हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि अंतरराज्यीय व्यापार लागतें आंतरराज्यीय व्यापार लागतों से 7-16 गुना तक अधिक हैं। इस प्रकार, ये लागतें माल के अंतर-राज्यीय आवागमन में सीमावर्ती अवरोधों की स्पष्ट मौजूदगी का संकेत हैं।<sup>1</sup> जीएसटी के कार्यान्वयन से इन लागतों में जबरदस्त कमी आएगी और इससे देश में अंतरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।

#### 4. भावी चुनौतियां

1.24 सारणी 4 में जीएसटी करों और उन माल/क्षेत्रों

<sup>1</sup> राजस्व निरपेक्ष दर और माल एवं सेवा कर संरचना संबंधी समिति की रिपोर्ट : <http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/cea-rpt-rnr-new.pdf>

## सारणी 4. जीएसटी दरें और जीएसटी आधार से अपवर्जन

आईजीएसटी (%)			वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या*	जीएसटी के बाहर मुख्य वस्तुएं
सीजीएसटी (%)	एसजीएसटी (%)	कुल (%)		
0	0	0	88	• अल्कोहॉल
1.5	1.5	3	स्वर्ण और आभूषण	• पेट्रोलियम और ऊर्जा
2.5	2.5	5	173	• बिजली
6	6	12	200	• भूमि और स्थावर संपदा
9	9	18	521	• शिक्षा
14	14	28	229	• स्वास्थ्य देखभाल
उपकर ( बहुल )				

आईजीएसटी केंद्र और राज्य जीएसटी का योग है।

\*समानिकृत तन्त्र रेखाओं की संख्या द्वारा मापित, जिनको टैरिफ कोड में परिभाषित किया गया है।

की संरचना दर्शाई गई है जो जीएसटी व्यवस्था से बाहर हैं। जैसाकि सारणी 4 में दर्शाया गया है, कर संरचना और आधार से अपवर्जन में सुधार की बहुत गुंजाइश है। अल्कोहॉल, पेट्रोलियम और ऊर्जा उत्पादों, बिजली तथा भूमि एवं भवन संपदा जैसे कुछ लेन-देन जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, लेकिन जीएसटी से बाहर केंद्र और/अथवा राज्यों द्वारा उन पर कर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य, और शिक्षा कर-व्यवस्था से पूरी तरह बाहर हैं, जीएसटी के अंतर्गत छूट प्राप्त हैं और इन पर केंद्र और राज्यों द्वारा कर भी नहीं लगाया जाता।

1.25 बिजली को जीएसटी के दायरे में लाने से, भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा है क्योंकि बिजली पर कर विनिर्माता की लागत से जुड़ जाता है और आदान कर क्रेडिट के रूप में वापसी का दावा किया जा सकता है। भूमि और भवन संपदा को तथा अल्कोहल को इसके दायरे में लाने से पारदर्शिता में सुधार होगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी; स्वास्थ्य और शिक्षा को इससे पूरी तरह बाहर रखना साम्यता के साथ असंगत है क्योंकि ये ऐसी सेवाएं हैं जिनका अमीर लोगों द्वारा भरपूर उपभोग किया जाता है। इसके अलावा, स्वर्ण और आभूषण उत्पाद—ये ऐसी मर्दें हैं जिनका अत्यधिक अमीर लोगों द्वारा अनाप-शनाप उपभोग किया जाता है—पर 3 प्रतिशत कर अभी भी काफी कम है।

1.26 दरों की बहुलता अनेक उद्देश्यों को पूरा करने का एक तरीका है, जिनमें गरीब वर्गों को अनेक आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए दरों को कम

रखने की जरूरत शामिल है।

1.27 जीएसटी परिषद—जो सहकारी संघवाद के अभिशासन में एक उल्लेखनीय नवप्रवर्तन है, और इस संस्था ने अपने अस्तित्व के प्रारंभिक दस महीनों में ही ऐसा सिद्ध भी कर दिया है, को भारत को एक अच्छे जीएसटी की स्थिति से और अधिक बेहतर जीएसटी की ओर ले जाने के लिए आने वाले महीनों में इन चुनौतियों का सामना करना होगा

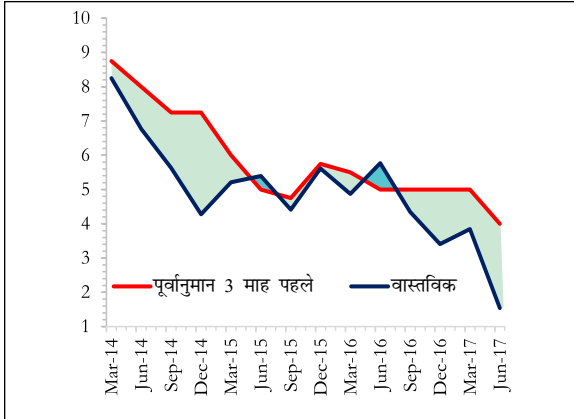
### III. कम मुद्रास्फीति की दिशा में सैद्धांतिक परिवर्तन?

1.28 क्या भारत कम मुद्रास्फीति की दिशा में स्फीतिकारी प्रक्रिया में संरचनागत परिवर्तन से गुजर रहा है?

1.29 अनुसंधान से पता चलता है कि लगभग पिछले पांच वर्षों में वैश्विक तौर पर और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में भी उपभोक्ता मूल्य से जुड़ी मुद्रास्फीति पेशेवर पूर्वानुमानों से सतत रूप से कम रही है। भारतीय संदर्भ में, साक्ष्य इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करते हैं— हालांकि दीर्घावधिक संदर्भ में, दोनों पक्षों की ओर से त्रुटियाँ हुई हैं। अभी हाल ही में ऐसे परिवर्तनों पर दृष्टि नहीं गई प्रतीत होती है (क्रमशः चित्र 1 और चित्र 2)। मिसाल के तौर पर, पिछली 14 तिमाहियों में छः तिमाहियों (2014 में तीन और हालिया अवधि में तीन) में मुद्रास्फीति का 100 आधार बिन्दु से अधिक आकलन किया गया जहां औसत त्रुटि 180 आधार बिन्दु की रही है (और यह भी केवल तीन माह पहले

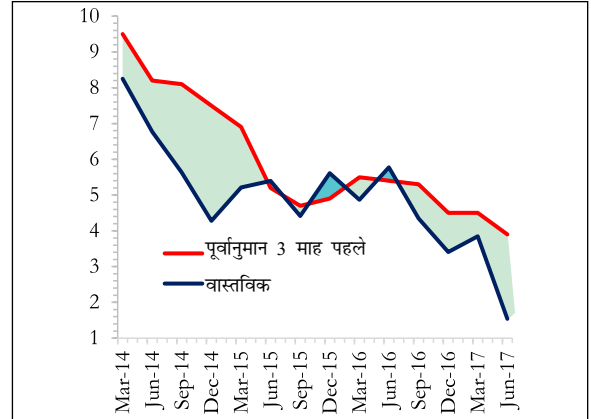


**चित्र 1. सीपीआई मुद्रास्फीति-आरबीआई पूर्वानुमान<sup>2</sup> और वास्तविक आंकड़े**



स्रोत: आरबीआई और समीक्षा परिकल्पना

**चित्र 2. सीपीआई मुद्रास्फीति-पेशेवर पूर्वानुमान<sup>2</sup> और वास्तविक आंकड़े**



के बहुत अल्पावधिक पूर्वानुमान के लिए) (चित्र 1)। यह भी ध्यातव्य है कि इस अवधि में 14 तिमाहियों में से 4 तिमाहियों (मार्च 2014, जून, सितम्बर और दिसम्बर 2015) में यह पूर्वानुमान परिणाम के 50 आधार बिन्दु की परिधि में था और 14 तिमाहियों में से एक तिमाही (दिसम्बर 2015) में यह 25 आधार बिन्दु की परिधि में था। पेशेवर अनुमानकर्ताओं का रिकार्ड भी ऐसा ही रहा है (चित्र 2)। पूर्वानुमान की तुलना में वास्तविक तौर पर कम मुद्रास्फीति तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के स्थायी रूप से गिर जाने जैसी असाधारण घटनाओं को परिलाक्षित कर सकती है।

1.30 आगे सवाल यह है कि क्या मुद्रास्फीति में कोई सैद्धान्तिक परिवर्तन हो रहा है और मौद्रिक प्रबंधन के लिए इसका क्या अर्थ है।

1.31 पहले चित्र 3 में दिखाए गए भारत में मुद्रास्फीति के दीर्घावधिक परिप्रेक्ष्य पर विचार करें। पिछले चार दशकों में (1977 से शुरू करके), मूल रूप से चार दौर रहे हैं: लगभग 23 वर्ष तक औसतन 9 प्रतिशत की उच्च मुद्रास्फीति; वर्ष 2000 और 2005 के बीच पांच वर्ष के लिए लगभग 4 प्रतिशत की कम मुद्रास्फीति; 2006-14 की अवधि में मुद्रास्फीति की जोरदार वापसी जो लगभग 9 प्रतिशत हो गई; और अब अपेक्षाकृत कम, संभवतः

बहुत कम मुद्रास्फीति का नया दौर।<sup>3</sup>

1.32 चित्र 3 मुद्रास्फीति के संचालकों को समझने में सहायता करता है। मुख्यतः उच्च मुद्रास्फीति और विशेषकर शीर्ष मुद्रास्फीति, वस्तु-कीमतों में वृद्धि, विशेषकर तेल की कीमतों और कृषि कीमतों में वृद्धि के साथ-साथ चलती है; कुछ मामलों में वे विनिमय दर में तेजी से हुए परिवर्तनों जैसे बिल्कुल ही अलग कारकों की वजह से भी होती है।

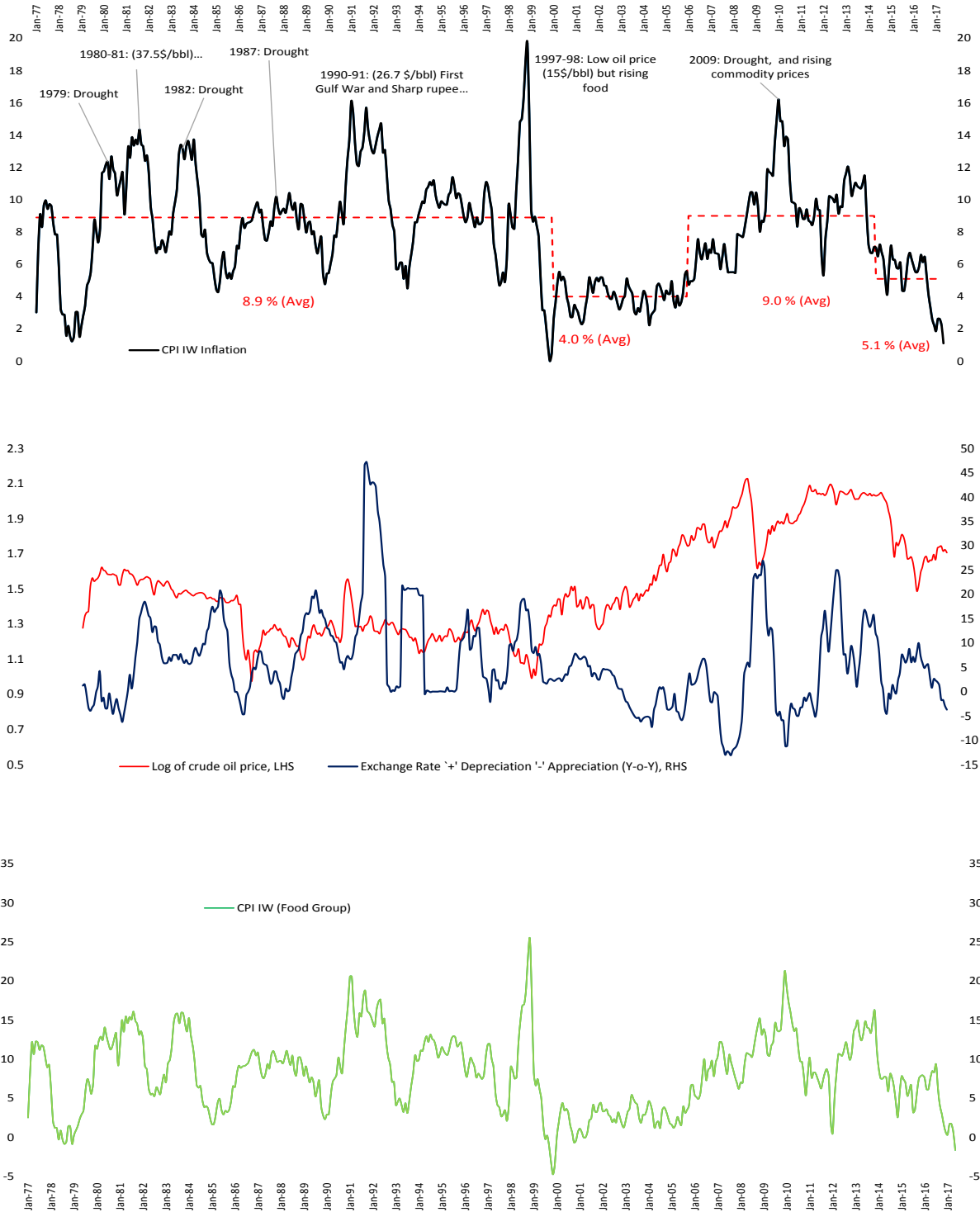
1.33 इसलिए, यदि तेल बाजार में और घरेलू कृषि में भी कोई ढांचागत परिवर्तन होते हैं तो स्फीतिकारी प्रक्रिया भी ढांचागत परिवर्तनों से गुजर सकती है। जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है, यह विश्वास करने के कुछ कारण अवश्य हैं कि दोनों परिवर्तन हो रहे हैं।

### तेल

1.34 अब तक यह लगभग स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो चुकी है कि भू-राजनीति का ज़िक्र तेल की कीमतों और इसीलिए उनसे आगे घरेलू मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों की सूची में किया जाए। लेकिन इन जोखिमों में संभवतः काफी कमी भी हो रही है। आज तेल बाजार कुछ साल पहले के बाजार की तुलना में इस अर्थ में बहुत भिन्न हो चुका है, कि जो तेल की कीमतों में कमी फ्रैक्चरिंग

<sup>2</sup> चित्र 1 में मुद्रास्फीति संबंधी पूर्वानुमान संबंधित मौद्रिक नीति विवरणों के फैनचार्ट में विश्वास बैंड के मध्यबिंदु के रूप में अनुमानित हैं। चित्र 1 और 2 मार्च 2014 में शुरू होते हैं क्योंकि 3 माह पहले के पूर्वानुमान (फैन चार्ट में निहित) पूर्ववर्ती अवधियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

<sup>3</sup> हैडलाईन सीपीआई मुद्रास्फीति अब 2 प्रतिशत से कम है किंतु परिष्कृत कोर भी (जो सभी अस्थिर खाद्य और ईंधन घटकों से अधिक रहती है) अब 4 प्रतिशत से कम हो गयी है। यह लगभग 9 प्रतिशत की भारत की दीर्घावधिक मुद्रास्फीति की औसत और जनवरी 2011 से सीपीआई-नई श्रृंखला में 6.8 प्रतिशत की परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति की औसत की तुलना में काफी बेहतर है।

चित्र 3. दीर्घावधिक मुद्रास्फीति<sup>4</sup> (1977-2017)

स्रोत: श्रम ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक और विश्व बैंक

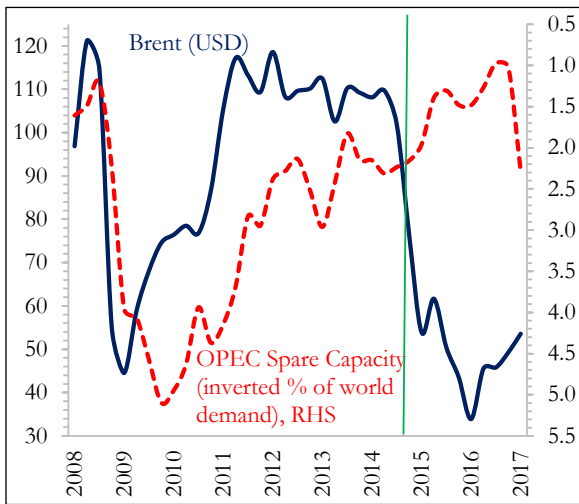
<sup>4</sup> श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित मुद्रास्फीति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह दीर्घावधिक अवधि के लिए उपलब्ध होती है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त (सीपीआई-सी) की नई श्रृंखलाएं वर्ष 2012-13 से ही उपलब्ध हैं। तथापि, दोनों श्रृंखलाएं (2012-13 से 2016-17) के लिए वह अवधि जब दोनों श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं, 0.94 के सहसंबंध गुणांक के साथ बहुत निकट रहती हैं।



अथवा कम से कम तेल की कीमतों में वृद्धि के जोखिमों को समाप्त कर रहा है।

1.35 हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जैसी परिष्कृत नई प्रौद्योगिकी की मेहरबानी से शेल ऑयल और गैस के दोहन के चलते, ओपेक-भिन्न, विशेषकर उत्तरी अमरीकी बाजारों से, तेल की आपूर्ति में बढ़ोतरी हो गई है, इसके अलावा, इस आपूर्ति की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि यह 50 डालर प्रति बैरल की कीमत के आसपास की दर पर लाभकारी है और इसकी आपूर्ति परंपरागत तेल के मुकाबले, कहीं कम पूंजी लागत के कारण कीमत संबंधी परिवर्तनों पर तेजी से प्रतिक्रिया करती है। परिणामस्वरूप, अब तेल की कीमतों पर ओपेक का उतना नियंत्रण नहीं है, जितना पहले होता था। चित्र 4 में ओपेक की क्षमता परिवर्तन तथा तेल कीमतें दर्शायी गई हैं। वर्ष 2014 से पहले, यह दोनों साथ-साथ चलती थीं, लेकिन तब से दोनों पूरी तरह अलग-थलग हो गई हैं।

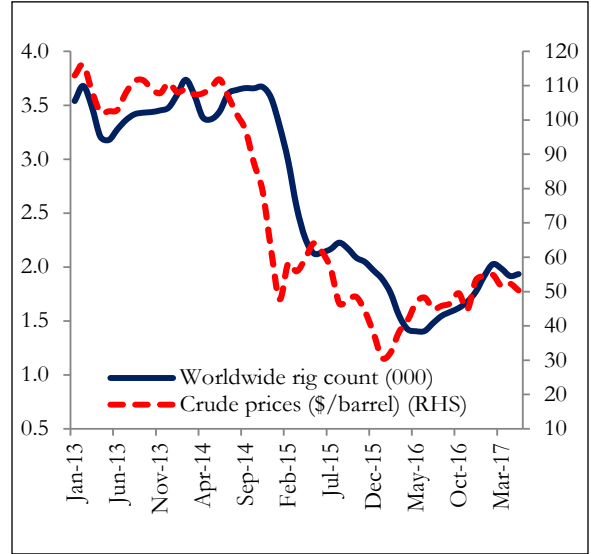
चित्र 4. ओपेक की कम होती बाजार शक्ति?



स्रोत: अमरीकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए)

1.36 चित्र 5 में विश्वव्यापी शेल रिग और तेल कीमतें दिखाई गई हैं। यहां भी यह संबंध असाधारण है, जहां रिग की क्षमता अपेक्षाकृत कम कीमतें होने पर गिरती है और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर तत्काल बढ़ती है।<sup>5</sup> शेल तेल और गैस का यह अकार्डियन जैसा स्वरूप तथा इस अनुमान के साथ कि अर्थक्षमता 50 डालर प्रति बैरल के आस-पास ही हासिल की जाती है, का अर्थ यह है कि तेल की कीमतों पर कुल मिलाकर रोक लगा दी गई है।

चित्र 5. शेल “अकार्डियन”



स्रोत: बेकर ह्यूज्स

1.37 इसलिए, भविष्य की बात करें तो, ऐसा नहीं है कि ये कीमतें अस्थिर नहीं रहेंगी और न ही यह होगा कि ये 50 डालर की “सीमा” से ऊपर कभी नहीं बढ़ेंगी। लेकिन शेल प्रौद्योगिकी जरूर सुनिश्चित करेगी कि वे इस सीमा से ऊपर बहुत देर तक न रह सकें क्योंकि शीघ्र आपूर्ति की प्रक्रिया इन कीमतों को शेल के उत्पादन की सीमांत लागत की ओर वापस ले जाएगी। नवीकरणीय स्रोतों की लागत और कीमतों में जबरदस्त गिरावट इस रुझान को और मजबूत बनाएगी।

1.38 संक्षेप में, भू-राजनीतिक जोखिम पहले की तरह खतरनाक नहीं हैं। प्रौद्योगिकी ने भारत को भू-अर्थव्यवस्था (ओपेक) और भू-राजनीति (मध्य पूर्व) के उतार-चढ़ावों के प्रति कम संवेदनशील बना दिया है। यदि ये परिवर्तन स्थायी सिद्ध होते हैं और जिस हद तक स्थायी हो, तो उस संख्या में स्फीतिकारी प्रक्रिया के लिए परिणामों को ध्यान में रखना होगा।

### कृषि

1.39 लंबे समय (दशकों तक) तक किए गए मूल्यांकनों के अनुसार भारतीय कृषि का निष्पादन साधारणतः सफल रहा है। एक उपलब्धि यह है कि उत्पादन-विशेष तथा अनाज, जो उपभोग की मुख्य मद है, का उत्पादन कम

<sup>5</sup> रिग और तेल की कीमतों के प्रवाह के बीच मुख्यतः इसी तरह का संबंध है।

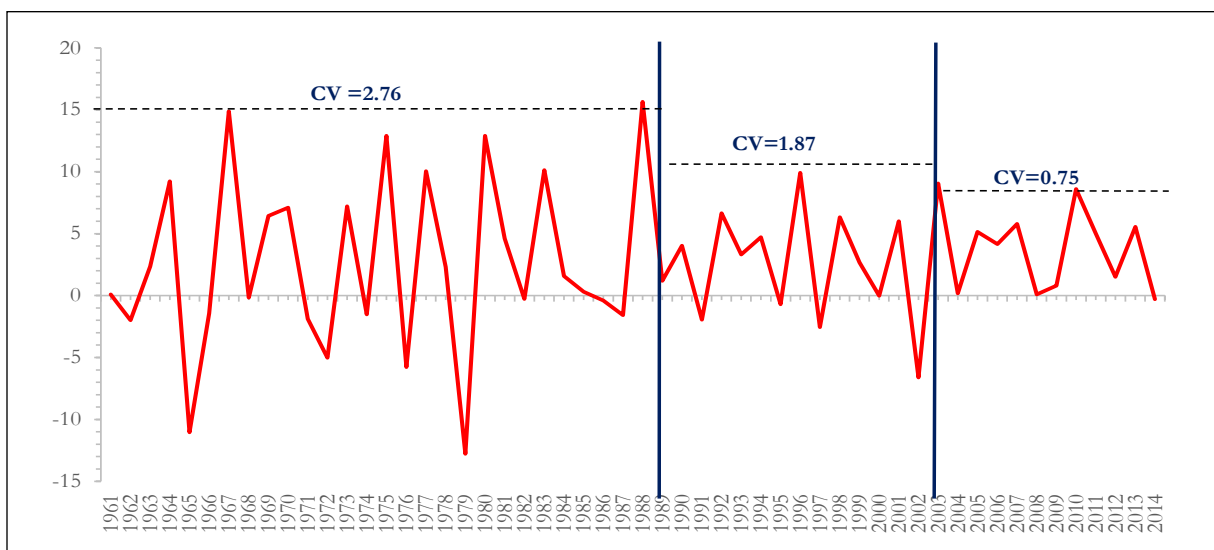
अस्थिर और कमजोर मानसून के प्रति अधिक प्रतिरोध क्षम हो गया है।

1.40 चित्र 6 में कृषि जीडीपी में वास्तविक वृद्धि दर्शाई गई है। औसत वृद्धि 3 प्रतिशत के आसपास रही है किंतु उत्पादन में वृद्धि की अस्थिरता जो परिवर्तन के गुणांक द्वारा मापी जाती है, 1988-2004 की अवधि में 1.87 प्रतिशत से घट कर 0.75 प्रतिशत हो गई है।

1.41 चित्र 7 और 8 में क्रमशः अनाजों और दालों के उत्पादन को दर्शाया गया है। यहां भी, अनाजों और

विशेषकर दालों दोनों में व्याप्त अस्थिरता में उल्लेखनीय कमी स्पष्ट है (सारणी 5)। पिछले दशक में परिवर्तन के गुणांक में जबरदस्त कमी हुई है। चित्र 6 से 8 के बारे में जो बात विशेष है, वह यह है कि मंदी की स्थिति बहुत कम हैं (1 प्रतिशत अथवा कम की वृद्धि दर)—मुद्रास्फीति के खतरे की मुख्य अवधियों में। उच्च उत्पादक, सिंचाई-प्रधान राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हाल ही में मध्य प्रदेश भी) में काफी अधिक समर्थन मूल्यों और प्रभावी खरीद ने अनाज उत्पादन में स्थिरता प्रदान की है।

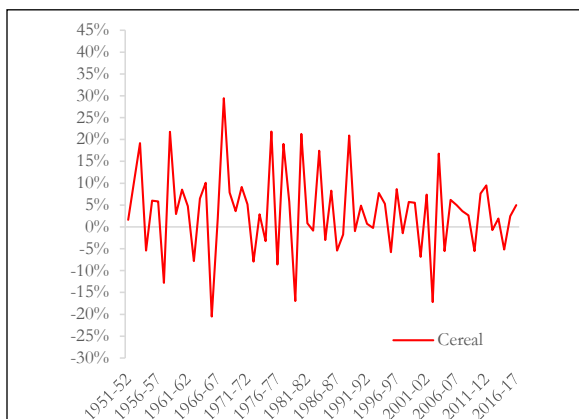
चित्र 6. भारत में कृषि जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: सीएसओ

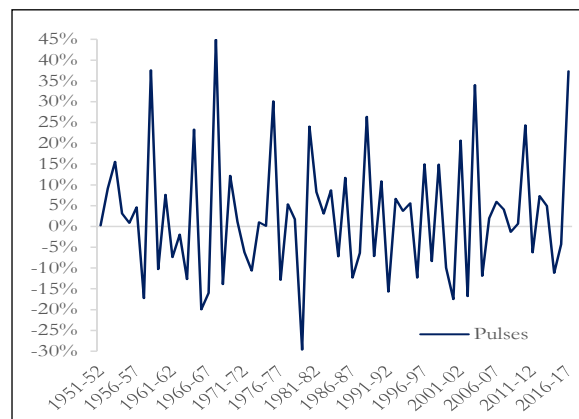
टिप्पणी: सीवी-परिवर्तन का गुणांक

चित्र 7. अनाज उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय

चित्र 8. दालों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)



**सारणी 5. दालों और अनाजों के उत्पादन में परिवर्तनीयता**

	औसत		परिवर्तन का गुणांक	
	दाल	अनाज	दाल	अनाज
1951-2017	2.6%	3.6%	5.88	2.69
1951-1965	2.2%	3.4%	6.86	3.19
1966-1989	2.8%	5.6%	6.03	2.04
1990-2004	0.7%	1.5%	20.35	5.01
2005-2016	5.3%	2.7%	2.42	1.64

स्रोत: अर्थ और सांख्यिकी, कृषि मंत्रालय

1.42 तो फिर, वर्ष 2007-2011 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल का क्या कारण था? वह घटना घरेलू नीति के साथ-साथ वैश्विक तेल और कृषि मूल्यों में उछाल के सम्मिलन से हुई थी। घरेलू नीति के संबंध में वर्तमान सरकार ने उस रूपरेखा में परिवर्तन करके कार्रवाई की है जिनमें कृषि मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाया है, कृषि विपणन व्यवस्थाओं को उदार बनाया है तथा मुद्रास्फीति लक्ष्य एवं-मौद्रिक नीति समिति की रूपरेखा को संस्थागत रूप दिया है।

1.43 हालिया महीनों में खाद्य कीमतों में हुई कमी के चलते मुद्रास्फीति अभूतपूर्व रूप से कम स्तरों पर आ चुकी है जो जून में 1.5 प्रतिशत हो गई। यह स्थिति निश्चित रूप अस्थायी है; शीघ्र ही खाद्य कीमतें सामान्य हो जाएंगी। किंतु जब यह स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो यह संभावना नहीं है कि मुद्रास्फीति अपने 2014 से पहले के स्तर तक वापस चली जाएगी? इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में गहन और प्रौद्योगिकी के कारण होने वाले परिवर्तन तथा घरेलू नीति और कृषि बाजारों में हुए सुधार भारत में कम मुद्रास्फीति-का नया युग प्रवर्तित कर सकते हैं।

**IV. विश्वास/उल्लास: आस्ति मूल्यों और वास्तविक अर्थव्यवस्था में अंतर**

1.44 जैसाकि बाद में भाग ग में विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है, अनेक संकेतक-सकल मूल्य वर्धन

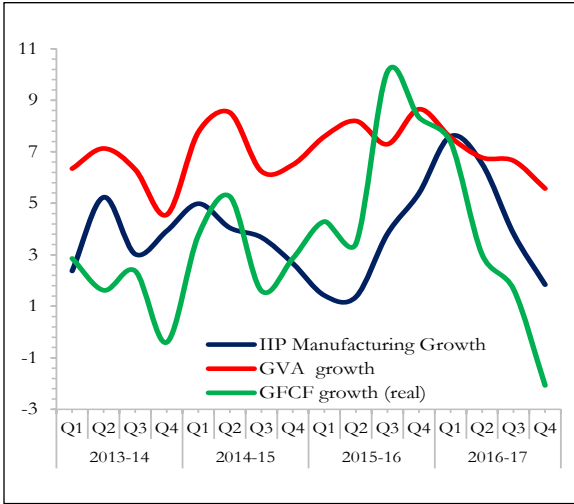
(जीवीए), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी), ऋण, कीमतें, क्षमता उपयोग, निवेश-ये सभी 2016-17 के दौरान आर्थिक गतिविधि में अल्पावधिक अवमंदन की ओर संकेत करते हैं (चित्र 9)। लेकिन फिर भी, इस अवधि में विशेष रूप से फरवरी 2017 से, आस्ति मूल्य बढ़े हैं। उदाहरणार्थ, सरकारी प्रतिभूति से होने वाली आय का 7.12 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटकर 6.5 प्रतिशत तक हो जाना उच्च बांड मूल्यांकन का सूचक है।

1.45 इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि उसी अवधि में, स्टॉक मूल्यों में रिकार्ड स्तर की वृद्धि हुई है, जब सेन्सेक्स 28,743 अंक से बढ़कर 32,020 तक जा पहुंचा जो 11 प्रतिशत का लाभ बैठता है (चित्र 10), यह अमरीकी डालर मूल्य में 15 प्रतिशत के समतुल्य है।

1.46 इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टॉक बाजार का मूल्य-अर्जन (पी/ई) अनुपात मई, 2017 में 23 के स्तर तक पहुंच गया, तथा अनुमान है कि जुलाई मध्य तक यह लगभग 25 तक पहुंच जाएगा। यह 18 की दीर्घावधिक औसत से काफी ज्यादा है और वर्ष 2007 में प्राप्त किए गए अत्यधिक उछाल के स्तरों से ज्यादा दूर नहीं है। वित्तीय साहित्य से यह स्पष्ट है कि असामान्य उच्च पी/ई स्तर बनाए रखने के लिए मुख्य शर्त यह है कि भावी आर्थिक और विशेषकर लाभ वृद्धि तीव्र हो, और/अथवा निवेशक अन्य कम जोखिम वाली आस्तियों (तथाकथित इक्विटी जोखिम प्रीमियम) की तुलना में स्टॉक धारिता हेतु कम प्रीमियम स्वीकार करने हेतु इच्छुक हों। ऐसा न होने पर, पूरे विश्व में औसत प्रत्यावर्तन की तीव्र प्रवृत्ति व्याप्त है जो भारत के संबंध में 2000 के दशक के मध्य में हुई तेजी के बाद की स्थिति से स्पष्ट होती है (चित्र 10)।

1.47 क्या हालिया गिरावट के कारण लाभ और विकास में आया उछाल अस्थायी सिद्ध होगा अथवा आस्ति मूल्यन, दूसरे शब्दों में, तर्कसंगत विश्वास या उल्लास को ठीक स्तर पर ले आएगी? यह अभी देखा जाना बाकी है। ऐतहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अधिक यथार्थपरक मूल्यन की दिशा में माध्य परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर सबसे पहले वैश्विक स्तर पर अत्याधिक नकदी उच्च मूल्यों को प्रेरित कर रही है।

चित्र 9. जीवीए, आईआईपी तथा निर्देश वृद्धि (प्रतिशत)



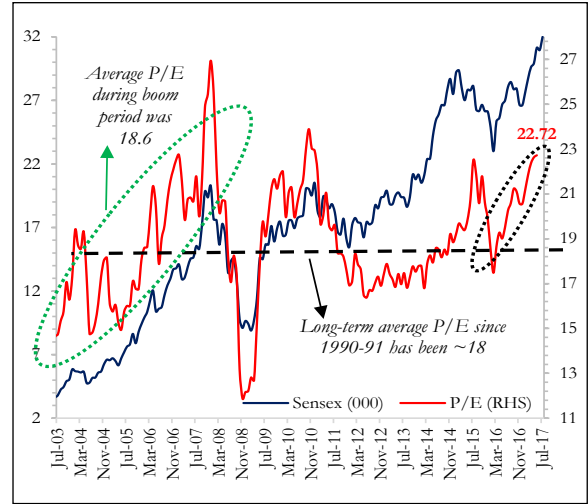
स्रोत: सीएसओ

## V. कृषि ऋण माफी: बृहत-आर्थिक प्रभाव<sup>6</sup>

1.48 हाल ही में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु द्वारा किसी न किसी रूप में कृषि ऋण माफी की घोषणाएं या वादे किए गए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगा दी है जिसमें सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों की बजाय सभी किसानों को ऋण माफी प्रदान किए जाने की बात कही गई है। यह संभावना है कि यह संक्रमण अन्य राज्यों में भी फैल जाएगा। यह स्थिति वर्ष 2007-08 की पूर्ववर्ती घटना के ठीक विपरीत है जब कृषि ऋण माफी भारत व्यापी आधार पर केन्द्र द्वारा दी गई थी।

1.49 कृषि ऋण माफी के समर्थक इस माफी को उन किसानों की मदद करने का माध्यम समझते हैं जो कृषि क्षेत्र पर हो रहे लगातार आघातों से ग्रस्त रहे हैं, दो वर्ष तक अपर्याप्त वर्षा जिसके बाद की कीमतों में बड़ी गिरावट का एक और वर्ष रहा। अन्य के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह इंगित किया है कि इन ऋण माफियों का ऋण अदायगी की संस्कृति पर दीर्घावधिक प्रभाव पड़ेगा और ये नैतिक दृष्टि से भी घातक होंगी: यह ऋण माफी उन लोगों का पक्ष लेती है जिन्होंने उधार लिया है न कि उनका जिन्होंने मितव्ययिता बरती है; यह उनका पक्ष लेती है जिन्होंने उधार लिया है न कि उनका जिन्होंने अपने ऋण चुका

चित्र 10. सेनसेक्स और मूल्य-अर्जन अनुपात (पी/ई)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और बीएसई

दिए हैं; और यह ऋण माफी उनका भी पक्ष लेती है जिन्होंने औपचारिक स्रोतों से उधार लिए हैं बजाय उनका जिन्होंने अनौपचारिक स्रोतों से अक्सर बहुत अधिक ब्याज दरों पर उधार लिए हैं। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि किसानों की मदद करने के लिए अधिक कार्यदक्ष और लक्षित तरीके भी हैं।

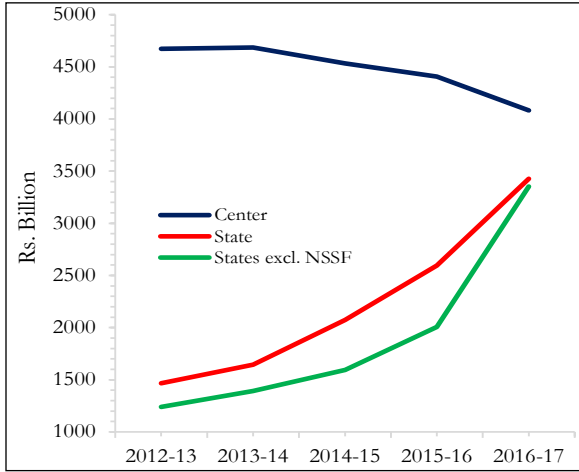
1.50 इस भाग में कृषि ऋण माफी के मापदण्ड संबंधी आयामों का आकलन नहीं किया गया है। बल्कि, इसमें ऐसी अर्थव्यवस्था जो अभी अपने विकास की पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है, के लिए इसके तात्कालिक परिणामों को समझने की दृष्टि से समष्टि आर्थिक विश्लेषण किया गया है। जिस हद तक चक्रीय प्रभाव पर चर्चा की गई है, यह माना गया है कि यह स्फीतिकारी है। परंतु वास्तव में, नीचे किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पकालिक परिणाम काफी अपस्फीतिकारी होने की संभावना है।

### 1. ऋण माफी की संभावित मात्रा

1.51 कृषि ऋण माफी की मांगें ऐसे समय में उभरी हैं जब राज्य के वित्त साधन गड़बड़ा रहे हैं। उदय योजना के कारण राज्य अब अधिक बाजार उधार ले रहे हैं (चित्र 11), यह संभावना है कि यह जल्द ही केन्द्र सरकार के उधारों से ज्यादा हो जाएंगे। परिणामस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों की तुलना में राज्य सरकारों के बांड पर स्प्रेड में पिछले छः महीनों में लगभग 60 आधार बिंदुओं की

<sup>6</sup> कृषि ऋणग्रस्तता संबंधी बुनियादी तथ्य परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।

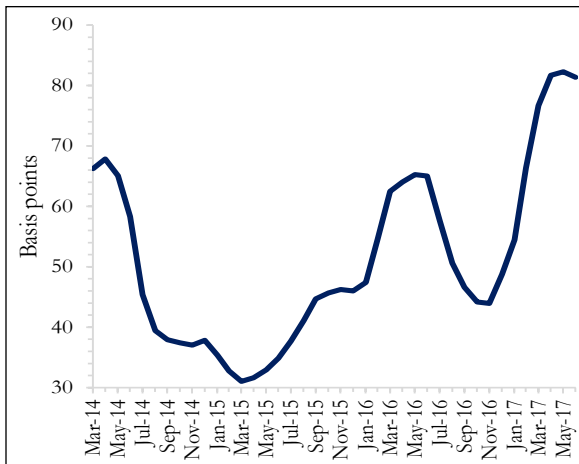
**चित्र 11. निवल बाजार उधार  
( बिलियन रुपये )**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, जे०पी० मॉर्गन

टिप्पणी: एनएसएसएफ का तात्पर्य राष्ट्रीय लघु बचत निधि है जो बाजार-भिन्न उधार को दर्शाता है।

**चित्र 12. राज्य विकास ऋण  
( एसडीएल )-सरकारी प्रतिभूति स्प्रेड ( 5-मास  
चल औसत, आधार बिन्दु )<sup>7</sup>**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और एचएसबीसी

लगातार वृद्धि हुई है (चित्र 12)। इसके बाद, जे०पी० मॉर्गन द्वारा अनुमानित कॉरपोरेट बांड पर स्प्रेड लगभग 40 आधार बिंदु बढ़ा है, जिससे निजी क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय संभवतः कम हो जाएगा।

1.52 समष्टि-आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाने में ऋण माफी की मात्रा के बारे में पूर्वानुमानों की जरूरत होती

है। माफी योजनाओं को लेकर तीन राज्यों ने विशिष्ट घोषणाएं की हैं: उत्तर प्रदेश ने अभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक लाख रुपये तक की माफी की घोषणा की है; पंजाब में यह सीमा छोटे किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की है परंतु इन किसानों को परिभाषित नहीं किया गया और, कर्नाटक ने माफी की धनराशि 50,000 रुपये तक सीमित की है (महाराष्ट्र की माफी शर्तें अभी भी स्पष्ट नहीं हैं)। माफी की घोषणा यह स्पष्ट नहीं करती कि क्या धनराशि परिवारों पर अथवा ऋणों पर लागू होंगी: विशेष बात तो यह है कि एक परिवार के पास एक से अधिक ऋण होंगे।

1.53 यह माना गया है कि ये ऋण माफी पारिवारिक स्तर की बजाय ऋण पर लागू होगी, क्योंकि परिवारों के संबंध में ऋणों को जोड़ना प्रशासनिक दृष्टि से कठिन होगा। यह भी माना गया है कि अन्य राज्य उत्तर प्रदेश के मॉडल का अनुसरण करेंगे। इस आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ऋण माफी की ऊपरी सीमा 2.2 और 2.7 लाख करोड़ रुपये (परिशिष्ट 1, सारणी 1) के बीच होगी। ऋण माफी का राज्यवार आकलन बॉक्स 1 में दिया गया है।<sup>8</sup>

## 2. समष्टि आर्थिक प्रभाव

1.54 अपने नितान्त मूल रूप में, कृषि ऋण-माफी देनदारियों को पूरी तरह से निजी क्षेत्र से हटाकर सरकारी क्षेत्र के तुलनपत्रों में स्थानांतरित कर देती हैं। इसके बाद समग्र मांग पर पड़ने वाला प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि किस क्षेत्र में संपदा से खपत करने की प्रवृत्ति है। वस्तुतः संपदा में से उपभोग करने की प्रवृत्ति राज्यों की नहीं है परंतु दोनों के बीच में संबंध है क्योंकि उनका खर्च उनके राजकोषीय दायित्व विधान (एफआरएल) के लक्ष्यों के संदर्भ में उनकी जरूरत द्वारा प्रभावित होता है। यदि वे ज्यादा ऋण लेते हैं, तो उन्हें बहुत से मामलों में अन्य खर्च कम करने (अथवा कर बढ़ाने) की जरूरत होगी। एक बार यदि खर्चों में परिवर्तन हो जाते हैं, तो इसके दूसरे दौर के प्रभाव होंगे।

1.55 निम्नलिखित विश्लेषण से यह अनुमान लगाया गया है कि उपर्युक्त चर्चा के अनुसार, कृषि ऋण माफी पूरे देश में व्याप्त हो जाएगी। उस मामले में, कुल ऋण

<sup>7</sup> औसत एसडीएल आय उन सभी राज्यों की आय का मासिक औसत है जिन्होंने उस माह में राज्य पत्र जारी किया है।

<sup>8</sup> यदि केवल पांच राज्य भी जिन्होंने घोषणा की है, इसे कार्यान्वित कर देते हैं, तो अनुमानित प्रभाव 1-1.25 लाख करोड़ रुपये होगा।

### बॉक्स 1. ऋण माफी का राज्यवार राजकोषीय आकलन

कृषि ऋण माफी को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों की राजकोषीय सामर्थ्य क्या है? इसका आकलन करने में माफी की संभावित लागत का अनुमान लगाने, राज्यों की एफआरएल सीमाओं की तुलना में उनकी राजकोषीय सीमा की मात्रा निर्धारण करने तथा इन दोनों की तुलना करने की जरूरत है। नीचे सारणी में किए गए विश्लेषण दर्शाये गये हैं।

राज्यों को राजकोषीय गुंजाइश की सीमा के अनुसार दर्जा दिया जाता है। अधिकतर राज्यों के लिए राजकोषीय सीमा जीएसडीपी का 3 प्रतिशत है। तथापि, छः राज्यों (ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और बिहार) की सीमाएं उच्च हैं और जीएसडीपी का 3.5 प्रतिशत है क्योंकि उनकी समग्र राजकोषीय स्थितियां मजबूत हैं, जैसाकि चौदहवें वित्त आयोग के मानदंडों द्वारा माना गया है।

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के साथ सीमाओं की तुलना करने पर यह पाया गया है कि केवल सात राज्यों की राजकोषीय गुंजाइश जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत से अधिक है। रुपये के संदर्भ में सर्वाधिक गुंजाइश वाले राज्य हैं—महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तुलनात्मक रूप से, झारखंड के पास भी पर्याप्त गुंजाइश है जो जीएसडीपी का 0.7 प्रतिशत है। वे राज्य जिनमें अतिरिक्त घाटा उठाने की क्षमता नहीं है, उनमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है।

#### कृषि ऋण माफी के लिए राज्य-विशिष्ट राजकोषीय गुंजाइश

राज्य	चालू	2017-18 ( बजट	राजकोषीय	राजकोषीय	2017-18	राजकोषीय	राजकोषीय
	जीएसडीपी बाजार मूल्य (2017-18)	अनुमान ) में उदय के बिना राजकोषीय घाटा	सीमा चौदहवें वित्त आयोग के बाद	गुंजाइश	( बजट अनुमान ) में उदय के बिना राजकोषीय घाटा	सीमा चौदहवें वित्त आयोग के बाद	गुंजाइश
	लाख करोड़	हजार करोड़	रूपए में		जीएसडीपी का प्रतिशत		
आंध्र प्रदेश	7.7	23.1	23.1	0.0	3.0	3.0	0.0
उत्तर प्रदेश	14.2	42.6	42.6	0.0	3.0	3.0	0.0
राजस्थान	8.3	24.8	24.8	0.0	3.0	3.0	0.0
केरल	7.5	25.8	22.4	0.0	3.4	3.0	-0.4
हिमाचल प्रदेश	1.4	4.9	4.2	0.0	3.5	3.0	-0.5
ओडिशा	4.1	14.4	14.4	0.0	3.5	3.5	0.0
छत्तीसगढ़	2.8	9.7	9.7	0.0	3.5	3.5	0.0
महाराष्ट्र	25.4	38.8	76.2	37.4	1.5	3.0	1.5
पश्चिम बंगाल	10.8	19.4	32.4	13.1	1.8	3.0	1.2
गुजरात	12.8	23.2	38.3	15.1	1.8	3.0	1.2
झारखंड	3.0	6.9	9.1	2.2	2.3	3.0	0.7
हरियाणा	6.2	16.2	18.6	2.4	2.6	3.0	0.4
कर्नाटक	12.8	33.4	44.8	11.5	2.6	3.5	0.9
तमिलनाडु	15.0	42.0	45.1	3.2	2.8	3.0	0.2
उत्तराखंड	2.3	6.6	6.8	0.2	2.9	3.0	0.1
पंजाब	5.0	14.6	15.1	0.5	2.9	3.0	0.1
बिहार	6.3	18.1	22.1	4.0	2.9	3.5	0.6
मध्य प्रदेश	7.4	21.1	25.7	4.7	2.9	3.5	0.6
तेलंगाना	7.6	26.1	26.6	0.5	3.5	3.5	0.0
<b>कुल</b>	<b>160.6</b>	<b>411.6</b>	<b>502.2</b>	<b>94.6</b>	<b>2.6</b>	<b>3.1</b>	<b>0.6</b>

टिप्पणी: राजकोषीय सीमा 14वें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिशों के आधार पर परिकल्पित की गई है। चालू और पिछले वर्षों में अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश के उपयोग को लागू किए जाने की आवश्यक शर्त शून्य राजस्व घाटा है। इसके बाद, की जीएसडीपी का 0.25 प्रतिशत के बराबर में राजकोषीय गुंजाइश तभी उपलब्ध है, यदि राजस्व प्राप्ति और ब्याज भुगतान का अनुपात 10 प्रतिशत से कम अथवा इसके बराबर हो; और जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.25 प्रतिशत, यदि ऋण और जीडीपी अनुपात जीएसडीपी के 25 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के राजकोषीय घाटे के आंकड़े 2016-17 (ब०अ०) से संबंधित हैं।



माफी 2.7 लाख करोड़ हो सकती है। साथ ही, यह मान लिया गया है कि जैसाकि वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा है कि केन्द्र इन ऋण माफियों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी पर ही ऋण माफी का वित्तपोषण करना होगा।

1.56 ऋण माफी के कुल मांग पर चार प्रभाव होंगे:

- निजी क्षेत्र के निवल धन में वृद्धि के माध्यम से निजी उपभोग प्रभाव
- सरकारी व्यय/करों में बदलाव के कारण सरकारी क्षेत्र प्रभाव
- राज्य सरकारों द्वारा अधिक उधार लिए जाने से निजी क्षेत्र को ऋण बाजार से बाहर कर देने का प्रभाव
- बैंकों की अनर्जक आस्तियों में कमी के कारण उनकी अधिक ऋण प्रदान कर पाने की क्षमता का प्रभाव

1.57 आइए, प्रत्येक प्रभाव पर विचार करें।

1.58 *निजी उपभोग प्रभाव:* ऋण माफी देने से कृषि परिवारों के निवल धन में वृद्धि होगी। धन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, यह अनुमान लगाया गया है कि निवल आय माफ किए गये ऋण की राशि जितनी बढ़ेगी (जबकि वास्तव में तो इस वर्ष की निर्वृत्य आय में सिर्फ माफ किए गए ऋण शोधन जितनी वृद्धि होती है)। कृषि परिवारों पर समस्तरीय आंकड़ों का प्रयोग करके हम उपभोग की (अस्थायी) आय लोच का अनुमान 0.25 आकलित कर पा रहे हैं।<sup>9</sup> चूंकि ऋण माफी से कुल आय में 28 प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है, अतः उपभोग में 7 प्रतिशत अथवा लगभग 55,000 करोड़ रु० की वृद्धि अनुमानित है। यह अनुमानित उपभोग प्रभाव कदाचित उच्चतर है, क्योंकि विश्व बैंक के 2008-09 के “कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना” पर अध्ययन में यह पाया गया है कि ऋण माफी के पश्चात् उपभोग नहीं बढ़ पाए थे।<sup>10</sup>

<sup>9</sup> यह कम संख्या मालूम पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति आमतौर पर उच्च है। परंतु व्यावहारिक अर्थशास्त्र बताता है कि आय में वास्तविक वृद्धि पर प्रतिक्रिया छोड़े गए व्ययों पर आधारित अनुमानित वृद्धि से बहुत भिन्न होती है।

<sup>10</sup> Giné, X and M. Kanz, 2014, “The Economic Effects of a Borrower Bailout Evidence from an Emerging Market,” World Bank Policy Research Paper, WPS7109.

1.59 सरकारी क्षेत्र प्रभाव: यह प्रभाव वित्तीय स्थिति की उस सीमा पर निर्भर करेगा जो राज्य सरकारों को अपनी संबंधित एफआरएल के अंतर्गत उपलब्ध हो। बॉक्स 2 में सरकारी क्षेत्र प्रभाव की विधि का वर्णन किया गया है। प्रमुख सहजबोध यह है कि ऋण माफी में वे खर्च शामिल होते हैं जोकि सकल मांग में नहीं जुड़ पाते (क्योंकि ये राज्यों के तुलन पत्र को देनदारियों का अन्तरण होते हैं) परंतु एफआरएल लक्ष्यों को पाने के लिए की गई कार्रवाई (अधिक कर और/अथवा कम व्यय) मांग को कम करेगी। यह अनुमानित है कि अच्छी राजकोषीय गुंजाइश वाले राज्यों के लिए ऋण माफी अतिरिक्त ब्याज लागत के माध्यम से लगभग 6,350 करोड़ रु० की राशियां मांग में जोड़ देगी। उन राज्यों के लिए जिनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं हैं, ऋण माफी मांग में लगभग 1.9 लाख करोड़ रु० की कमी कर सकती है। राज्यवार दोनों प्रभावों का समंजन कर प्राप्त निवल प्रभाव कुल मांग में 1.9 लाख करोड़ रु० के लगभग कमी कर सकते हैं।

1.60 अब दूसरे चरण के प्रभाव पर ध्यान दें:

1.61 निजी क्षेत्र को साख बाजार से बाहर धकेलने का प्रभाव: राजकोषीय सीमा वाले राज्यों द्वारा ऋण माफी का परिणाम उच्च उधारी में होगा। यह फर्मों को अपने निजी खर्चों को घटाने को विवश कर सकता है। जे०पी० मॉर्गन का विश्लेषण बताता है कि कारपोरेट बांड पर फैलाव लगभग 40 आधार बिन्दु बढ़ गया है।

1.62 अधिक साख सुलभ होने का प्रभाव: गैर-निष्पादक कृषि ऋण तुलन पत्रों से हटने से बैंकों के तुलन पत्र इस सीमा तक सुधर जाएंगे कि वे निजी क्षेत्र को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे जिससे फर्मों के खर्च में बड़ी वृद्धि होगी। विश्व बैंक के अध्ययन में यह पाया गया कि 2008-09 ऋण माफी करने वाले राज्यों में उधार लेने में वृद्धि हुई थी, हालांकि जिन जिलों में छूट की योजना का खूब प्रचार किया गया उन जिलों में ऐसी बात नहीं देखी गयी।

1.63 यह अनुमानित है कि ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को लगभग निरसित कर देंगे।



## बॉक्स 2. ऋण माफी का समष्टि अर्थशास्त्रीय लेखांकन

ऋण माफी के दो ध्रुवीय मामलों पर विचार करें जहां राज्यों की राजकोषीय स्थिति ठीक नहीं है और जहां राजकोषीय स्थिति कुछ ठीक है। दोनों मामलों में:

$$FD = E - R \quad (1)$$

जहां एफडी राजकोषीय घाटा है,  $\pi$  और  $\tau$  क्रमशः इसके कुल व्यय तथा ऋण-भिनन राजस्व हैं। मान लीजिए कि राज्य  $\pi$  की सीमा तक ऋण माफी प्रदान करते हैं।

$$\text{अब } FD = E - R + LW \quad (2)$$

यदि ऋण माफी वाले राज्य पहले से ही अपनी घाटों की सीमा पर हों तब अपरिवर्तित FD के लिए उच्च LW को समायोजित करने के लिए समीकरण 2 में E को कम करने (व्यय कम करके) अथवा (कर बढ़ाकर) R को बढ़ाने की आवश्यकता होगी।

मुख्य बात यही है जबकि मापा हुआ वित्तीय घाटा परिवर्तित न हो सके तो कुल मांग में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में LW सिर्फ आस्तियों का एक लेनदेन है (समष्टि-लेखांकन शब्दावली में “लाइन से नीचे”) जिसमें राज्य बैंकों को प्रभावपूर्ण तरीके से किसानों की तरफ से भुगतान करता है। उसी समय, R में वृद्धि अथवा E में कमी एफआरएल लक्ष्य के कारण आवश्यक है, जिसका वास्तविक समष्टि स्तरीय प्रभाव होगा, जो कुल मांग को कम करेगा। अतः इस मामले में ऋण माफी प्रदान करना कुल सरकारी क्षेत्र की मांग में संभवतः बड़ी राशि की कमी करेगा।

अब दूसरे मामले में, यदि राज्यों की स्थिति ऋण माफी से पहले अच्छी हो तो तब LW में वृद्धि से R अथवा E में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु यहां भी अधिक ऋण लेने के कारण अतिरिक्त ब्याज लागत का भार बजट पर पड़ेगा। अतः इस स्थिति में समष्टि प्रभाव गौण रह जाएगा। इसमें LW की वृद्धि तो प्रभावहीन रहती है, किन्तु अतिरिक्त ऋण के कारण अतिरिक्त ब्याज लागत का भार तो उठाना ही पड़ेगा।

1.64 कुल प्रभाव: इन प्रभावों को जोड़कर सकल मांग में 1.1 लाख करोड़ रु० की कमी की आशंका है।<sup>11</sup> दूसरे शब्दों में, ऋण माफी जीडीपी के 0.7 प्रतिशत जितनी समग्र मांग को कम कर सकती है जो अभी तक पूरी गति नहीं पकड़ पाई जो अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण अपस्फीतिकारी झटका दे सकता है। किन्तु ध्यान रहे, यह एक उच्च अनुमान है। वास्तविक प्रभाव राज्यों की उस संख्या पर निर्भर करेगा जो वास्तव में छूट प्रदान करने का निर्णय लेते हैं और वे इसे समय के अनुसार कैसे वितरित करते हैं।

## VI. प्रचुरता के समय में कृषि संबंधी तनाव?

1.65 ऋण माफी के लिए अचानक मांग की क्या वजह है? क्या यह संभव है कि कृषक तनाव वस्तुतः तब बढ़ा है जब इस वर्ष मौसमी परिस्थितियां तो बहुत ही अच्छी रही हैं? आखिरकार, आय तथा मौसमी दशाएं सामान्यतः अधिक सहसंबंधित होती हैं। जब 2006-12 के दौरान मौसम सही था और अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ रही थी, तब कृषि की आय भी तेजी से बढ़ी। फिर जब वर्षा बहुत कम हुई तो परिणामस्वरूप फसलें कम हुईं और कठिनाई

बढ़ी। लेकिन पिछले दो वर्षों में पर्याप्त वर्षा तथा अच्छी फसल हुई है, तो हैरानी इस बात की है कि प्रचुरता के इस समय में तनाव क्यों उत्पन्न हो रहा है।

1.66 कृषि तनाव को तटस्थ भाव से आंकना कठिन है। कई राज्यों में बेचैनी और ऋण राहत के लिए मांगों का अविर्भाव आसानी से देखा जा सकता है। परंतु इनके राजनीतिक और आर्थिक उद्गमों को सुलझाना कठिन है। उदाहरण के लिए, ऋण माफी के लिए व्यापक मांग उत्तर प्रदेश की ऋण माफी के प्रदर्शन प्रभाव को अधिक प्रतिबिम्बित कर रही है।

1.67 फिर भी, इस तनाव के लिए कम कीमतों तथा कम कृषि आय किसी सीमा तक आंशिक कारण मालूम होते हैं।<sup>12</sup>

1.68 इस स्थिति का आकलन करने के लिए, कृषि मंत्रालय के एगमार्कनेट डेटाबेस का उपयोग किया गया। इसमें कृषि उत्पादों की प्रमुख मंडियों में आवक तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कीमत के दैनिक आंकड़े होते हैं। बहुत सी वस्तुएं, जैसे गेहूं, अरहर, मूंग, टमाटर, आलू और प्याज के लिए कीमत, मात्रा, आय के लिए

<sup>11</sup> राज्य जिन्होंने ऋण माफी की पहले ही घोषणा की है, उनके लिए यह प्रभाव लगभग 57,900 करोड़ रु० अनुमानित है।

<sup>12</sup> लागतों पर विस्तृत आंकड़ों के अभाव में कृषि आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता; इसके बजाय मात्रा और कीमत के गुणनफल द्वारा कृषि आय को मापा जा रहा है।

अनुमान प्रदान किये जाते हैं और जहां प्रासंगिक हो (गेहूं और दालों), फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर बेची गई फसल का प्रतिशत भी मुहैया कराया जाता है। डाटाबेस में अलग-अलग राज्यों की सूचना के साथ अखिल भारतीय आधार पर सूचना भी होती है। सभी गणनाएं कृषि वर्ष (जुलाई-जून)<sup>13</sup> के लिए हैं।

1.69 कुछ वृहत् पैटर्न उभर रहे हैं। आर्थिक तनाव-जैसा वास्तविक आय द्वारा मापा गया ग्रामीण (सीपीआई) द्वारा अपस्फीत कीमत और बाजार में आने वाली मात्रा के गुणनफल द्वारा मापित आर्थिक तनाव तो एक व्यापक प्रक्रिया नहीं है।<sup>14</sup> उदाहरण के लिए, यह गेहूं और चना को प्रभावित नहीं कर रही, जहां बाजार मात्रा और कीमतें बढ़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि हुई है।

1.70 परंतु दाल और आलू जैसी कुछ सब्जियों (चित्र-13) में वास्तविक कृषि आय में गिरावट होती प्रतीत होती है। जून 2017 में समाप्त हो रहे कृषि वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा वास्तविक आय में मूंग के मामले में अधिकतम (30 प्रतिशत) तथा आलू के मामले में सबसे कम (4 प्रतिशत) के साथ अरहर और मूंग के लिए क्रमशः लगभग 10 और 28 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई। तथापि प्याज और टमाटर की कीमतों में हाल ही में बढ़ोतरी शुरू हो गई है।

1.71 कुछ रुचिकर प्रादेशिक भिन्नताएं भी रही हैं। उत्तर प्रदेश ने गेहूं और आलू सहित अधिकतर फसलों में समुचित रूप से अच्छा काम किया है। गेहूं के मामले में, गेहूं की खरीद में काफी वृद्धि हुई थी जो एमएसपी से नीचे कीमत पर बिक्री की मात्रा में हुई गिरावट के रूप में प्रतिबिंबित हुई। इसकी तुलना में, मध्य प्रदेश में जिसमें हाल ही में गेहूं पर विशेष आग्रह रहा है, एमएसपी से नीचे की कीमत पर बिक्री की मात्रा में वृद्धि देखी गई। दालों में पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों में बड़ी कमी देखी गई, विशेषकर मूंग में, यद्यपि कुछ राज्यों (मूंग में

राजस्थान और अरहर में कर्नाटक और मध्य प्रदेश) में तेजी से कीमतें गिरी हैं।

1.72 स्पष्ट रूप से, आपूर्ति में वृद्धि के कारण कीमतों में बड़ी गिरावट हुई। पहली यह है कि इसने कीमतों को इतना अधिक क्यों कम कर दिया कि इससे कृषि आगम पर इतना बुरा असर पड़ा है। आखिरकार वर्ष 2014 में, अरहर, आलू तथा प्याज सहित अधिकतर फसलों में, बिना आगम गिरावट के भी, उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। यह वर्ष भी कीमत में हुई गिरावट की सीमा में असामान्य प्रतीत हो रहा मालूम होता है।

1.73 इसकी दो संभावित व्याख्याएं दिखाई पड़ती हैं: पहली, किसानों के लिए बिक्री केन्द्र थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं पर लगाई गई भंडारण सीमा के कारण कम हो गए और निर्यात पर प्रतिबंध लगाए गए जबकि कुछ जिलों के संबंध में आयातों में उदारता बरती गई। साक्ष्य संकेत एक ओर चने और दूसरी ओर अरहर तथा मूंग के अनुभवों की परस्पर तुलना करने पर मिलते हैं। चने पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के चलते किसानों को प्राप्त बाजार कीमतों को बढ़ाने में मदद मिली। दूसरा, पिछले वर्ष की तुलना में कमजोर मांग कीमतों पर दबाव डाल सकी थी।

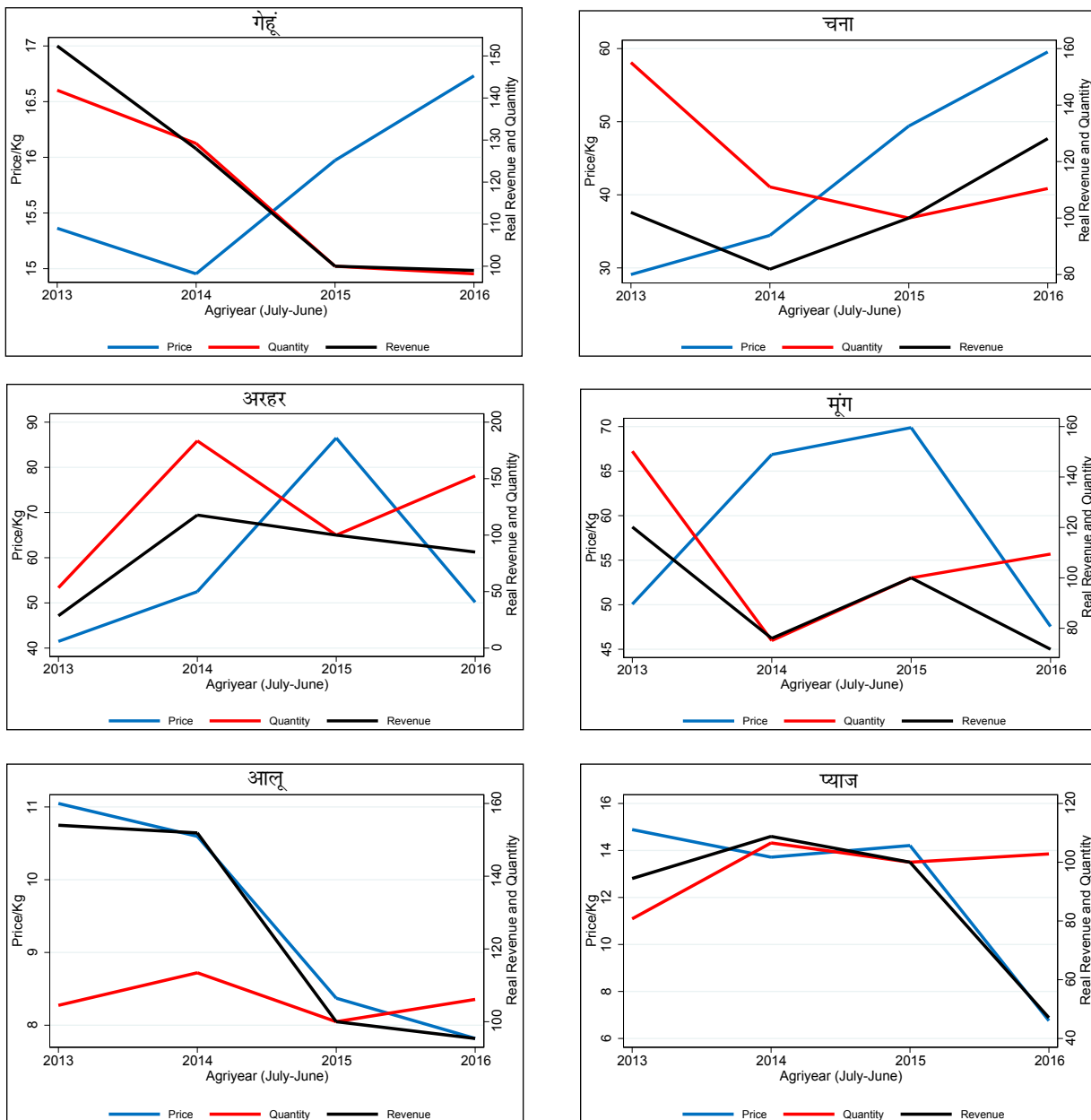
1.74 कुछ प्रेक्षकों की उम्मीदों के विपरीत, विमुद्रीकरण ने रबी फसल की आपूर्ति में कमी नहीं की। नकदी की कमी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुस्पष्ट देखी गई तथा वे ऋण की कमी के चलते और बढ़े जब, ऋण वृद्धि सितंबर के 16 प्रतिशत से धीमी होती इस वर्ष की पहली तिमाही और मई के अंत तक 8-9 प्रतिशत तक हो गई। (चित्र 14 में काली रेखा)।

1.75 नकद और ऋण की इस कमी के कारण कृषित क्षेत्रफल और उर्वरक का उपयोग कम हो सकता था। तब भी, पिछले वर्ष रबी रोपण-जो कि विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान हुआ था तथा उत्पादन सही सलामत

<sup>13</sup> आवक पर आंकड़ों में समस्त उत्पादन पर ध्यान नहीं रखा गया है। एगमार्क विनियमित बाजार का 48.7 प्रतिशत तथा अविनियमित बाजार को कवर करता है। तथापि, राज्य और अखिल भारतीय स्तर दोनों पर कवरेज प्रातनिधिक है। हमारा अनुमान समय-समय पर राज्यों को सामान्य प्रतिदर्श पर आधारित है।

<sup>14</sup> यदि यहां कोई धन संबंधी भ्रान्ति है तो निगरानी करने के लिए मौद्रिक आय सही पैमाना होगा। चूंकि ग्रामीण सीपीआई मुद्रास्फीति 2015-16 की तुलना में 2016-17 से कम थी, वास्तविक आगमों में गिरावट मौद्रिक आगम में बड़ी गिरावट का संकेत करेगी।

चित्र 13. चयनित कृषि वस्तुएं: वास्तविक आय, मात्रा और कीमतें



स्रोत: एगमार्क नेट और समीक्षा अनुमान

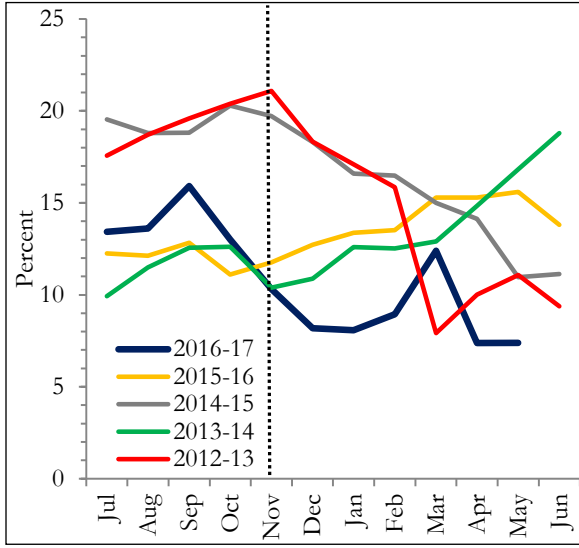
टिप्पणी: कृषि वर्ष 2016 का अर्थ है 2016-17 और अन्य वर्षों के संबंध में भी इसी तरह है। कीमतें भारित औसत हैं। वास्तविक आगम तथा मात्रा कृषि आधार वर्ष 2015-16=100 के साथ सूचीबद्ध है।

रहा था (बोये गये क्षेत्र में 5.7% तथा उत्पादन में 7% की वृद्धि)।

1.76 अंततः, यहां कुछ व्यवहारवादी घटक भी हो सकते हैं। पिछले वर्ष दालों के रोपण में वृद्धि उच्च बाजार कीमतों के साथ-साथ सरकार द्वारा अधिक खरीदी तथा एमएसपी में बड़ी वृद्धि के वादे, दोनों की प्रतिक्रिया

थी। परंतु विपणन के समय कीमतें उन पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी कम रही। खरीदी में रिकार्ड वृद्धि के बावजूद (खरीफ दालों की खरीद 2015-16 में नगण्य स्तर से 2016-17 पर बढ़कर 1.5 मिलियन टन हो गई), कुछ दालों की काफी बिक्री न्यूनतम समर्थन कीमत से कम पर हुई। इस तरह, कृषि तनाव इसलिए

**चित्र 14. ऋण वृद्धि (%)—कृषि  
(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक तथा समीक्षा परिकलन

रहा होगा क्योंकि प्राप्त कीमतें पिछले वर्ष की अपेक्षा कम तथा अधिकांशतः एमएसपी कीमतों की अपेक्षा भी कम रही थी।

### VII. विमुद्रीकरण के दीर्घावधिक लाभ और अल्पावधिक दुष्प्रभाव: अद्यतन स्थिति

1.77 2016-17 की आर्थिक समीक्षा खंड-I में विमुद्रीकरण के संभाव्य परिणामों पर चर्चा की गई थी जो अधिकांशतः सैद्धांतिक थी, क्योंकि उस समय तक उपलब्ध आंकड़े सीमित थे। इसके छह महीने बाद, इस चर्चा में जोड़ने के लिए और अधिक आंकड़े उपलब्ध हैं। यह चर्चा कुछ संकेतकों के आस-पास घूमती है जोकि खंड I में रेखांकित किए गए थे।

#### 1 नकद और डिजीटलीकरण

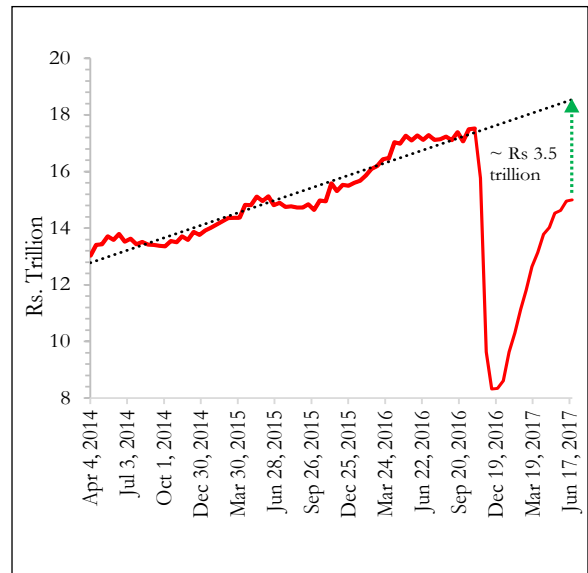
1.78 नकद के उपयोग में कमी तथा डिजीटल माध्यमों से भुगतान के उपयोग में वृद्धि विमुद्रीकरण के मुख्य उद्देश्य थे। इसके बाद प्रगति क्या रही?

1.79 जैसा कि आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड-I में दर्शाया गया है, भारत तुलनीय देशों की अपेक्षा नकद पर बहुत अधिक निर्भर था जो लगभग 12 प्रतिशत उच्च नकद-जीडीपी अनुपात प्रदर्शित करता था तथा समय-समय पर नकद जीडीपी अनुपात बढ़ रहा था

(चित्र 2 और चित्र 3, आर्थिक समीक्षा 2016-17 खंड I के अध्याय 3 में)। विमुद्रीकरण के लागू होने के बाद से नौ महीने हो रहे हैं। यह मानते हुए और यह एक महत्वपूर्ण अनुमान है कि पुनः मुद्रीकरण पूरी तरह से हो गया है और कि अब नकद की आपूर्ति मांग को पूरी तरह से प्रदर्शित करती है, तब आज के नकद के स्तर की विमुद्रीकरण के पूर्व के नकद स्तर से तुलना की जा सकती है।

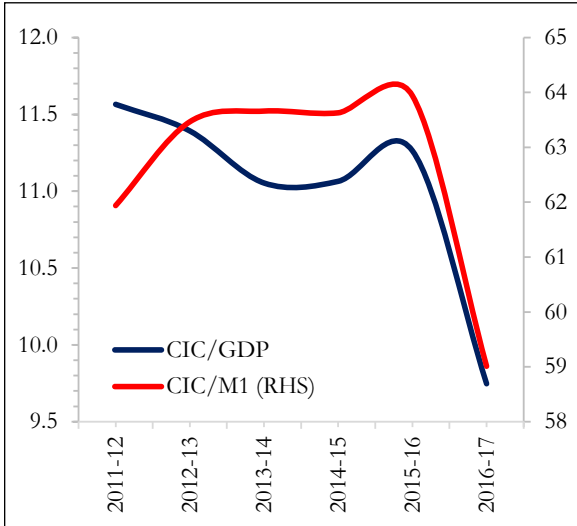
1.80 चित्र 15 में 2014 से नकद के स्तर की रूपरेखा दी गई है तथा प्रवृत्ति रेखा भी दर्शाई गई है और यह भी इंगित किया गया है कि विमुद्रीकरण की अनुपस्थिति में नकद कहां रहा होगा (विमुद्रीकरण के दिन प्रचलित स्तर के साथ आज के स्तर की तुलना करना सटीक नहीं है)। इन स्तरों, और जीडीपी के हिस्से के रूप में तथा धन के संदर्भ में, नकद के प्रयोग में तीव्र और संतुलन संबंधी गिरावट हुई है: जुलाई की स्थिति के अनुसार नकद का स्तर, विमुद्रीकरण से पूर्व के रूझानों से लगभग 3.5 लाख करोड़ रु. (20%) कम है जो खण्ड I में प्रस्तुत परिकलनों के अनुरूप है। नकद रखने में इस कमी को चित्र 16 में दर्शाया गया है, जिसमें नकद को जीडीपी तथा धन के हिस्से (एम1)के रूप में बताया गया है। पूर्वोक्त जीडीपी के 11.3 प्रतिशत के स्तर से लगभग

**चित्र 15. विमुद्रीकरण और नकदी धारिता  
(ट्रिलियन रु० में)**



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक और समीक्षा परिकलन

**चित्र 16. जीडीपी और एम1 तथा परिचालन में करेंसी के अनुपात ( प्रतिशत )**



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक और समीक्षा परिकलन

1.6 प्रतिशत बिन्दु कम होकर 9.7 प्रतिशत तथा उत्तरोक्त 5 प्रतिशत बिन्दु गिर गया।

1.81 निस्सन्देह, एक अंतिम निर्णय तभी सुनाया किया जा सकता है, यदि जीडीपी के सापेक्ष में नकदी के वर्तमान स्तर इस अवधि में बने रहते हैं, लेकिन मालूम होता है कि नकद पर निर्भरता तेजी से गिर रही है। यह गिरावट बताती है कि नकद रखने का बहुत अधिक भाग बचत के लिए उपयोग किया गया जो कि अब बैंकिंग तंत्र में हस्तांतरित हो गया है। इसके अतिरिक्त, विमुद्रीकरण के पश्चात नये प्रवर्तन तथा अनुपालन व्यवस्था तथा बढ़े हुए डिजीटलीकरण ने लेनदेन के लिए नकद के उपयोग को कम किया है।

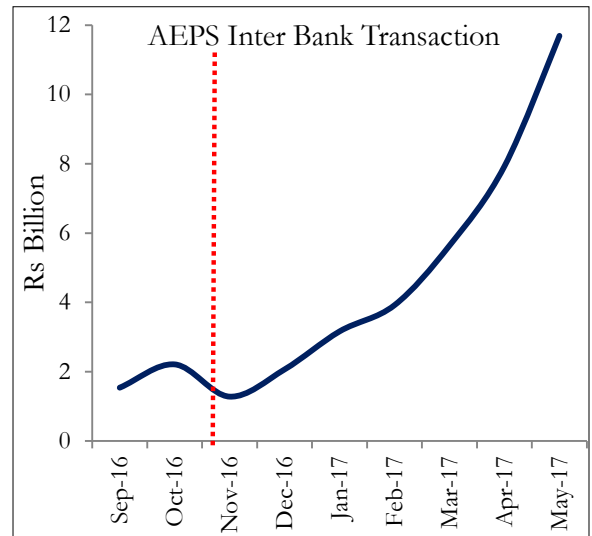
1.82 डिजीटलीकरण के बारे में क्या कहा जा सकता है? डिजीटलीकरण समाज के तीन क्षेत्रों पर वृहत प्रभाव डाल सकता है: गरीब जो कि डिजीटल अर्थव्यवस्था से बाहर हैं; कम समृद्ध जो डिजीटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं और जिनके पास जन धन खाते तथा रुपये कार्ड है तथा अमीर जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए पूरी तरह से डिजीटल अर्थव्यवस्था से जुड़े चुके हैं। विभिन्न संकेतक इन वर्गों पर पड़ने वाले

प्रभाव बताते हैं; “डिजीटलीकरण से बाहर” के वर्ग के लिए आधार समर्थित भुगतान तंत्र (ईपीएस): मध्यवर्ती वर्गों के लिए रुपये कार्ड; तथा डिजीटलीकरण से जुड़े हुए लोगों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड। ये आंकड़े चित्र 17-20 में प्रस्तुत किए गए हैं।

1.83 यह स्पष्ट है कि सभी श्रेणियों में डिजीटलीकरण में काफी वृद्धि हुई है। यहां तक कि कुछ मामलों में विमुद्रीकरण के तुरन्त बाद के उछाल में कमी आने के बावजूद, डिजीटलीकरण का स्तर और इसकी गति विमुद्रीकरण के पहले की तुलना में अभी भी काफी तेज है। यह बात बड़े ग्राहकों वाली श्रेणी के लिए भी सच है जिनके लेनदेनों का चित्र 20 में उल्लेख किया गया है।<sup>15</sup>

1.84 आशा थी कि विमुद्रीकरण से भवन सम्पदा में काला धन कम होगा, जो स्थावर सम्पदा की घटी हुई कीमत में परिलक्षित होगा (चित्र 21 जो भारत के सात प्रमुख शहरों में भारित औसत कीमतों को दर्शाता है)। विमुद्रीकरण के पहले भी, मकान मुद्रास्फीति में गिरावट आई थी और विमुद्रीकरण के बाद कीमत में और अधिक गिरावट हुई है। तब से इस गिरावट में उलटफेर हुआ है

**चित्र 17. “डिजीटल तंत्र के बाहर रहे” लोगों के लिए ईपीएस डिजीटल लेनदेन ( बिलियन रु. में )**

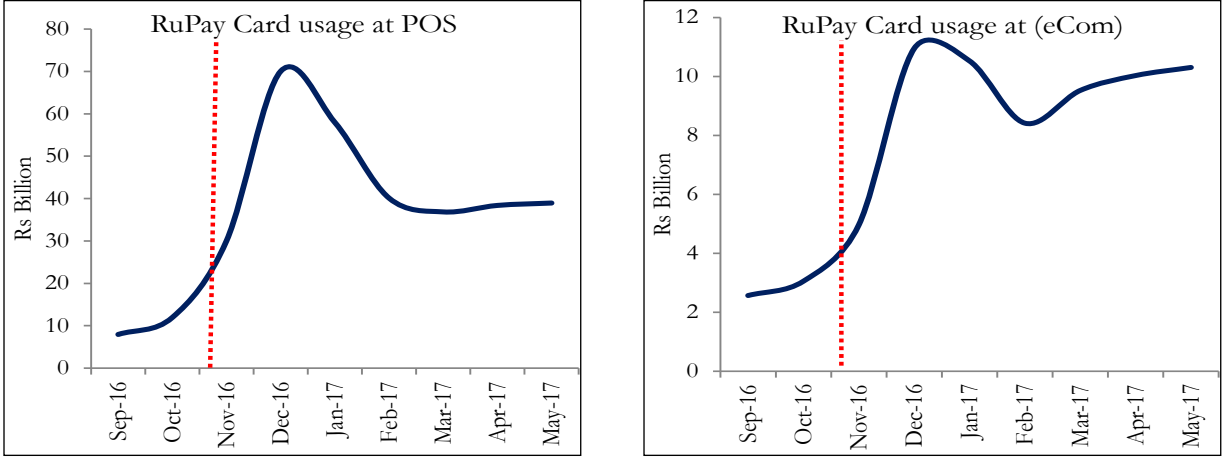


स्रोत: एनपीसीआई

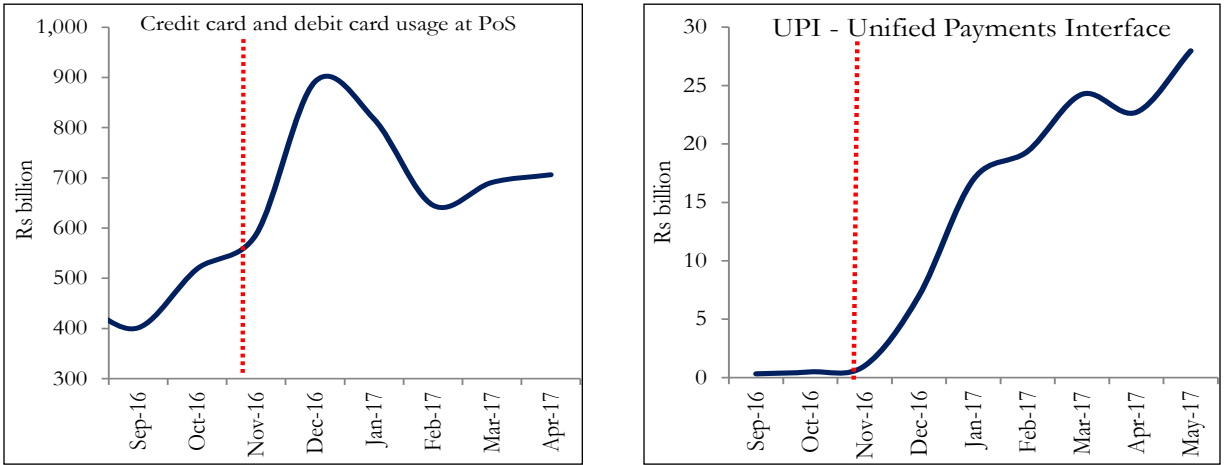
टिप्पणी: ईपीएस-आधार समर्थित भुगतान तंत्र

<sup>15</sup> डिजीटल लेन देन की संख्या पर आधारित आंकड़े (उनके मूल्य के विपरीत) चित्र 17-20 के अनुसार ही छवि दर्शाते हैं।

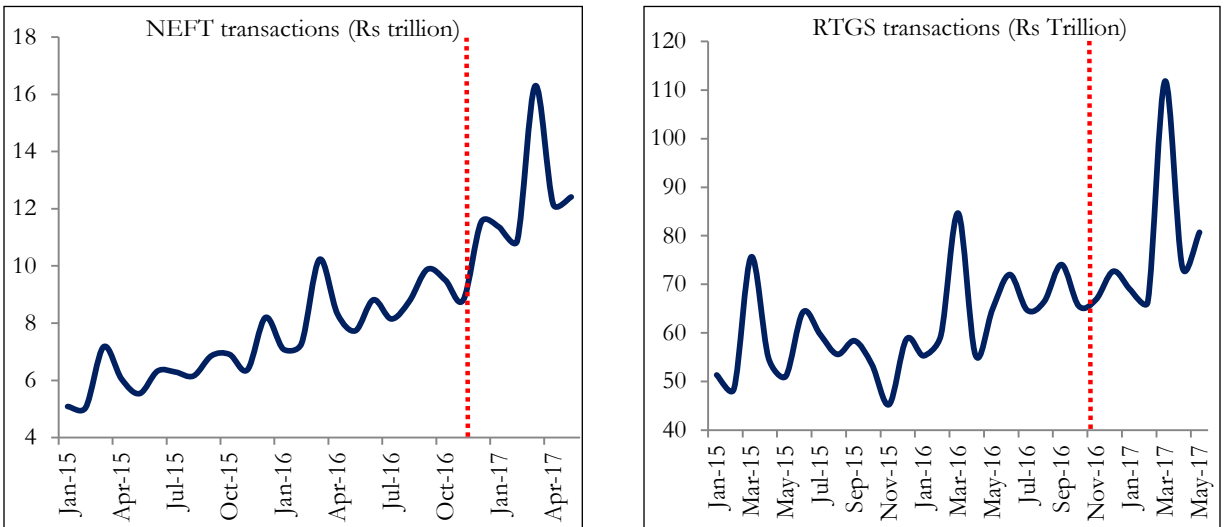
चित्र 18. कम अमीर उपभोक्ता के डिजीटल लेनदेन ( बिलियन रु में )



चित्र 19. अमीर उपभोक्ता के डिजीटल लेनदेन ( बिलियन रु में )



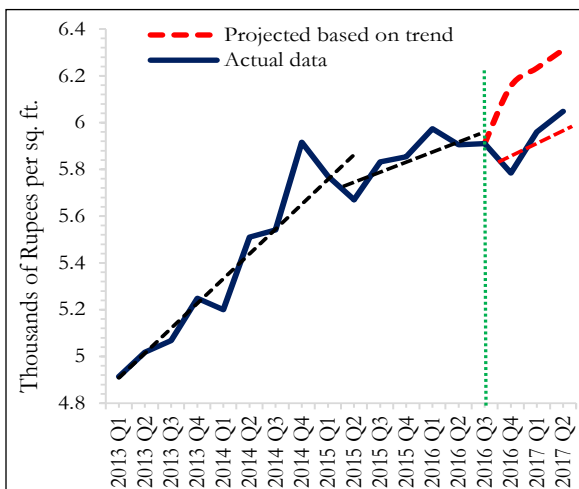
चित्र 20. बड़े उपभोक्ताओं के डिजीटल लेनदेन ( ट्रिलियन रु में )



स्रोत: एनपीसीआई

टिप्पणी: एनईएफटी-नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फण्ड्स ट्रांसफर, आरटीजीएस-रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, भीम-भारत इंटरफेस फॉर मनी

चित्र 21. प्रमुख भारतीय शहरों में भवन सम्पदा की कीमतें<sup>16</sup> ( मौसम के अनुसार समायोजित )



स्रोत: नाइट फ्रेंक

और ऐसा लगता है कि कीमतें दोबारा बढ़ रही हैं। यह देखना बाकी है कि क्या विमुद्रीकरण का आवास बाजार में स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

## 2. आय कर की अनुपालना

1.85 क्या विमुद्रीकरण का सांकेतिक प्रभाव—नामत: 2017-18 के केन्द्रीय बजट में कर का अनुपालन न करने वालों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जाएगी—इसका कर संबंधी अनुपालना पर प्रभाव पड़ा है? कर आंकड़ों के अनुसार नए व्यष्टि कर दाताओं की संख्या 2015-16

की 63.5 लाख से बढ़कर 2016-17 में 80.7 लाख हो गई है। परन्तु इन सभी बढ़ोतरियों का श्रेय विमुद्रीकरण को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नए करदाताओं के बढ़ने में कुछ प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसकी बजाय, पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में विमुद्रीकरण पश्च अवधि (9 नवंबर, 2016-मार्चान्त 2017) में करदाताओं की संख्या बढ़ने को मापकर इस प्रभाव का अनुमान लगाया गया है।

1.86 जैसाकि सारणी 6 दर्शाती है, विमुद्रीकरण पश्च करदाताओं की संख्या में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक थी (25 प्रतिशत की तुलना में 45 प्रतिशत)। यह लगभग 5.4 लाख अतिरिक्त करदाता या केवल कुछ महीनों में सभी व्यष्टि करदाताओं का 1 प्रतिशत था। सूचित कर-योग्य आय में वृद्धि (नए करदाताओं में से) लगभग ₹10,600 करोड़ थी। अतः विमुद्रीकरण के बाद कराधार वाकई बढ़ा है। तथापि, यह रोचक तथ्य है कि नए करदाताओं में से संसूचित औसत आय ₹2.7 लाख, आरंभिक ₹2.5 लाख कर से बहुत अधिक नहीं था। अतः कर संग्रहण पर तत्काल प्रभाव फीका पड़ गया था। जैसे-जैसे इन करदाताओं की संसूचित आय बढ़ती जाएगी, संग्रहण पर पूरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा।

1.87 कुल मिलाकर, समय बीतने के साथ-साथ विमुद्रीकरण से लाभ मिलना जारी रहना चाहिए क्योंकि

### सारणी 6. विमुद्रीकरण के बाद अतिरिक्त करदाताओं का अनुमान (9 नवंबर-31 मार्च)

	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2016-17
नए करदाताओं में वृद्धि	25.1	45.3
विमुद्रीकरण के चलते संभावित अतिरिक्त करदाता (पिछले वर्ष की वृद्धि की तुलना में अतिरिक्त के अनुसार परिकल्पित)		5.4
विवरणों में दर्ज आय में वृद्धि	38.6	54.3
विवरणों में दर्ज आय में संभावित वृद्धि (करोड़)		10,587
औसत करयोग्य आय (लाख)	2.5	2.7

<sup>16</sup> विमुद्रीकरण पूर्व मौसम के अनुसार समायोजित आंकड़ों के लिए प्रयुक्त त्रि घातांकी समायोजन (अर्थात् हॉल्ट-विटर्स) से पूर्वानुमान की प्रवृत्ति ली गई है। आर में 'सीज' पैकेज का उपयोग करते हुए मौसम के अनुसार समायोजन किया जाता है; कीमतों के संबंध में आंकड़े एनसीआर, मुम्बई, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और अहमदाबाद के स्थावर सम्पदा की कीमतों का औसत है, जो प्रत्येक शहर में संपत्ति की बिक्री के मूल्यों द्वारा प्रभासित है।



इसने अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने और कराधार बढ़ाने की जो गति बनाई है, वह जारी रहेगी।

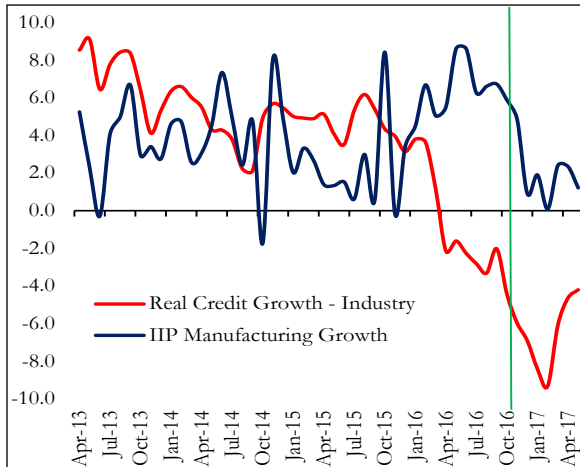
### 3. जीडीपी

1.88 वास्तविक जीडीपी वृद्धि, वित्तीय वर्ष के दौरान धीमी गति के कारण 2015-16 के 8 प्रतिशत से गिरकर 2016-17 में 7.1 प्रतिशत रह गई। वास्तविक जीडीपी वृद्धि, 2016-17 की पहली छमाही में 7.7 प्रतिशत से घटकर दूसरी छमाही में 6.5 प्रतिशत रह गई। तिमाही आधार पर जीडीपी वृद्धि भी पहली दो तिमाहियों की तुलना में तीसरी और चौथी तिमाही में गिरावट दर्शाती है। इन संकेतकों में देखी गई मंदी विमुद्रीकरण से पहले हुई थी लेकिन विमुद्रीकरण के बाद की अवधि में और गहन हो गई।

1.89 उच्च बारंबारता वाले संकेतक-उदाहरणार्थ उद्योग की वास्तविक ऋण वृद्धि, आईआईपी विनिर्माण-ऐसा ही पैटर्न दर्शाते हैं। चित्र में यह भी दर्शाया गया है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा लगता है कि प्रभाव कम हो गया है जैसाकि इन संकेतकों के वापस पटरी पर आने से दिखता है (चित्र 22)।

1.90 परन्तु जीडीपी अनुमानों से विमुद्रीकरण की एक पहली सी उभरती है। हांलाकि वास्तविक वृद्धि नरम हुई, यह गिरावट अनुमान से बहुत कम थी: समग्र रूप से वर्ष के लिए वृद्धि आर्थिक समीक्षा 2016-17 खण्ड-I में अनुमानित 6.5 से 6.75 प्रतिशत के दायरे से बहुत अधिक थी। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह है कि

चित्र 22. उच्च बारंबारता वाले समष्टि आर्थिक संकेतक



स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

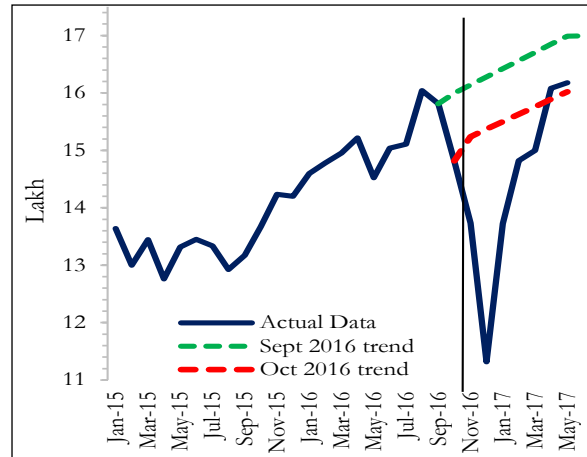
अनुमानित जीडीपी वृद्धि में विमुद्रीकरण के बाद तेजी आई, जैसाकि बॉक्स 3 में स्पष्ट किया गया है।

### 4. अनौपचारिक क्षेत्रक का प्रभाव: मनरेगा

1.91 आर्थिक समीक्षा खण्ड 1 में यह बताया गया था कि विमुद्रीकरण के प्रभाव अल्पावधिक होंगे। खण्ड 1 में यह भी बताया गया था कि परम्परागत आर्थिक संसूचक-जिसमें आंकड़े औपचारिक क्षेत्रकों के संबंध में लिए जाते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह विमुद्रीकरण से अपेक्षाकृत कहीं अधिक अप्रभावित बना रहेगा - में इन कारकों का प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। दो पहिया वाहनों की बिक्री के मामले में अनौपचारिक क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में किए गए एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विमुद्रीकरण के बाद इनमें तेजी से गिरावट आयी है, किंतु 6 से अधिक महीनों के बाद स्थिति विमुद्रीकरण से लगभग पूर्व की अवस्था पर लौट आई है। (चित्र 23)। वास्तविक बिक्री तथा रुझान रेखाओं के बीच संचयी गिरावट कम समय तक चलने वाले अनौपचारिक प्रभावों का एक अनुमान है।

1.92 अनौपचारिक क्षेत्रक के संबंध में लागत को ज्ञात करने का एक वैकल्पिक तरीका बीमा के लिए मांग से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करना है। नकारात्मक रूप में प्रभावित परिवारों द्वारा बीमा की मांग की जाती है जो परिवार और मित्रों की ओर से अनौपचारिक बीमा या सरकार द्वारा मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी स्कीमों जैसी अधिक औपचारिक सामाजिक बीमा के रूप में होती है।

चित्र 23. घरेलू बाजार में दो पहिया वाहनों की बिक्री के संबंध में आंकड़े (मौसमी आधार पर समायोजित)



स्रोत: भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माताओं के लिए सोसाइटी

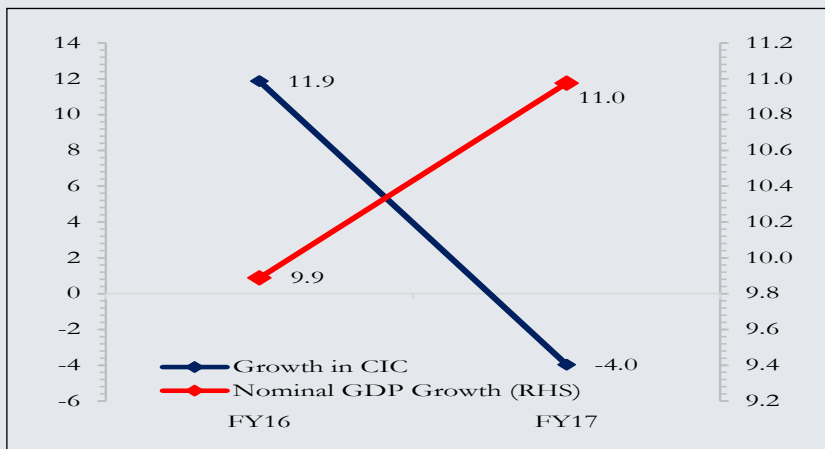
### बॉक्स 3. विमुद्रीकरण और अनुमानित जीडीपी पहली

फरवरी में आर्थिक समीक्षा के खण्ड-I में तर्क दिया गया था कि जीडीपी वृद्धि पर विमुद्रीकरण के अल्पावधिक प्रभाव का आकलन करने में, वास्तविक जीडीपी वृद्धि की बजाय मौद्रिक वृद्धि अधिक बेहतर संकेतक रहेगी: “आखिरकार विमुद्रीकरण अधिकांशतः मौद्रिक मांग झटका है, अतः पहली बार इसका प्रभाव मौद्रिक परिमाण पर होगा।

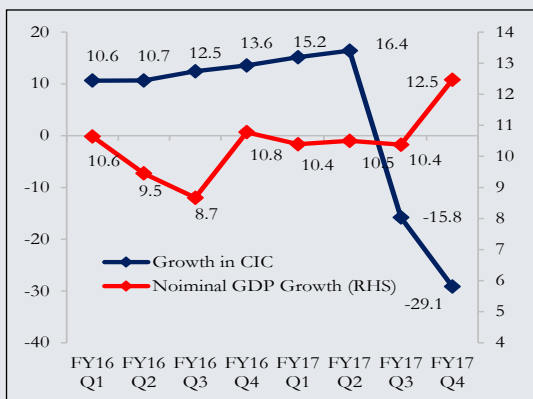
मौद्रिक परिमाण वास्तविक से बिलकुल अलग छवि प्रस्तुत करते हैं। चाहे तुलना वार्षिक रूप से की जाए या तिमाही आधार पर, आंकड़े दर्शाते हैं कि विमुद्रीकरण के बाद मौद्रिक जीडीपी वृद्धि में तेजी आई है। 2016-17 में वार्षिक मौद्रिक जीडीपी वृद्धि 2015-16 की वृद्धि से लगभग 1.1 प्रतिशतांक अधिक थी; 2016-17 की दूसरी तिमाही में भी यह पहली छमाही की अपेक्षा 1.1 प्रतिशतांक अधिक थी।

यह कितनी बड़ी पहली है, इसे समझने के लिए समतुल्य मौद्रिक झटके का स्मरण करना उचित होगा: वार्षिक आधार पर नकदी में वृद्धि 12 प्रतिशत से घटकर (-) 4 प्रतिशत रह गई। अतः नकदी वृद्धि में लगभग 16 प्रतिशतांक के परिवर्तन के परिणामस्वरूप मौद्रिक जीडीपी वृद्धि में 1 प्रतिशतांक की बढ़ोतरी हुई है।

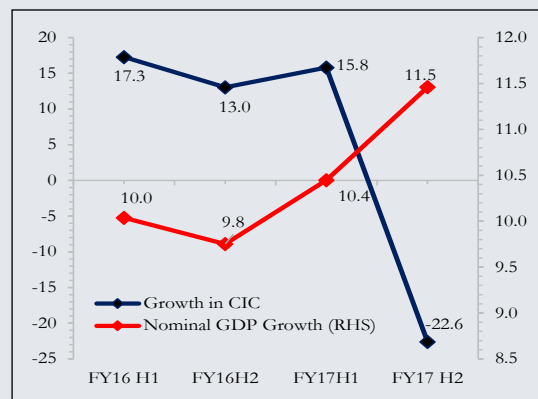
चित्र: वार्षिक सीआईसी एवं मौद्रिक जीडीपी वृद्धि ( प्रतिशत )



चित्र: तिमाही सीआईसी एवं मौद्रिक जीडीपी वृद्धि ( प्रतिशत )



चित्र: अर्धवार्षिक सीआईसी एवं मौद्रिक जीडीपी वृद्धि ( प्रतिशत )



वृद्धि की यह दर पिछले अनुच्छेद में बतायी गई यह बात कि विमुद्रीकरण के कारण कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी आई, को देखते हुए आश्चर्यजनक है। अधिक मौलिक रूप में, यह तथ्य मौद्रिक सिद्धान्त के संदर्भ में भी आश्चर्यजनक है। नकदी की उपलब्धता में वृद्धि की दर 2016-17 की दूसरी छमाही के 16 प्रतिशत से घटकर 2016-17 की पहली छमाही में (-) 23 प्रतिशत हो गई जो 39 प्रतिशत अंक कमी को दर्शाता है। अगर यह भी मान लिया जाए कि कुछ नकदी राशि निष्क्रिय पड़ी हुई थी तो भी धनराशि के परिमाण से संबंधित सिद्धान्त के किसी भी विश्वसनीय लगने वाली बात से यह पूर्वानुमान प्राप्त होगा कि जीडीपी विकास में मामूली गिरावट आई हालांकि इसकी गति में विश्वसनीय प्रतीत होने वाली वृद्धि बतायी गई। इसके बजाए अर्थव्यवस्था में तेजी दिखाई पड़ती है। (परिशिष्ट 2 में इस संबंध में एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार वास्तविक तथा नाममात्रिक परिमाण का आकलन किया जाता है)।

वास्तव में, मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग जिन वर्षों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है उन वर्षों के दौरान प्रायः बढ़ जाती है जो इस बात को इंगित करती है कि यह स्कीम एक प्रकार के सामाजिक बीमा के रूप में उपयोगी है (फेट्जर 2014)<sup>17</sup>।

1.93 अतः प्रश्न यह है कि क्या मनरेगा से संबंधित आंकड़े इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि विमुद्रीकरण के कारण सामाजिक बीमा के लिए मांग में वृद्धि हुई है। इसका आकलन करने के लिए, हमने पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक सप्ताह से संबंधित मनरेगा रोजगार के जिलावार आंकड़ों को संकलित किया। ये आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे।

1.94 क्या 8 नवम्बर से पहले के सप्ताहों की तुलना में 8 नवम्बर के बाद के सप्ताहों में मनरेगा के तहत रोजगार में वृद्धि हुई और क्या यह प्रभाव पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वर्ष 2016 (विमुद्रीकरण का वर्ष) के दौरान अधिक स्पष्ट था। यह आम तौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली एक अनुभव आधारित पद्धति थी जिसे अंतरों में अंतर ज्ञात करने की विधि के नाम से जाना जाता है (बट्ट्रेण्ड और अन्य 2004 परिशिष्ट 4)। इन आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया और उन कारकों को ज्ञात किया गया जिनके कारण इस वर्ष और इसके पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मनरेगा पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ा था। इससे संबंधित ब्यौरे परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं।

1.95 मुख्य निष्कर्ष चित्र 24-27 में दर्शाए गए हैं और ये निष्कर्ष सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित हैं। विमुद्रीकरण की अवधि (नवम्बर, 2016 के आरंभ से लेकर मार्च 2017) के दौरान बीमा के लिए मांग में वृद्धि हुई है, इस संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये स्थिति विशेषकर कम विकसित राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के संबंध में अधिक मजबूत बनी रही (चित्र 25) जिसके दौरान काम पर रखे गए मानव दिवसों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ये परिणाम तुलना के प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाए गई समय अवधि तथा साथ ही तुलना के वर्षों के संदर्भ में संवदेनशील हैं।

1.96 यह एक रोचक बात है कि विमुद्रीकरण-मनरेगा के बीच संबंधों के 4 चरण थे: (क) विमुद्रीकरण के

बाद लगभग 4 सप्ताह तक मनरेगा कार्य के लिए मांग में कमी की स्थिति बनी रही; (ख) इसके पश्चात् स्थिति में सुधार आने में 4 सप्ताह का समय लग गया, और उसके बाद (ग) 10 सप्ताह की अवधि जबकि मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई; और अंत में, (घ) मार्च के मध्य के बाद से पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में मनरेगा की मांग के संबंध में कोई अंतराली प्रभाव एक बार पुनः दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

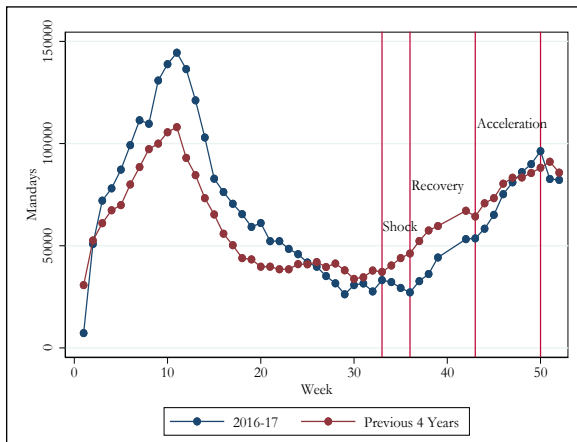
1.97 यह व्यापक पैटर्न विशेषरूप से कम विकसित राज्यों में दिखाई देता है जिनमें तीसरे चरण के दौरान मांग में अधिक उछाल आया, तथा बिहार के संदर्भ में मनरेगा के अंतर्गत मांग में विशेष तौर पर अधिक वृद्धि हुई। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता (चित्र 27)।

1.98 इस संदर्भ में दो पैटर्न विशेषकर ध्यातव्य हैं। उत्तर प्रदेश में विमुद्रीकरण के कारण पड़ने वाला कोई भी प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से दिखाई नहीं देता जो ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष के आरंभ में पिछले वर्षों की तुलना में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार में आई तेज वृद्धि से संबंधित है (चित्र 27)। यह भिन्नात्मक पैटर्न अन्य किसी राज्य में स्पष्ट दिखाई नहीं देता (चित्र 24, 25 और 26)। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण यह है कि यदि लोगों ने वर्ष के आरंभिक हिस्से में मनरेगा से प्राप्त होने वाले अधिकतम भत्तों को प्राप्त कर लिया तो यह एक सहज बात है कि वर्ष के परवर्ती हिस्से में, जो विमुद्रीकरण की भी अवधि है मनरेगा के तहत रोजगार की कम उपलब्धता होगी। उत्तर प्रदेश संभवतः परवर्ती/पूर्ववर्ती विश्लेषण के लिए अधिक उपयुक्त राज्य नहीं है क्योंकि आपूर्ति ओर मांग दोनों पूर्ववर्ती अवधि सभी वर्षों में प्रायः एक समान होती है, यह बात उत्तर प्रदेश के संबंध में लागू नहीं होती।

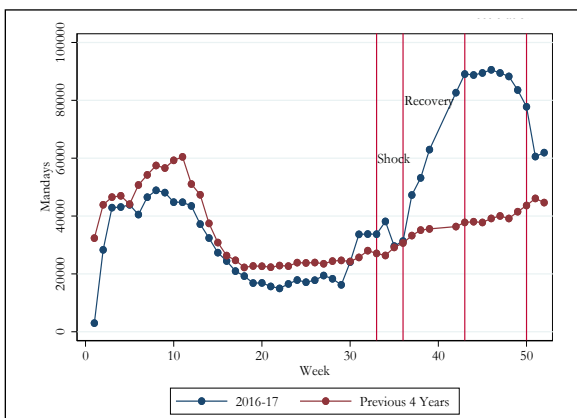
1.99 दूसरी बात, विमुद्रीकरण के बाद के पहले 4 सप्ताहों में मांग में कमी का पैटर्न हैरान कर देने वाला है। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण यह है कि विमुद्रीकरण के कारण मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में वृद्धि हुई है किन्तु आरंभ में मनरेगा के तहत काम सृजित करने में स्थानीय सरकार की क्षमता से संबंधित बाधाओं के

<sup>17</sup> फेट्जर, टी.(2014), "सोशल इन्स्युरेन्स एंड कन्फ्लिक्ट: एविडेन्स फ्रॉम इंडिया, वेबसाइट: [www.trfjetzer.com/wp-content/uploads/JMP.pdf](http://www.trfjetzer.com/wp-content/uploads/JMP.pdf) पर उपलब्ध

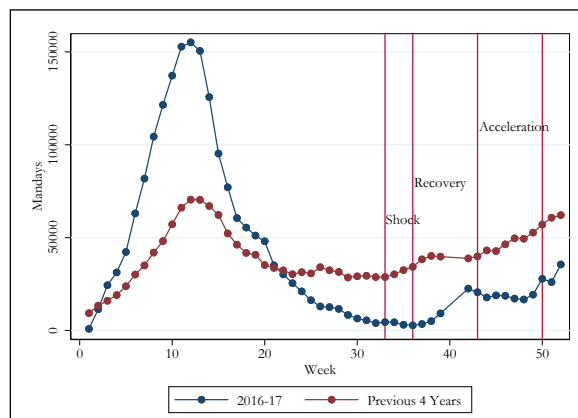
चित्र 24. अखिल भारत



चित्र 26. बिहार



चित्र 27. उत्तर प्रदेश



स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा सर्वेक्षण परिकलन

कारण असंतुलित हो गई। इसके दृष्टिगत, विमुद्रीकरण के कारण बीमा हेतु आपूर्ति और मांग दोनों में कमी आई तथा पहले कुछ सप्ताहों में उपलब्धता में कमी के कारण मांग में वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बाद में नकदी का प्रवाह आरंभ होने और वित्तीय बाधाएं समाप्त हो जाने पर बीमा हेतु मांग को आंकड़े में स्पष्ट तौर पर समझा जा सकता है।

1.100 वैकल्पिक रूप में, यह संभव है कि 2016-17 में बेहतर कृषि उत्पादन, जो विमुद्रीकरण के बाद शस्य प्रापण के 4 सप्ताहों के दौरान विशेषरूप से प्रदर्शित हुआ, के कारण विमुद्रीकरण के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को संतुलित करने में सफलता प्राप्त हुई।

1.101 कुल मिलाकर तीन प्रायोगिक परिणाम इस संबंध में सुझाव देते हैं। पहला, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण सामाजिक बीमा हेतु मांग में वृद्धि हुई जो विशेषकर कम विकसित राज्यों के संबंध में ज्ञात हुई किन्तु आश्चर्यजनक रूप से उत्तर

प्रदेश इसका अपवाद रहा। दूसरा, यह प्रभाव दिसम्बर और मार्च के बीच की अवधि के दौरान उच्च स्तर पर बना रहा और इसके बाद यह समाप्त हो गया जो चित्र 24 में दर्शाए गए अनुसार दो पहिया वाहनों की बिक्री के संबंध में प्राप्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है, और अंतिम, मनरेगा आवश्यकता के समय के दौरान एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र होने के रूप में अपनी उल्लिखित भूमिका को पूरा करने में सफल प्रतीत होता है।

1.102 इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि परिणाम निर्णायक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, परवर्ती-पूर्ववर्ती अवधि के बीच की स्थिति में अंतर की माप करने के लिए विमुद्रीकरण से पहले की जितनी अधिक अवधि को प्रयोग में लाया जाएगा उतने ही क्षीण परिणाम प्राप्त होंगे। विमुद्रीकरण और अनौपचारिक क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बीच सभी विपुल एवं जटिल परस्पर संबंधित कारणों के समाधान के लिए और अधिक अनुसंधान करने की आवश्यकता है।

## 5. क्या मौजूदा विकास के रुझान को बनाए रखा जा सकता है?

1.103 गत 2 वर्षों के दौरान जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की दर 7.5 प्रतिशत रही है। किन्तु यह वृद्धि कम निवेश, निर्यात की मात्रा तथा ऋण वृद्धि की स्थिति में प्राप्त की जा सकी है। निरंतर विकास की गति में इस कमी की स्थिति और इसे प्रेरित करने वाले अपेक्षाकृत अंतर्निहित दुर्बल कारकों के कारण एक प्रश्न उठता है और साथ ही एक पहली भी खड़ी होती है। इस समस्या पर प्रकाश डालने के लिए विभिन्न देशों की स्थिति का एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है और यह देखा गया है कि क्या गत 25 वर्षों के दौरान अन्य उभरते हुए बाजार वाले देशों में ऐसी ही स्थिति रही है (अर्थात् आनुक्रमिक 2 वर्षों की अवधियों जबकि भारत में विकास की दर कारकों के ऐसे संयोजन से प्राप्त की गई हो अर्थात् 2015-16 और 2016-17 के दौरान वास्तविक निवेश, निर्यात की मात्रा और ऋण में हुई वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्तर)। यह अध्ययन आंकड़ों की उपलब्धता को देखते हुए गत 25 वर्षों के संबंध में किया गया है।

1.104 पहला, गत 2 वर्षों (2015-16 और 2016-17) के दौरान वास्तविक निवेश (सकल स्थिर पूंजी निर्माण), निर्यात की मात्रा और ऋण की मात्रा के संबंध में भारत की स्थिति की पहचान की गई है।<sup>18</sup> इस अवधि के दौरान निवेश में 4.5 प्रतिशत (वास्तविक) वृद्धि हुई, निर्यात की मात्रा में 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा ऋण-जीडीपी अनुपात में 2 प्रतिशत अंकों की कमी आई (सभी वार्षिक औसत)। उसके पश्चात लगभग 23 अन्य तुलनीय देशों (इनकी सूची परिशिष्ट 5 में दी गई है) के एक प्रतिदर्श पर विचार किया गया था ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि कितनी बार निवेश, निर्यात की मात्रा और ऋण की मात्रा के इस संयोजन में कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है। परिणाम सारणी 7 में दिए गए हैं।

1.105 चूंकि इस संबंध में तीन मानदण्डों को प्रयोग में लाया गया है अतः सात संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं: तीन ऐसे मामले जिनमें किसी भी एक मानदंड को प्रयोग में लाया गया हो, तीन ऐसे मामले जिनमें किन्हीं दो मानदंडों के संयोजनों को प्रयोग में लाया गया हो, तथा एक मामला ऐसा जिसमें तीनों मानदंड प्रयोग में लाए गए हों। सारणी से पता चलता है कि पिछले 25 वर्षों के दौरान ऐसा कभी

नहीं हुआ जबकि मौजूदा भारतीय संयोजन के अनुरूप निवेश, निर्यात और ऋण के मामले में 7 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई हो। वास्तव में, ऐसा भी कोई मामला नहीं ज्ञात हुआ जहां तीन में दो मानदण्डों को प्रयोग में लाया गया हो। केवल अत्यधिक कम मामलों में, 7 प्रतिशत के संगत वृद्धि प्रदर्शित हुई है वह भी जबकि तीन में से केवल एक मानदण्ड पूरा किया गया हो।

1.106 अगला प्रश्न यह है कि निवेश, निर्यात की मात्रा और ऋण के संबंध में भारतीय संयोजन 5 प्रतिशत वृद्धि के दुर्बल विकास निष्पादन से संबंधित है (सारणी 7)। एक बार फिर उत्तर 'कभी नहीं' में है। वास्तव में, 5 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि तीन में दो मानदण्डों के संगत रही है जिसे केवल चार प्रतिशत बार ही पूरा किया गया है।

1.107 अतः गत दो वर्षों के दौरान भारतीय स्थिति वास्तव में आपवादिक स्वरूप की रही है। इस संबंध में अन्य प्रकार से यह कहा जा सकता है कि 7 प्रतिशत प्रतिदर्श में औसत निवेश और निर्यात मात्रा में वृद्धि क्रमशः 13.8 प्रतिशत और 12 प्रतिशत हुई है जो भारत की स्थिति की तुलना में काफी अधिक है। एक कठोर लेखांकन परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि भारत की इस आपवादिक स्थिति की व्याख्या करने में कोई कठिनाई नहीं है। परिभाषा की दृष्टि से, खपत और कुछ कम हद तक सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है। किन्तु विभिन्न देशों के साथ भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना का प्रयोजन लेखांकन से संभावित आर्थिक स्पष्टीकरण की ओर बढ़ना है।

1.108 परिणाम अत्यधिक स्पष्ट है। चूंकि मौजूदा स्थिति निश्चित रूप से किसी अन्य देश के संबंध में लागू नहीं होती, अतः मौजूदा वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए विकास के अपेक्षाकृत अधिक सामान्य प्रेरकों जैसेकि निवेश एवं निर्यात में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी तथा ऋण वृद्धि को सुकर बनाने के लिए तुलन पत्रों को साफ-सुथरा रखना होगा।

## 6. बैंकिंग: विद्युत तथा दूरसंचार क्षेत्र की लाभकारिता में निरंतर कमी आना तथा दोहरे तुलनपत्र से संबंधित चुनौती

1.109 दो क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ है जो टीबीएस समस्या के समाधान और इस प्रकार ऋण, निवेश और आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण को दुष्प्रभावित करती है।

<sup>18</sup> मुख्य ध्यान पिछले दो वर्षों से संबंधित आंकड़ों पर दिया गया है क्योंकि इस दौरान डब्ल्यूपीआई और सीपीआई श्रृंखला के बीच भारी अंतर देखा गया जिसके कारण जीडीपी के संबंध में अनुमान लगाना जटिल हो गया है।

## सारणी 7. भारत की मौजूदा विकास दर का विश्व के अन्य देशों के साथ तुलनात्मक रिकार्ड ( 1191-2015 )

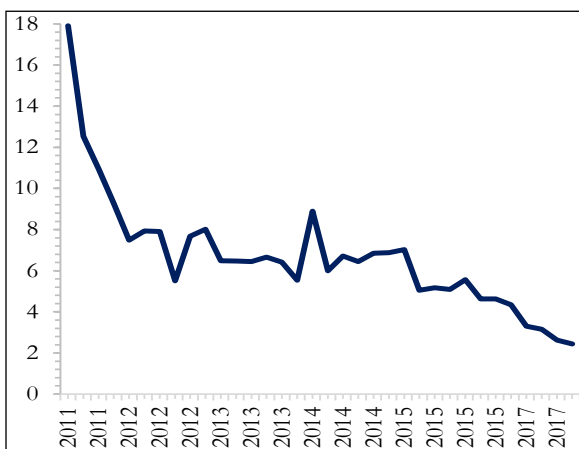
मानदंड	जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता $\geq 7\%$	जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता $\geq 5\%$
		108
क. किसी भी एक मानदंड के पूरा होने की स्थिति में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता का प्रतिशत	16	29
ख. किन्ही दो मानदंडों के पूरा होने की स्थिति में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता का प्रतिशत	0	4
ग. सभी तीनों मानदंडों के पूरा होने की स्थिति में जीडीपी में वास्तविक वृद्धि की बारंबारता का प्रतिशत	0	0

टिप्पणी: निर्धारित मानदंड हैं ( 1911 से 2016 के दौरान प्रत्येक 2 वर्ष की अवधि के लिए): (i) वास्तविक निवेश वृद्धि  $\leq 4.5\%$ , (ii) निर्यात में वृद्धि  $\leq 2\%$ , और (iii) ऋण और जीडीपी अनुपात में कम से कम 2 प्रतिशतता अंक की कमी। निर्यात वृद्धि के लिए न्यूनतम सीमा 2% मानी गई है, तब भी जबकि भारत के लिए वित्त वर्ष 16 और वित्त वर्ष 17 के दौरान इसमें औसत वृद्धि 1% से कम रही हो। ऋण और जीडीपी अनुपात संबंधी आंकड़ा विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है तथा इसमें ऋण के बैंक से इतर स्रोत शामिल हैं।

1.110 विद्युत के क्षेत्र में अल्पावधिक और मध्यम अवधि से संबंधित दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाली अनेक उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं। जैसा कि चित्र 28 में दिखाया गया है, नवीकरणीय ऊर्जा की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है। यह भारत तथा विश्व द्वारा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए एक सकारात्मक दीर्घावधिक स्थिति है। किन्तु इसके कारण अनेक अल्पावधिक चुनौतियां सामने आएंगी।

1.111 चित्र 29 में निजी क्षेत्र में ताप विद्युत के उत्पादन में 883 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्शाई गई है जो ताप विद्युत उत्पादन में कुल वृद्धि का 57 प्रतिशत है। बिजली के उत्पादकों तथा वितरकों के बीच दीर्घावधिक शक्ति क्रय करार (पीपीए) के दौरान एक पूर्व निर्धारित हिस्सा

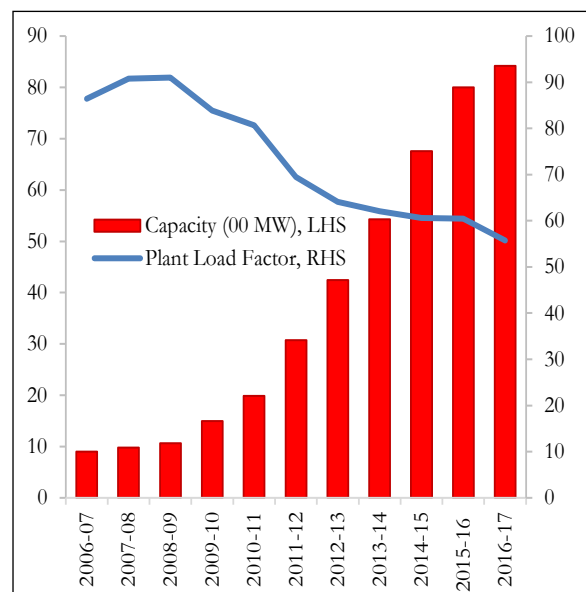
चित्र 28. भारत में सौर ऊर्जा से उत्पन्न प्रति यूनिट बिजली की कीमत (रुपए प्रति किलो वाट घण्टा)



स्रोत: सोलरडे.कॉम

तय किया गया है। तथापि, बिजली उत्पादन में काफी वृद्धि होने तथा बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति के कारण मांग में कमी आने के कारण मांग को उत्पादन के अनुरूप नहीं रखा जा सका है। ताप विद्युत की मांग में कमी काफी हद तक इस कारण हुई है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित बिजली की कीमत अधिक प्रतिस्पर्धी होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप औसत संयंत्र लोड फैक्टर लगातार घटकर लगभग 60 प्रतिशत पर पहुंच गया है (चित्र 29)।

चित्र 29. निजी क्षेत्र में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता तथा संयंत्र लोड फैक्टर (आरएचएस) (क्षमता हजार मेगावाट में)

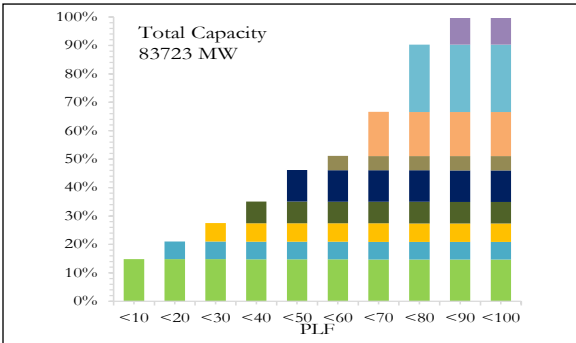


स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

1.112 इसका अर्थ यह है कि संयंत्र क्षमता को देखते हुए मौजूदा वितरण की स्थिति में अनेक संयंत्र क्षमता उपयोग के व्यवहार्य स्तर से काफी नीचे पर प्रचलित हो रहे हैं। यदि 60 प्रतिशत और इससे अधिक का एक स्थूल मानक व्यवहार्य मान लिया जाए तो चित्र 30 से यह ज्ञात होता है कि मौजूदा क्षमता का लगभग 50 प्रतिशत अव्यवहार्य है।

1.113 इसे ध्यान में रखते हुए क्रेडिट स्वीस द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष बिजली के क्षेत्र में काम कर रही दबाव ग्रस्त कंपनियों को अनुपात (इसे कंपनियों द्वारा लिए गए ऐसे ऋण की हिस्सेदारी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका ब्याज कवरेज (आईसी) अनुपात 1 से कम हो) निरंतर बढ़ रहा है और 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है तथा इनका जोखिम के स्तर का ऋण 3.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है (चित्र 32)।

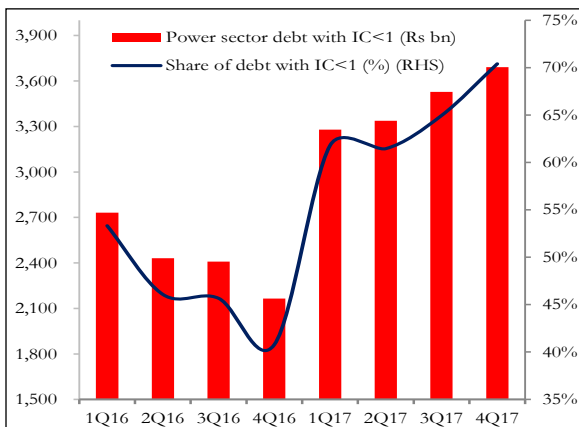
चित्र 30. निजी क्षेत्र में कोयला तथा गैस उत्पादन की क्षमता-पीएलएफ वितरण



स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्रधिकरण

टिप्पणी: अलग-अलग रंग क्षमता में वृद्धिशील योग को सूचित करते हैं।

चित्र 32. निजी क्षेत्र में ऋण, जबकि ब्याज कवरेज 1 से कम हो

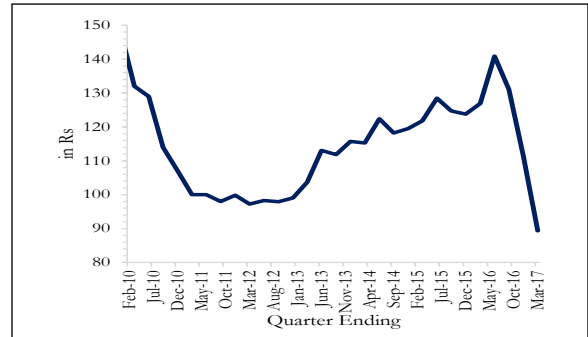


स्रोत: क्रेडिट स्वीस के आकलन

टिप्पणी: आईसी ब्याज कवरेज को सूचित करता है। यदि आईसी<1 हो तो आय इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे ब्याज देनदारियां पूरी की जा सकें।

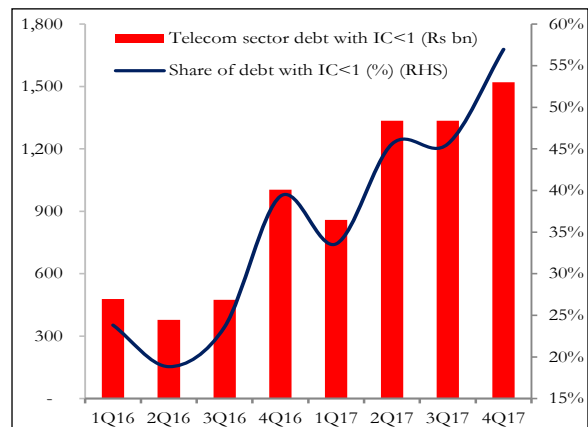
1.114 किन्तु मध्यम कालिक समस्याएं भी हैं जिन पर कम ध्यान दिया जाता है। जैसेकि बिजली वितरण कंपनियां यह समझती हैं कि उन्होंने बिजली उत्पादकों के साथ जिस मूल्य पर बिजली का क्रय करने के लिए करार किया है उससे कम कीमत पर बिजली प्राप्त करने के सस्ते वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा बिजली के प्रशुल्क में कमी करने की मांग अधिकाधिक की जाने लगेगी। हाल में उठने वाली बातें उनकी इस आशंका को स्पष्ट करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वे अपनी कुछ मौजूदा सविदाओं को फिर से तय कर सकते हैं। इससे, विशेषकर भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा हाल ही में दी गई यह व्यवस्था कि ये सविदाएं अति पवित्र होती हैं (इस संबंध में विडम्बना यह है कि इस मामले में निजी क्षेत्र ने सविदा को निरस्त करने और उसे फिर से तय करने मांग की) के संदर्भ में यह मामला और अधिक जटिल हो जाता है। इस तथ्य

चित्र 31. प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व ( रुपए, तिमाही )



स्रोत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

चित्र 33. दूर संचार में ऋण, जबकि ब्याज कवरेज 1 से कम हो





से बिलकुल हटकर कि भारत के पास सविदा को फिर से तय करने के लिए कोई व्यवहार्य ढांचा उपलब्ध नहीं है, भविष्य में कीमतों में कमी आने की स्थिति में क्षमता में और अधिक वृद्धि होना आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य होगा तथा ऋणग्रस्तता में और अधिक वृद्धि होगी जो संपोषणीय स्थिति नहीं होगी।

1.115 दूरसंचार के क्षेत्र में नवीकरणीय आघात को अपने संदर्भों में अनुभव किया गया है जो नए प्रचालकों के दूरसंचार के क्षेत्र में आने के कारण हुआ है जिसके कारण डेटा की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है तथा डेटा अभिगम की स्थिति में सुधार हुआ है जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा है। किन्तु नवीकरणीय आघात के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान दूरसंचार प्रचालकों के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार बने रहने की स्थिति निकट भविष्य में गंभीर होने जा रही है तथा उनकी लाभकारिता में नाटकीय ढंग से कमी आई है। जैसाकि चित्र 31 में दर्शाया गया है, रिलाइंस जियो द्वारा सितम्बर, 2016 में दूरसंचार सेवा की शुरुआत किए जाने के बाद से इस उद्योग में कुल मिलाकर प्रति उपभोक्ता औसत आगम में एक दीर्घावधि (दिसम्बर, 2009-जून, 2016) के दौरान प्राप्ति की तुलना में 22 प्रतिशत कमी आई है और सितम्बर, 2016 के बाद से इसमें लगभग 32 प्रतिशत की कमी आयी है।

1.116 इस कारण को देखते हुए क्रेडिट स्विच द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि जिन कंपनियों का ब्याज कवरेज 1 से कम है उनके दूरसंचार ऋण की हिस्सेदारी 2016 के आखिरी महीनों के बाद से दोगुने से भी अधिक हो गई है, तथा यह दर 55 प्रतिशत से भी ऊपर निकल गई है एवं संबंधित जोखिम ग्रस्त ऋण 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है (चित्र 33)। दूरसंचार के मामले में न केवल बैंकिंग प्रणाली को ही कठिनाई में डाला है बल्कि इससे सरकार को भी परेशानी होने वाली है जिसे उन कंपनियों से विभिन्न प्रकार के शुल्क और कर की प्राप्ति होती है।

1.117 सबसे पहले दिसम्बर, 2014 के मध्यवार्षिक आर्थिक विश्लेषण में भारत के दोहरे तुलन पत्र की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया गया था, जबकि आर्थिक समीक्षा 2016-17 के खण्ड I में इसकी विस्तार से जांच की गई थी। बाद में जारी की गई आर्थिक समीक्षा में इस बात पर बल दिया गया है कि इस चुनौती का सामना करने के

लिए चार स्थितियों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है-मान्यता, समाधान (जिसमें कंपनियों के तुलन पत्र को लक्षित किया जाना है), पुनर्पूजीकरण (जिसमें बैंकों के तुलन पत्रों को लक्षित किया जाना है), और सुधार।

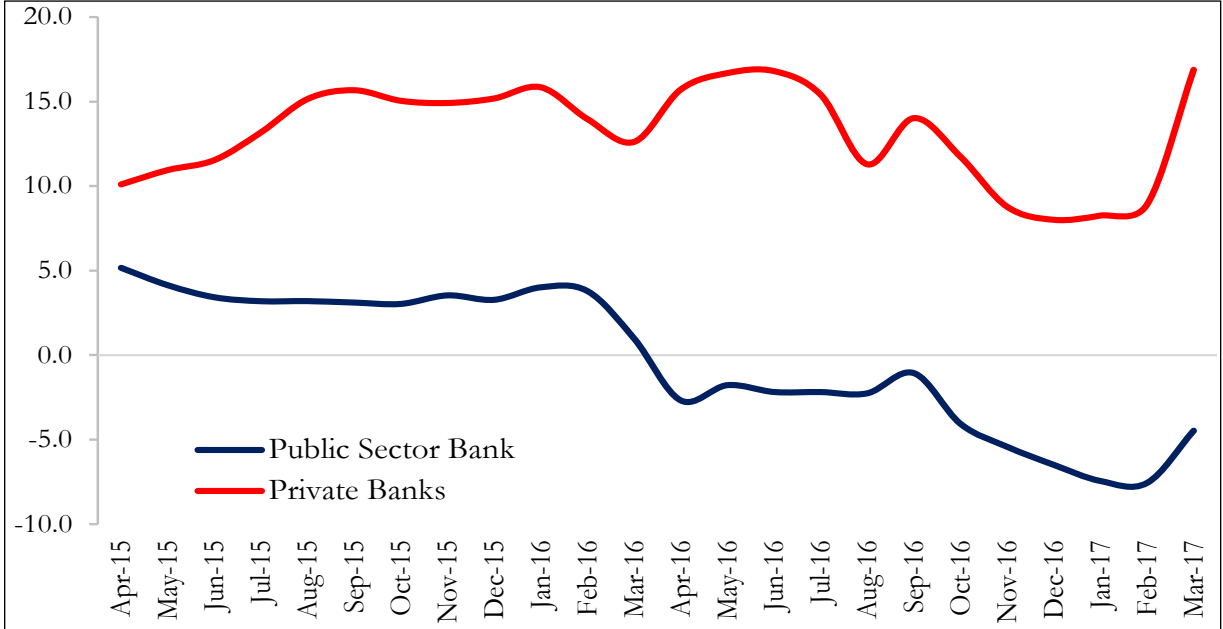
1.118 पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्णायक रूप से मान्यता और हाल ही में समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। मई, 2017 में सरकार ने समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यादेश जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने 13 जून, 2017 को ऐसे 12 ऋण खातों की निर्णायक रूप से पहचान की जिन पर भारत के नए दिवालिया कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जानी है। इस बीच, सुधार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 कमजोर बैंकों को त्वरित उपचारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के अंतर्गत रखा गया है तथा इन बैंकों को अन्य उपायों के साथ अपने बैंकिंग परिचालनों को कम करना शुरू करने के लिए बाध्य किया गया है।

1.119 आशा की जाती है कि इन उपायों से टीबीएस की चुनौतियों का निर्णायक रूप में सामना किया जा सकेगा। प्रेक्षकों द्वारा समाधान प्रक्रिया के विलंबित होने तथा बाधित होने की संभावना के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया है क्योंकि इस संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत परीक्षित नहीं हैं तथा निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के ऋणों को बट्टे खाते में डालने में स्वाभाविक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस दिशा में शीघ्र और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होने से इन संदेहों को शांत करने में सहायता प्राप्त होगी तथा नीति निर्माता इस प्रगति पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए हैं।

1.120 यदि समाधान हेतु लक्षित नए उपायों को लागू कर दिया जाए तो भी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक उपयोगी दृष्टिकोण के संदर्भ में अन्य समाधानों के बारे में सोचना उपयुक्त होगा। दबाव में पड़ी परिसंपत्तियों और पिछले कुछ समय से विद्यमान अनिश्चिता के वातावरण में बैंकों और विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नए ऋण जारी करने के बजाए अपनी अनर्जक आस्तियों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा है। नीचे दिए गए चित्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि ऋण में मंदी के लिए अपर्याप्त मांग की स्थिति से पूर्ण स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता, क्योंकि निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण में काफी अधिक वृद्धि हुई है और इसकी राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी अधिक है।

<sup>19</sup> जून 2016 और मार्च 2017 के दौरान औसत मोबाइल डेटा प्रयोग में 6.5 गुना वृद्धि हुई है तथा यह 154 एमबी से बढ़कर 2000 एमबी हो गया है। प्रति जीबी मूल्य 121 रू. से घटकर 17 रू. हो गया है

चित्र 34. विभिन्न बैंक समूहों द्वारा दिए जा रहे कारपोरेट ऋण\* में वृद्धि



स्रोत: एक्स्ट्रापोलेटिंग राजन ( 2015 ) [https://www.rbi.org.in/scripts/BS\\_SpeechesView.aspx?Id=1013](https://www.rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=1013).

मार्चात 2017 के आंकड़ों की सावधानीपूर्वक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस तारीख को सभी मौद्रिक राशियों में अचानक वृद्धि होती है।

1.121 समस्या यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नए ग्राहकों और अवसरों की तलाश करने की बजाए नुकसान को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अतः वे आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करने के वास्तविक कार्य को फिर से कैसे शुरू कर सकते हैं? समस्याएं फिर से उत्पन्न न हों, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या करना आवश्यक होगा?

1.122 निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व चौथा समाधान, अर्थात् स्थिति में सुधार लाना है। इस संबंध में तीन बातें महत्वपूर्ण होंगी पहली, राहत चयनात्मक आधार पर उपलब्ध कराई जाए, पीसीए ढांचे को लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन बैंकों का कार्यनिष्पादन अत्यधिक निम्न कोटि का है उन्हें आगे से ऋण नहीं दिया जाए और वे कालान्तर में सिमट जाएं। इस प्रकार, राहत केवल आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बैंकों और इसके सनिकट स्थित बैंकों को प्रदान की जाए। दूसरी, निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका में विस्तार किया जाए और कुछ मामलों में निजी क्षेत्र को उनमें बहुमत स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। तीसरी, इन उपायों के साथ ही बैंको के पुर्नपूँजीकरण तथा उनकी ऋण प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ बनाने जैसे विशेष कार्य किए जाएं।

1.123 सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने दोहरे तुलन पत्र (टीबीएस) की चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आशा है कि वे तेजी से कार्य करेंगे। किन्तु उनके कारगर होने की प्रतीक्षा करने के बजाए ऋण, निवेश और विकास की गति को फिर से शुरू करने में सहायक एक बैंकिंग क्षेत्र को सृजित करना हमारी निरन्तर जारी रहने वाली प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए।

## ख. 2017-18 के लिए दृष्टिकोण तथा नीतियां

1.124 इस महत्वपूर्ण समीक्षा में वर्ष 2017-18 के शेष महीनों के संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण तथा बृहत आर्थिक एवं अन्य नीतियों की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया है।

### 1. वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक क्रियाकलापों के संदर्भ में दृष्टिकोण

1.125 किसी भी विकास से संबंधित दृष्टिकोण को व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। व्यापक संदर्भ से आशय विकास की गति को फिर से बहाल करने में प्रत्याशाओं को उपयुक्तता प्रदान करना है।

1.126 पिछले कुछ समय से भारत एक ऐसी पीड़ा को झेल रहा है जिसे कार्मैन रेनहार्ट तथा केनेथ रोगोफ्फ ने

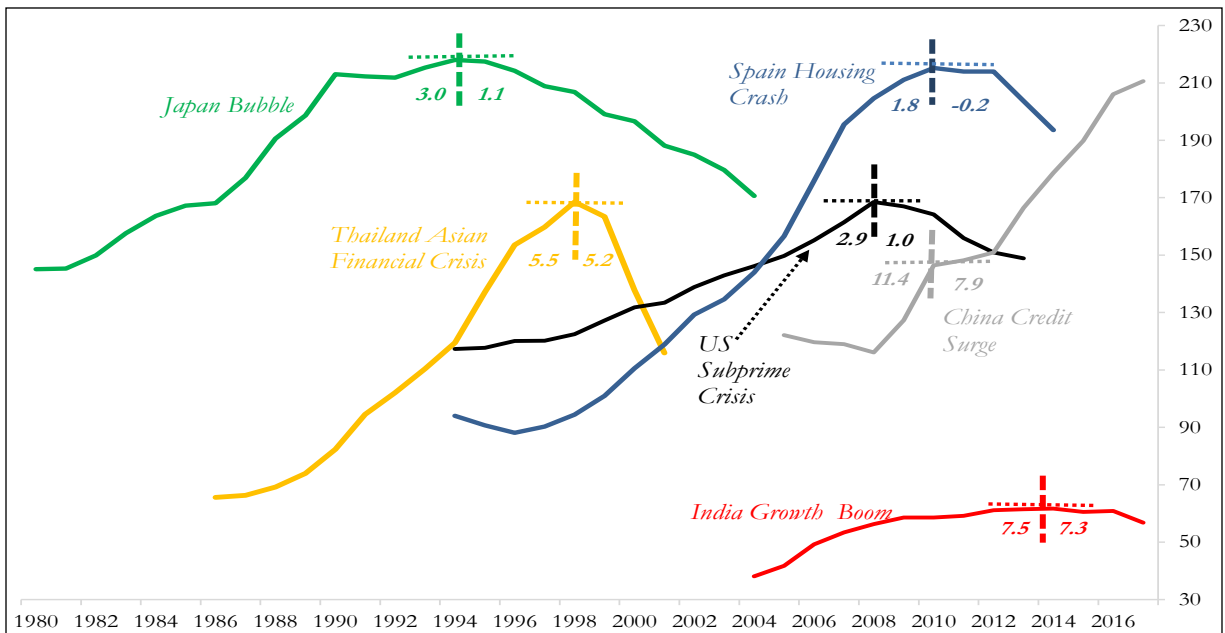
तुलन पत्र में 'मंदी' का नाम दिया है ('मंदी' के बजाए भारत के संदर्भ में इसे संभावित विकास दर से कम दर पर संवृद्धि कहना अधिक उपयुक्त होगा)।

1.127 भारतीय अर्थव्यवस्था में सन् 2000 के दशक के मध्य में ऋण एवं निवेश के संदर्भ में व्याप्त प्रति क्षण परिवर्तनशील स्थिति अभी भी बनी हुई है। चित्र 35 में विभिन्न देशों का संदर्भ दर्शाया गया है। अधिकांश देशों में उछाल के साथ ही ऋण में तेजी से वृद्धि देखी जा सकती है जिसके बाद ऋण में कटौती ज्ञात होती है जिसके पश्चात विकास की गति में तेजी आ सकती है-जिसका होना सुनिश्चित नहीं है। थाइलैंड, अमरीका और स्पेन में विभिन्न सीमाओं तक इस पैटर्न का अनुसरण किया गया है। चीन में एक अलग मार्ग का अनुसरण किया गया है: इस देश में स्थिति का सामना करने के लिए ऋण एवं निवेश के साधनों का फिर से प्रयोग किया गया है ताकि संवृद्धि में मंदी पर रोक लगाई जा सके। इस दृष्टिकोण को अपनाने से अल्पावधि में लाभ प्राप्त होते हैं, हालांकि इसके कारण पूंजी की दक्षता में कमी आती है तथा वित्तीय क्षेत्र में असक्षमता की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण भविष्य में विकास की गति नाटकीय रूप से मंद पड़ सकती है। एक रोचक तथ्य है कि वर्ष 2000 के मध्य में भारत में देखे गये

उछाल के बाद ऋण एवं निवेश के पैटर्न में कोई गंभीर गिरावट नहीं आई। हालांकि गत 2 वर्षों में बैंक ऋण में मंद गति से हो रही वृद्धि चिंता का विषय है, किन्तु यह निश्चित तौर पर मंदी से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः भारत में निवेश और ऋण पर्याप्त स्तर पर पहुंच चुका है। यदि तीव्र विकास की गति फिर से बहाल होने के लिए ऋण में कमी करना एक आवश्यक स्थिति है तो संभवतः भारत को कम ऋण की जरूरत है-यदि संक्षेप में कहा जाए तो इसे अल्पावधि में अधिक ऋण में कटौती करने की आवश्यकता है।

1.128 जैसाकि पहले ही वर्णन किया जा चुका है और चित्र 43-49 के भाग ग में दर्शाया गया है। प्रथम तिमाही, 2016-17 से वास्तविक गतिविधियों के अनेकों संकेतक-जीडीपी, ऋण, निवेश, क्षमता, उपयोग प्रथम की कमी की ओर इशारा कर रहे थे, और तीसरी तिमाही में उनमें और शिथिलता आ गई। चौथी तिमाही 2016-17 में वास्तविक जीवीए वृद्धि 5.6 प्रतिशत थी। जब तक संभावित उत्पादन, अत्यधिक कम है यदि संभावित उत्पादन अधिकांश व्यक्तियों द्वारा माने गए स्तर (लगभग 7 प्रतिशत या अधिक), नहीं रहा तो उत्पादन में अंतर और अधिक हो जाएंगे।

चित्र 35. ऋण में शीर्ष बिन्दुओं तथा जीडीपी में वास्तविक वृद्धि का आलेखीय निरूपण



स्रोत: बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्लमेंट (बीआईएस) तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

आंकड़े में ऋण-जीडीपी अनुपात तथा समय को आलेखित किया गया है; चार्ट में दी गई संख्याएं चीन और भारत को छोड़कर अन्य देशों के संबंध में ऋण-जीडीपी अनुपात के शीर्ष पर पहुंच जाने से 5 वर्ष पहले और बाद में वास्तविक जीडीपी वृद्धि को सूचित करती हैं।

1.129 आगे बढ़ते हुए, प्रश्न है कि लगभग छः महीने पहले प्रकाशित समीक्षा के संस्करण I के सारांश के बाद से क्या परिवर्तन हुए हैं? तब हमने जीडीपी वृद्धि 6.75 और 7.5 के बीच रहने का पूर्वानुमान लगाया था। उस समय हमने मान लिया था कि विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में सुधार का क्रम ऊपर उठेगा और विमुद्रीकरण के बाद से मौद्रिक स्थिति होने वाली रियायतों का प्रभाव भी उस जीडीपी वृद्धि में निहित करेगा।

1.130 तब से सभी नए कारक-वास्तविक विनिमय दर मूल्यवृद्धि, कृषि ऋण माफी, विद्युत क्षेत्र तुलनपत्र पर दूरसंचार, कृषि दबाव, तथा जीएसटी के कार्यान्वयन से परिवर्ती चुनौतियां-गतिविधियों में अपस्फीति संबंधी झुकाव पैदा करते हैं।

1.131 फरवरी 2017 से, आरबीआई की 36-मुद्रा बॉस्केट-के अनुसार वास्तविक प्रभावी संदर्भ में चीन और एशियाई मुदाओं की तुलना में रुपये में लगभग 1.5 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई है। कारण यह है कि चीनी यूआन में भारी गिरावट हुई है, रुपया की तुलना 2.7 प्रतिशत सहित (चित्र 57 और 58 भाग ग में)।

1.132 कृषि ऋण माफी पर अपस्फीति संबंधी प्रभाव निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करेंगे कि कितने राज्य उ०प्र०, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और कर्नाटक अनुसरण करेंगे, और वे कितनी राहत प्रदान कर सकते हैं और यह राहत कितने चरणों में होगी। कुछ तार्किक अवधारणाओं के अनुसार इस वर्ष में अपस्फीति संबंधी प्रभाव जीडीपी के 0.35 प्रतिशत तक हो सकते हैं (यह मानते हुए कि पूर्व भाग में अनुमानित परिमाण दो वर्षों में वितरित किए गए हैं)।

1.133 इसके अतिरिक्त, वास्तविक नीति दर खण्ड-I के पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक कठोर रही है। ऐसी परिस्थितियों में, और यह मानते हुए कि वर्तमान वृहद् 2 अगस्त 2017 को रेपो दर में 25 आधार बिंदु कम की गई मौद्रिक तथा राजकोषीय नीतियों के स्वरूप को बरकरार रखा गया है, जीडीपी के पूर्वानुमान से और जोखिम और कम होंगे।

1.134 अच्छा पहलू यह है कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षण

में सरकार और आरबीआई ने दोहरी तुलनपत्र, चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष उपाय किए हैं। इससे बहुत कम समय में बाजार का विश्वास बढ़ गया है। निवेश एवं ऋण मांग बहाली के लिए कारपोरेट तुलन पत्रों की डिलीव रजिंका आवश्यक है। ऋण आपूर्ति के बंद चैनलों के खोलने के लिए बैंकों के तुलनपत्रों को निष्प्रभावी करना आवश्यक होगा। तथापि, उठाए गए कदमों का वास्तविक प्रभाव कार्य क्षेत्र, प्रभावकारिता और दबाव वाली परिसंपत्तियों का समय पर समाधान करने पर निर्भर करेगा।

1.135 जीएसटी के कुछ अच्छे पहलू भी हैं। चेक पोस्टों को हटाना और परिवहन बाधाओं के लगातार सरलीकरण से आर्थिक गतिविधियों को अल्पावधिक के लिए बढ़ावा मिलेगा।

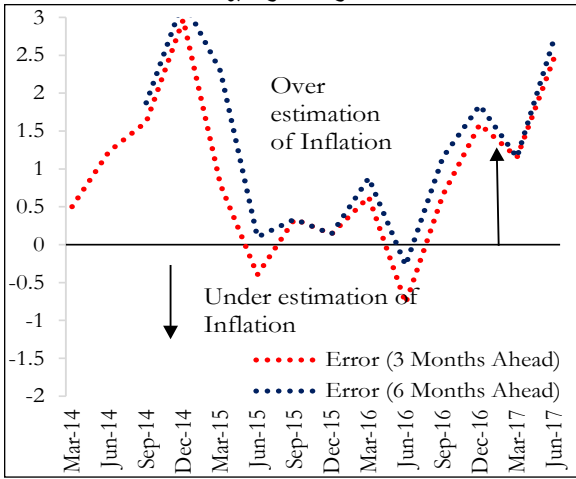
1.136 फरवरी में, सर्वेक्षण (खण्ड-I) में वित्त वर्ष 2018 के लिए वृद्धि 6.75 से 7.5 प्रतिशत के स्तर में रहने के पूर्वानुमान लगाया गया। पूर्व में किए गए विचार-विमर्श से यह संकेत मिलता है कि जोखिम कम हो गए हैं। तदनुसार संभावनाओं का संतुलन बदला है, जहां परिणाम अब पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक भारांश वाले, अपेक्षाकृत कम सीमा के निकट है।

## 2. 2017-18 के लिए मूल्यों और मुद्रास्फीति हेतु आऊटलुक

1.137 'कम मुद्रास्फीति' के बारे में यह तर्क दिया गया है कि भारत पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार और घरेलू कृषि दोनों में और अधिक स्थिर विकास के कारण ढांचागत गैर-स्फीति विषयक परिवर्तन में फंसा हुआ है। जो असंभावित मुद्रास्फीति विकास में दर्शाए गए हैं (चित्र 36 क)

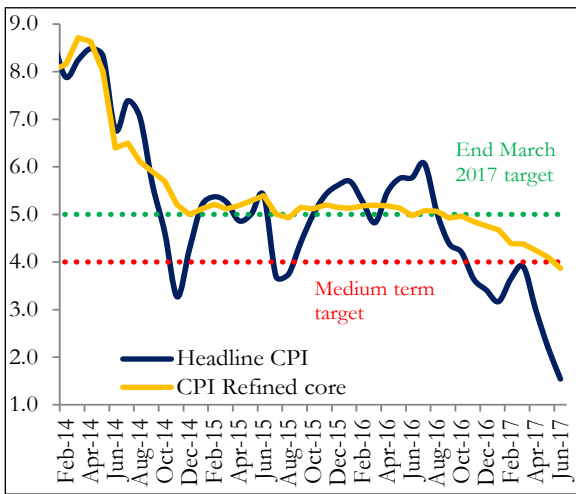
1.138 समीपवर्ती अवधि में हैडलाईन सीपीआई मुद्रास्फीति संख्या नाटकीय ढंग से कम हुई है, जून 2017 में 1.5 प्रतिशत से कम रही जो मध्यावधिक 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम है। (चित्र 36 ख)। मार्च 2017 के लक्ष्य, से 7 महीनों, सितंबर 16 से मार्च 17 तक 124 बिंदु के औसत तक कम हुई है। जून के 246 बिंदुओं के साथ यह मार्च, 2018 के लक्ष्यों से 175 बिंदुओं के औसत से 2017-18 के सभी तीनों महीनों में नीचे चल रही है। परिष्कृत कोर मुद्रास्फीति-मूलभूत मुद्रास्फीति को मापने

चित्र 36क. सीपीआई मुद्रास्फीति: आरबीआई पूर्वानुमान त्रुटि



स्रोत: आरबीआई और सर्वेक्षण गणना

चित्र 36ख. हेडलाइन और रिफाइंड कोर सीपीआई मुद्रास्फीति ( प्रतिशत )



स्रोत: एमओएसपीआई और सर्वेक्षण गणना

की प्रवृत्तियां अस्थिर तेल एवं खाद्य घटकों ने बदल दी और एमपीसी की फरवरी की बैठक में इस बात का उल्लेख भी किया है कि यह लगातार कम हो रही है और अब 3.9 प्रतिशत है, जो मध्यावधिक 4 प्रतिशत के लक्ष्य से कम है।

1.139 इस पृष्ठभूमि के विपरीत, निकट भविष्य में मुद्रास्फीति अनेक निकटवर्ती कारकों द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसमें निम्न शामिल है:

- पूंजी प्रवाह और विनिमय दर जो आऊटलुक एवं उन्नत अर्थव्यवस्था में नीतियों, विशेषरूप से यूएस

से प्रभावित होती हैं, के लिए आउट लुक;

- तात्कालिक सांकेतिक दर अधिमूल्यन;
- मानसून;
- जीएसटी का शुभारंभ;
- 7वां वेतन आयोग अवाइस;
- संभावित कृषक ऋण माफी; और
- उत्पादन अन्तराल

1.140 आईएमएफ और अन्य संस्थानों ने यह नोट किया कि व्यापक-वैश्विक वसूली प्रगति पर है। परन्तु उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीतियों की उलझनें हैं—और इस कारण से भारत से पूंजीगत बहिर्वाह और रुपया के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है।

1.141 उन्नत देश की मौद्रिक नीति की दुविधा यह है कि जब आर्थिक गतिविधियां उछाल पर होती हैं और अस्थिरता के संकेत सामान्यतः कम होते हैं—वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों पर संकट मंडराने के पूर्वाभास, से मौद्रिक नीति सरलीकरण की मांग बढ़ती है, मुद्रास्फीति लक्ष्य से कम रहती है। (केवल यूके में छोड़कर), जैसाकि वैश्विक आर्थिक संकट से यह कई बार घटित हुआ है। इसके अलावा, दीर्घावधिक लाभ कम हुआ है, और इससे मंदी के संकेत मिल रहे हैं। इस प्रकार अभी तक यह देखा जाता रहा है कि मौद्रिक कठोरता अच्छी रहेगी, अर्थात् भारत से पूंजी प्रवाह का जोखिम, इस वर्ष के पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार नहीं है।

1.142 ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि, आर्थिक समीक्षा खण्ड-I के प्रकाशन से सांकेतिक प्रभावों के संदर्भ में सांकेतिक विनिमय दर में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जैसे (फरवरी-जून 2017 के बीच)। भारत के अनुमान बताते हैं कि 10 प्रतिशत विनिमय दर मूल्यवर्धन से सीपीआई मुद्रास्फीति 0.8 प्रतिशत कम हो जाएगी। 'भारत में तीव्र अपस्फीति के क्या कारण हैं? साजिद चिनॉय, पंकज कुमार और प्राची मिश्रा, आईएमएफ वर्किंग पेपर नं डब्ल्यूपी/16/166 मुद्रास्फीति की कम होती गति लगभग 0.25 प्रतिशतांक बिन्दु होगी।

1.143 खाद्य मूल्यों के संदर्भ में, इस वर्ष में वर्षा

दीर्घावधिक औसत के बराबर या अधिक होने की आशा है और 12 जुलाई के अनुसार इसका स्तर तथा क्षेत्रीय वितरण आश्वस्तकारी है। 21 जुलाई तक बुआई आंकड़े उत्साहवर्धक रहे हैं। अरहर को छोड़कर, सभी प्रमुख फसलों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में एकड़वार उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि हुई है जैसे: चावल (4.6 प्रतिशत), दालें (3.4 प्रतिशत) ईख (8.7 प्रतिशत) और कपास (20.1 प्रतिशत) सहित।

1.144 सभी पहलुओं पर विचार करने पर, जीएसटी से मूल्य कम होने की अपेक्षा है क्योंकि पूर्व के केन्द्र और राज्यों के संयुक्त करों की तुलना में कम कर लगना। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि 7वां वेतन आयोग आवास किराया भत्ता से मुद्रास्फीति में 0.4 और 1.2 प्रतिशतांक के बीच औसत वृद्धि हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि केवल केन्द्र या केन्द्र और सभी राज्यों ने आवास किराया भत्ते को लागू किया है या नहीं। इसके अलावा, यह औसत प्रभाव चरणबद्ध समय में कम हो जाएगा, अर्थात् वास्तविक अवार्ड के बाद 6 महीनों में<sup>20</sup> इस तथ्य के अलावा कि जीएसटी और वेतन आयोग के प्रभाव मुख्यतया एक दूसरे में जल्दी ही निष्प्रभावी करेंगे, ये दोनों एकबारगी घटनाएं हैं जो मूल्य स्तर में प्रभावित करते हैं न कि मुद्रास्फीति को। मौद्रिक नीति को सामान्यतः अस्थायी मूल्य स्तर प्रभावों के जरिए देखे जाने की आवश्यकता, उन पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, धन और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर जहां तक संभव हो दुसरे प्रभावों को छोड़कर<sup>21</sup>।

1.145 जैसाकि पहले कहा गया है, कि किसान ऋण माफी गैर अपस्फीति की बजाए अधिक अपस्फीति संबंधी है और इस कारण से कीमतों को ऊर्ध्वमुखी की बजाय अधोमुखी आधार प्रदान किया जाए।

1.146 मुद्रास्फीति के लिए उत्पादन अन्तराल बहुत महत्वपूर्ण है और पूर्व के विचार-विमर्श में कमजोर होती अर्थव्यवस्था और उत्पादन अन्तराल के बारे में रेखांकित करते हैं।

1.147 निम्नांकित मुद्रास्फीति की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन को रेखांकित करते हुए पिछले विश्लेषणों के साथ आउट-लुक का मूल्यांकन इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे चल रही है, यह संकेत करता है कि मार्च 2018 तक मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य से नीचे रहने की संभावना है।

### 3. नीति विषयक दृष्टिकोण

1.148 जीडीपी और मुद्रास्फीति के ये पूर्वानुमान, निसंदेह सशर्त हैं, विशेषकर मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के संबंध में यहां प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टिकोण को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

#### मौद्रिक नीति

1.149 समीक्षा खण्ड-I से मौद्रिक नीति की तीन मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। वास्तविक नीति ब्याज दरें वर्तमान में अत्याधिक ऊंची हैं, सरकारी दरों में असामान्य अस्थिरता है, जो संभावित नीतिगत परिवर्तनों और बैंकों में अधिक नकदी की स्थिति को दर्शाता है जो लगभग नौ महीनों से बची हुई है। बाद की दो का अध्याय 3 में विस्तार से चर्चा की गई है?

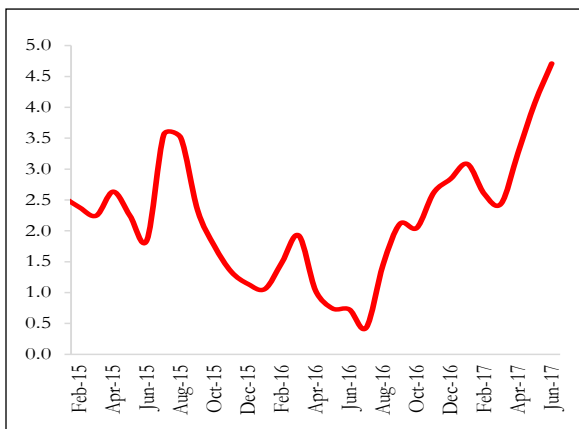
1.150 चित्र 37क और 37ख मौद्रिक नीति स्वरूप के दो संकेतक मुहैया कराते हैं। वास्तविक ब्याज दरें (वर्तमान मुद्रास्फीति पर आधारित), 4.7 प्रतिशत पर, अधिक हैं हाल ही में पिछले कुछ समय से वे उच्चतम हैं (चित्र 37)<sup>22</sup>। उभरते बाजार-वाले देशों (चित्र 38) की तुलना में ये दरें विशेषरूप से अधिक हैं।

<sup>20</sup> मुद्रास्फीति के ये प्रभाव आर्थिक की बजाय पूरी तरह से सांख्यिकीय हैं।

<sup>21</sup> मौद्रिक नीति समिति के कई सदस्यों द्वारा अस्थायी बनाम स्थायी कारकों के बारे में भिन्न-भिन्न उत्तर दिए गए हैं।

<sup>22</sup> वास्तविक ब्याज दरों की गणना वर्तमान और संभावित मुद्रास्फीति दरों के आधार पर की जा सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान मुद्रास्फीति दरों का प्रयोग ठीक रहेगा।

चित्र 37क. वास्तविक ब्याज दरें ( प्रतिशत )

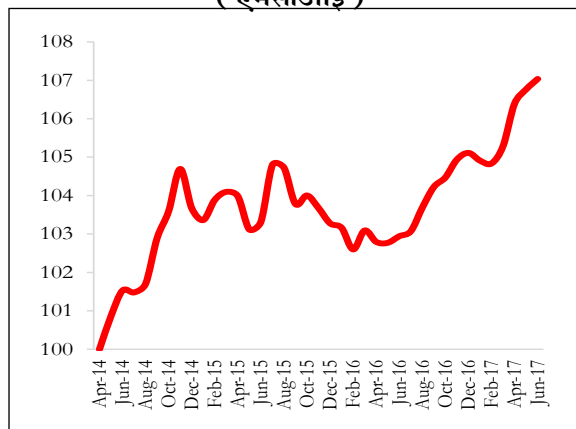


स्रोत: आरबीआई और सर्वेक्षण गणना।

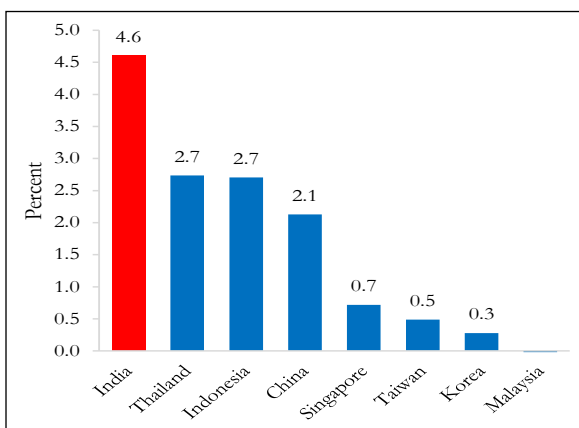
नोट: सांकेतिक रेपो दर से मुद्रास्फीति को घटा कर वास्तविक ब्याज दर प्राप्त किया जाता है;

\*आरबीआई की गणना के अनुसार प्रत्येक महीने के लिए एमसीआई के वास्तविक विनिमय दर ( एक-तिहाई अधिभार और वास्तविक नीतिगत दर में प्रतिशतांक बिन्दु परिवर्तन ( दो तिहाई अधिभार ) में प्रतिशतांक अंतर को जोड़कर, जिसमें अप्रैल 2014 को आधार माना जाए, प्रचार किया जाता है।

चित्र 37ख. वास्तविक मौद्रिक स्थिति सूचकांक ( एमसीआई )\*



चित्र 38. देशवार वास्तविक बांड लाभ

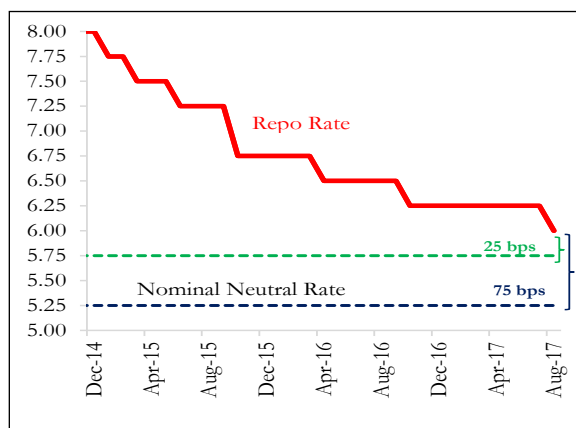


स्रोत: ब्लूमबर्ग

1.151 अन्य संकेतक, वास्तविक मौद्रिक स्थिति<sup>23</sup>—जो विनिमय दरों के परिवर्तन में कारक है, क्योंकि वे घरेलू वस्तु और सेवाओं की विदेशी मांग को प्रभावित करते हैं—भी अनवरत रूप से आगे बढ़ रहे हैं और लम्बे समय से अपने उच्चतम स्तर पर बने हुए हैं (चित्र 37ख)।

1.152 उच्च वास्तविक ब्याज दरें अत्यधिक कठोर नीति के लिए उचित नहीं हैं। आखिरकार, मुद्रास्फीति लक्ष्य-सह-एमसीपी रूपरेखा नई है, और अपनी अनिवार्यता के लिए विश्वसनीयता का वातावरण बना रही

चित्र 39. रेपो दर और सांकेतिक निरपेक्ष दर



स्रोत: आरबीआई, गणना

है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि मुद्रास्फीति को इसके लक्षित स्तर के नजदीक रखा जाए। प्रश्न यह, उठता है कि क्या ब्याज दरों का वर्तमान स्तर स्थिति के अनुसार जरूरी है। आर्थिक सिद्धांत हमें बताते हैं कि यह प्रश्न आर्थिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मोटे तौर पर, यदि चक्रिय स्थितियां मजबूत हैं, वास्तविक ब्याज दरें 'सामान्य' से अधिक होनी चाहिए, यदि स्थितियां कमजोर हैं, तो ब्याज दरें कम होनी चाहिए। परन्तु "सामान्य" क्या है और क्या वर्तमान स्थिति कमजोर या मजबूत है?

<sup>23</sup> जैसे यूरोपीयन सेन्ट्रल बैंक का मासिक बुलेटिन (जून 2002) ऐसे वास्तविक मौद्रिक स्थिति सूची के प्रयोग की तर्कसंगतता बताता है। [www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200206\\_focus03.en.pdf?62fae8f6b163749307cfa99ff6c824d](http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb200206_focus03.en.pdf?62fae8f6b163749307cfa99ff6c824d)



1.153 सामान्य और निष्प्रभावी ब्याज दरें वे हैं जब मुद्रास्फीति लक्ष्य और वास्तविक जीडीपी संभावना के नजदीक हो। निष्प्रभावी दरों को मापना आसान नहीं है परन्तु भारत में भारतीय रिजर्व बैंक से निष्प्रभावी ब्याज दरों के अनेक अनुमान हैं। ये सारणी 8 में दर्शाए गए हैं। मुख्यत, वास्तविक निष्प्रभावी ब्याज दरें लगभग 1.125-1.75 प्रतिशत के आस-पास हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 5.25-5.75 की निष्प्रभावी दरें हैं (4 प्रतिशत लक्षित मुद्रास्फीति को मानते हुए)। आज की दरें 6.00 प्रतिशत या निष्प्रभावी दरों से लगभग 25-75 आधार बिंदु से अधिक होती हैं। (चित्र 39)

1.154 चक्रीय स्थितियां किस प्रकार की होनी चाहिए? तथाकथित, टेलर नियमानुसार, मुख्य संकेतक मुद्रास्फीति अन्तराल है अथवा वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्य तथा उत्पाद अन्तराल से कितनी दूर है और वर्तमान जीडीपी वृद्धि संभावना से कितनी दूर है। यदि अनुमानित मुद्रास्फीति और वृद्धि उनके संतुलन स्तर से अधिक हो, सांकेतिक ब्याज दरें सामान्य, और असामान्य से अधिक होनी चाहिए।

1.155 आऊटलुक विचार-विमर्श से यह सुझाव निकल कर आया है कि अनुमानित मुद्रास्फीति और जीडीपी दोनों अपने संतुलन स्तर से कम हैं। वर्तमान 1.5 प्रतिशत पर मुद्रास्फीति दर 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे चल रही है, घरेलू अर्थव्यवस्था में इसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की क्षमता का अभाव है। उदाहरणार्थ 2016-17 की तीसरी तिमाही में 72.7 प्रतिशत औसत क्षमता उपयोग अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर मंदी का संकेत है।

1.156 चक्रीय स्थितियां, बताती है कि नीति दरें वास्तव में 50-100 के आधार बिंदुओं से कम या-निष्प्रभावी दरों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मौद्रिक कार्यक्षेत्र की सुगमता बहुत अधिक हो, निष्प्रभावी ब्याज दरों के साथ तुलना से अधिक पूर्व की सुगमता, अन्य सुधारपरक कार्रवाई, विशेषकर टीबीएस चुनौतियों से निपटना से अभिप्रेरित अर्थव्यवस्था में तेजी इसकी पूरी संभावना का प्रयोग कर सकेगी।

1.157 इसके अलावा, यह स्मरणीय है कि वास्तविक दरें जो उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए निर्णयों

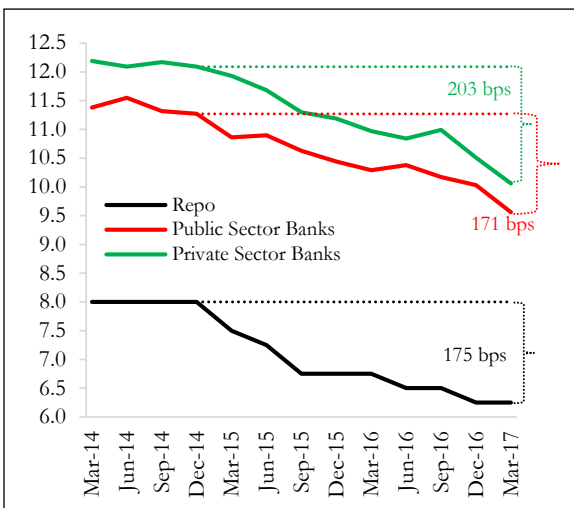
### सारणी 8. भारत में अनिश्चित ब्याज दरों का अनुमान

अध्ययन	मौद्रिक नीति नियमों का प्रकार	अवधि	वास्तविक तटस्थ दर	तटस्थ सांकेतिक दर, 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य सहित	कटौती के लिए स्थान जैसे चालू नीति दरें (6%)
1. कार्यकारी निदेशक का भाषण आरबीआई (2013)	मानक टेलर नियम और सगुमता के साथ टेलर नियम	2012-13Q3	0.5-0.9 प्रतिशत	4.5-4.9 प्रतिशत	110-150 बीपीएस
2. आरबीआई वर्किंग पेपर सं. 05/2015 (2015)	मानक टेलर नियम एवं संरचनात्मक टेलर नियम	2014-15Q4	1.6-1.8 प्रतिशत (मुख्य अनुमान)	5.6-5.8 प्रतिशत	20-40 बीपीएस
3. मीडिया के साथ पश्च नीति आरबीआई सम्मेलन (फरवरी 2015)	...	2014-15	1.5-2 प्रतिशत	5.5-6.0 प्रतिशत	0-50 बीपीएस
4. एमपीसी: मीडिया के साथ पश्च नीति आरबीआई सम्मेलन (अक्टूबर 2016)	...	2016-17Q3	~1.25 प्रतिशत	~5.25 प्रतिशत	~75 बीपीएस

को प्रभावित करती हैं, वार्षिक औसत है, किसी समय विशेष के लिए नहीं। 2016-17 में औसत वास्तविक नीति ब्याज दरें 1.8 प्रतिशत थी। यदि मार्चांत 2018 तक मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत तक पहुंचती है तो 2017-18 के लिए औसत मुद्रास्फीति 3 प्रतिशत होगी। परिणामस्वरूप, औसत वास्तविक नीति दर लक्ष्य मुद्रास्फीति दर के द्वारा सुझाई गई दर से पर्याप्त अधिक रहेगी।

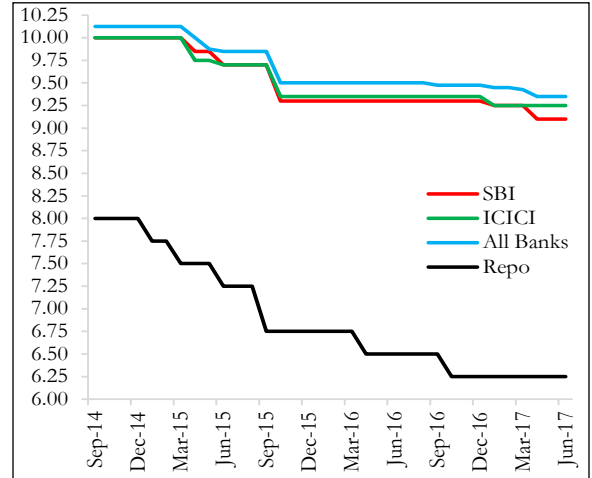
1.158 मौद्रिक सुगमता के विरुद्ध एक तर्क है कि कमजोर पासथ्रू (इससे बाहर निकलना कठिन) है: नीति दर में कटौती करने में क्या परेशानी है यदि ऋण देने की दरें कम नहीं होती हैं? यह सच है कि नीति दर में कटौती के बराबर आधार दरें कम नहीं हुई हैं (80 की तुलना में 175 आधार बिंदु चित्र 40)। परन्तु निजी बैंकों में पासथ्रू सरकारी बैंकों की तुलना में बहुत अधिक हैं, इससे प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त होता है इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। सभी बैंकों के लिए नए ऋणों के निमित्त पासथ्रू (1 अप्रैल 2016 से सभी रुपया ऋण निधियों की आंशिक लागत है, जो आधार भूत ऋण दर से जुड़ा है) अधिक रहा है। चित्र 41 दर्शाता है कि इन ऋणों के देने की दरें नीति दर के बराबर ही गिरी हैं और ये कटौतियां सरकारी क्षेत्र के बैंकों (175 आधार बिंदु) की अपेक्षा निजी बैंकों (200 आधार बिंदु) के लिए अधिक

**चित्र 40. रेपो दर नए रुपया ऋणों पर बैंक समूहवार भारत औसत ऋण दर**



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिकलन

**चित्र 41. रेपो दर और आधार दर (प्रतिशत)**



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिकलन

रही हैं। लघु और मध्यम उद्यमों सहित यह कटौती सभी लेनदारों को लाभ पहुंचाएगी।

1.159 इसके अतिरिक्त, पासथ्रू के अपर्याप्त रहने पर भी, नीति दरों में कटौती करने से वित्तीय स्थिरता के लाभ हैं, क्योंकि ऋण देने की दरों में बराबर गिरावट के बगैर निधियों की लागत में कटौती उनकी लाभप्रदता की बहाली में सहायता करेगी। अपेक्षाकृत कम दरें टीबीएस समस्याओं की प्रक्रिया को भी आसान बनाएगी।

### राजकोषीय नीतियां

1.160 2017-18 के लिए बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रखा गया है, जो तेजी से राजकोषीय समेकन की बजाय लगातार राजकोषीय समेकन को दर्शाता है। यह चयन विकल्प की भावना से है न कि एफआरबीएस समीक्षा समिति रिपोर्ट में प्रस्तावित बहुसंख्यक दृष्टिकोण है (अध्याय 2 में बॉक्स 2 में बहुसंख्यक और वैकल्पिक दृष्टिकोण की तुलना दी गई है)।

1.161 इस वर्ष के लिए राजकोषीय संभावना अनिश्चित है। निचले स्तर के जोखिमों (बजट के समय संभावित से इतर) शामिल हैं:-

- प्रत्याशा से कम अनुमानित वृद्धि से कम कर राजस्व;
- वस्तु एवं सेवा कर पूर्व करों की तुलना में कम वस्तु

एवं सेवा कर दरों के कारण कम वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से परिवर्तनात्मक चुनौतियां;

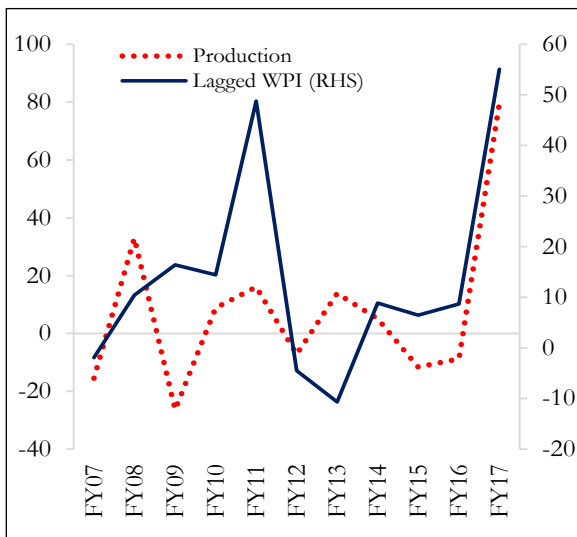
- दहन से संबंधित फर्मों की व्यावहार्यता पर संरचनात्मक झटका के कारण कम स्पेक्ट्रम प्राप्तियां; और
- अनुमानित रु. 30,000 करोड़ पर 7वें वेतन आयोग से अधिक व्यय।

1.162 माल एवं सेवाकर अनुपालन एवं विमुद्रीकरण द्वारा सृजित संभावनाओं, दोनों से अच्छे राजस्व का अनुमान है; तदनुसार प्रतिबद्धताओं के सापेक्ष परिमाण तथा अंतिम समेकन की स्थिति का मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

### अन्य नीतियां

1.163 कृषि दबाव के लिए उपयुक्त नीतिगत अनुक्रिया की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि 2017 अभाव की बजाय अधिशेष का वर्ष है, और कृषि संबंधी आय बढ़ाने के लिए नीतियां बनाना अनिवार्य होगा, 2016 के अनुभव से सीख लेना महत्वपूर्ण है। ऐसी एक सीख सितंबर, 2016 की दाल संबंधी रिपोर्ट<sup>24</sup> में दी गयी है।

**चित्र 42. अरहर का उत्पादन और सुस्त मुद्रास्फीति ( प्रतिशत वर्षानुवर्ष )**



स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कृषि मंत्रालय

क्या कीमतों के प्रति यह कृषकों की प्रतिक्रिया है। एक वर्ष में कम कीमत बुआई और इसके आगे की कीमत को प्रभावित करती है, जो मकड़ा जाल चक्र बनाती है। चित्र 42 तुअर के मामले में इसे रेखांकित करता है जहां पिछले वर्ष प्राप्त कीमत के साथ उत्पादन का बहुत अधिक सह-संबंध है। नीति को मान्यता द्वारा संचालित होना है कि लम्बी अवधि में, किसानों और उपभोक्ताओं के हित के बीच आवश्यक प्रतिपक्ष नहीं होता है; परिलब्धि और स्थिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (और उनकी सहायता के लिए अधिप्राप्ति) तथा निर्यात बाजारों तक पहुंच किसानों को उत्पादन की कमी बेशी और कीमत बढ़ोतरी के जोखिम से बचने में सहायता करती है जो उपभोक्ताओं के लिए दुखदायी होती है।

1.164 अतः किसानों के लिए बेहतर कीमत प्राप्त करने के मार्ग में आड़े आ रही अड़चनें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लगाई गई स्टॉक सीमाएं, निर्यात प्रतिबंध, ई-नेम के कार्यान्वयन में बाधाओं को दूर करना।

1.165 अधिशेष जारी रखने की शर्तें पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम जो, जब बाजार कम सुविकसित थे तक गंभीर दुर्लभता की परिस्थितियों का सामना करने के लिए दशकों पहले अधिनियमित किया गया था, पर पुनर्विचार करने के लिए खूब उपर्युक्त क्षण हो सकता है। यह समय यह करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है कि क्या किसानों को प्रत्यक्ष सहायता करना वर्तमान अप्रत्यक्ष कम प्रभावकारी, अकारगर प्रकार की सहायता की तुलना में कृषि संबंधी आय में वृद्धि करने के लिए कहीं अधिक असरदार उपाय हो सकता है।

## ग. 2016-17 के विकास की समीक्षा

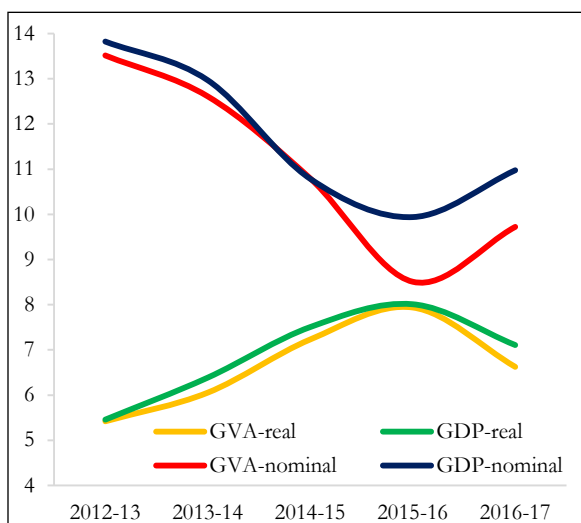
### 1. सकल घरेलू उत्पाद

1.166 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के मई, 2017 अनुमानों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के 8 प्रतिशत के मुकाबले 2016-17 में बढ़कर 7.1 प्रतिशत हो गया। यह निष्पादन आर्थिक समीक्षा खंड 1 में फरवरी में अनुमानित रेंज

<sup>24</sup> “Incentivising Pulses Production Through Minimum Support Price (MSP) and Related Policies”, September 16, 2016 - [http://finmin.nic.in/sites/default/files/Pulses\\_report\\_16th\\_sep\\_2016.pdf](http://finmin.nic.in/sites/default/files/Pulses_report_16th_sep_2016.pdf)

के मुकाबले अधिक रहा (चित्र 43)। इस वृद्धि में यह सुझाव दिया गया है कि अर्थव्यवस्था विमृद्रीकरण से होने वाले बड़े नकदी वर्ष 2016-17 की दूसरी छमाही में नकदी परिचालन 22.6 प्रतिशत हो गया। यह सुस्पष्ट, लचीला, अंकित वृद्धि और अधिक परिमाणवाला

**चित्र 43. वास्तविक और अंकित जीवीए और जीडीपी में वार्षिक वृद्धि**



स्रोत: सीएसओ

रहा चूंकि 2015-16 के मुकाबले अंकित जीवीए और जीडीपी वृद्धि दोनों में 2016-17 में 1 प्रतिशतांक बिंदु से अधिक की वृद्धि हुई।

1.167 अच्छे मानसून के अलावा, जिसमें कृषिगत वृद्धि के साथ सरकार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है (सारणी 9)। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग द्वारा वेतन बढ़ोतरी के प्रभाव को दर्शाता है (सारणी 9)। इन क्षेत्रों ने लगभग कुल जीवीए वृद्धि का एक तिहाई योगदान दिया है, जबकि वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2016 की अवधि में जीवीए वृद्धि में लगभग छठवें हिस्से का योगदान रहा है।

1.168 समुत्थानशीलता का सुझाव देते समय वित्त वर्ष 2017 में कई अन्य संकेतकों के अलावा नवीनतम जीडीपी आंकड़ों में विकास स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। वास्तविक जीडीपी और जीवीए वृद्धि में आवर्ती चार तिमाहियों में गिरावट देखी गई है कृषि, सहबद्ध क्षेत्रों तथा लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाओं को छोड़कर मुख्य जीवीए-कुल जीवीए में वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2017 में 3.6 प्रतिशतांक बिंदु तक गिरावट

**सारणी 9. मूल्य वर्द्धित और जीडीपी में वृद्धि ( प्रतिशत, स्थिर कीमतें )**

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कृषि, वानिकी व मत्स्यपालन	5.6	-0.2	0.7	4.9
खनन व विनिर्माण	0.2	11.7	10.5	1.8
विनिर्माण	5.0	8.3	10.8	7.9
विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	4.2	7.1	5.0	7.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार आदि	6.5	9.0	10.5	7.8
वित्तीय, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाएं	11.2	11.1	10.8	5.7
लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य	3.8	8.1	6.9	11.3
जीवीए	6.1	7.2	7.9	6.6
कोर जीवीए	6.6	9.0	9.8	6.2
जीडीपी	6.4	7.5	8.0	7.1

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन एवं सर्वेक्षण परिकल्पन

टिप्पणी: कोर जीवीए = कृषि एवं सहबद्ध तथा सरकारी प्रशासन, रक्षा व अन्य का जीवीए

देखी गई (सारणी 9) और वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही से वित्त वर्ष 17 की चौथी तिमाही के बीच 6.8 प्रतिशतांक बिन्दु की गिरावट देखी गई (चित्र 44 तथा 45)। विनिर्माण जीवीए वृद्धि वित्त वर्ष 2016 की चौथी तिमाही से कम होना शुरू हुई और नई तथा संशोधित आईआईपी संख्या में वही गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई (चित्र 46)।

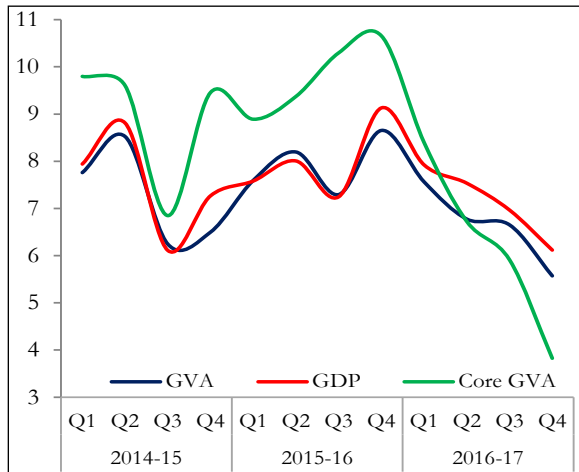
1.169 वास्तविक जमा निवेश में वृद्धि वित्त वर्ष 2013 की दूसरी छमाही से ही कम थी तथा वित्त वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में अस्थायी प्रयास के पश्चात से इसमें

तेजी से गिरावट आई, बाद में सार्वजनिक निवेश से कुछ हद तक सुधार हुआ। (चित्र 47 एवं 48)। 2016-17 में निजी निवेश में वृद्धि ऋणात्मक रही केवल खपत से मांग में उछाल आया जो वित्त वर्ष 2017 में जीडीपी वृद्धि का लगभग 96 प्रतिशत बैठता है।

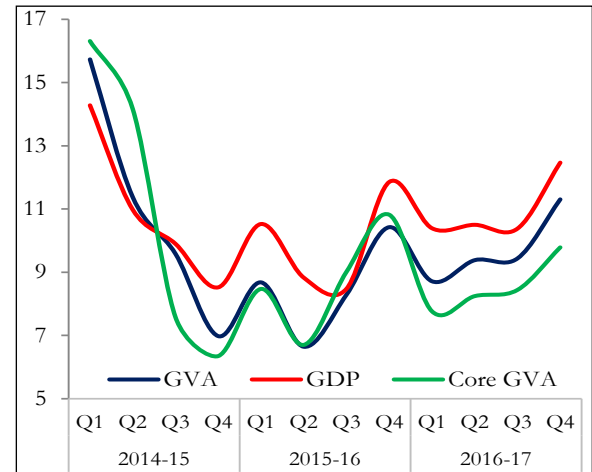
## 2. मुद्रास्फीति

1.170 अधिक से कम मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था नाटकीय संक्रमण के दौर से गुजर रही है (देखें: नीचे खण्ड); 2014-15 में वार्षिक औसत मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत थी तथा वित्त वर्ष 2017 में कम होकर यह

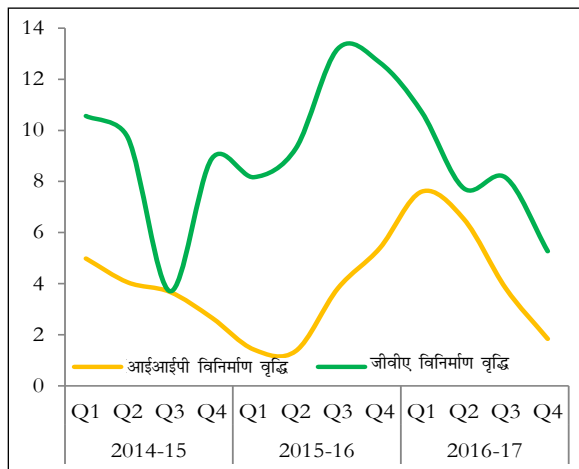
**चित्र 44. जीवीए एवं जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत में स्थिर कीमतों)**



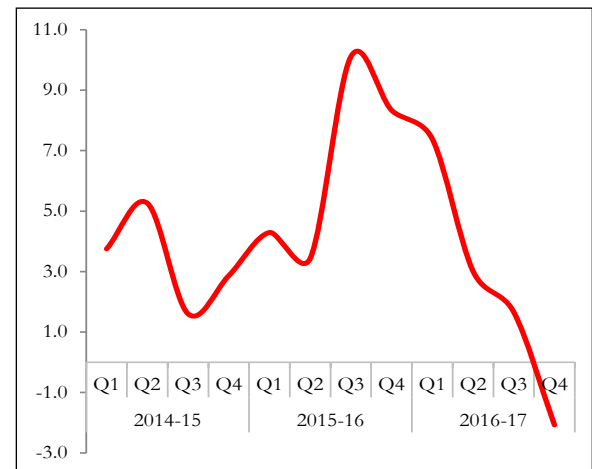
**चित्र 45. जीवीए एवं जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत में वर्तमान कीमतों)**



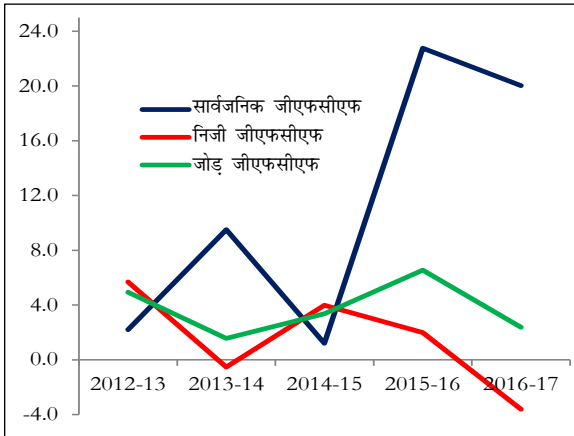
**चित्र 46. विनिर्माण में वृद्धि (प्रतिशत में)-जीवीए तथा आईआईपी**



**चित्र 47. स्थिर कीमतों पर जीएफसीएफ वृद्धि**



चित्र 48. निर्धारित पूंजी निर्माण में वृद्धि  
( प्रतिशत, स्थिर कीमतें )

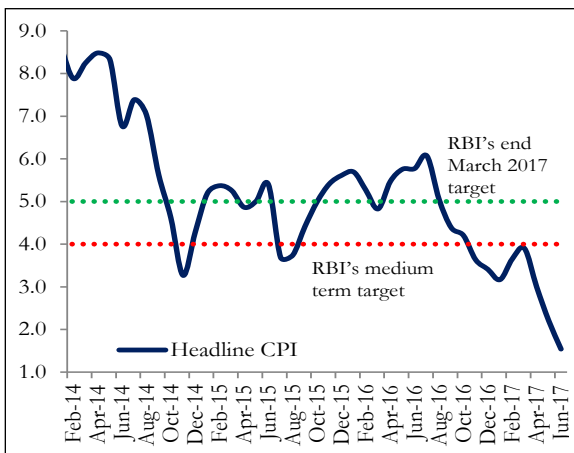


आंकड़ों के स्रोत: सीएसओ, आरबीआई एवं सर्वेक्षण गणना

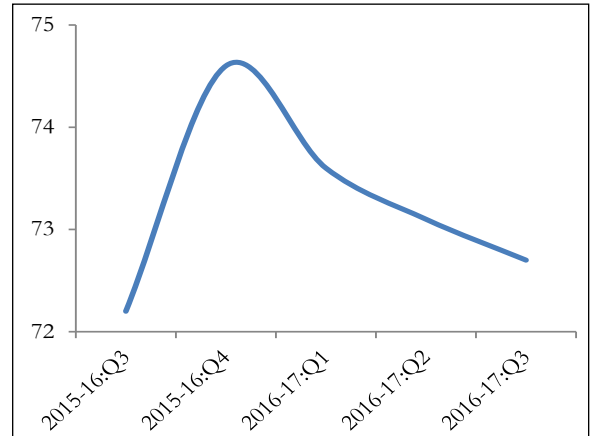
4.5 प्रतिशत पर आ गई है। 2016-17 में कई नाटकीय घटनाक्रम हुए। आंशिक रूप से वृद्धि में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति जुलाई, 2016 में 6.1 प्रतिशत से कम होकर जून 2017 में 1.5 प्रतिशत पर आ गई। मुख्य रूप से दालों तथा सब्जियों के दाम अधिक होने के कारण वित्त वर्ष 2017 के पहले कुछ मासों में खाद्य मंहगाई ऊंची रही लेकिन बाद में मौसमी उपलब्धता में सुधार और खासकर विमुद्रीकरण के पश्चात इसमें सुधार हुआ।

1.171 हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 10 क्रमिक मासों में कम होकर भारतीय रिजर्व बैंक के 2017 के लक्ष्य से नीचे अर्थात् लगभग 1.7 प्रतिशतांक बिंदु पर आ गई थी (चित्र 50)। केवल हेडलाइन ही नहीं बल्कि रिफाइन्ड कोर मुद्रास्फीति, जो कृषि; परिवहन सेवाओं में तेल तथा

चित्र 50. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति  
( प्रतिशत )



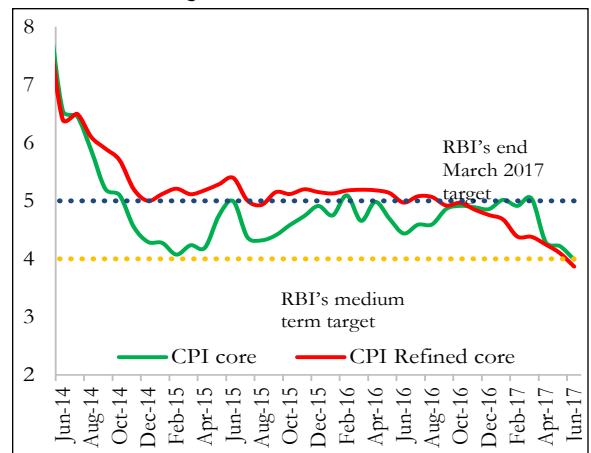
चित्र 49. विनिर्माण में क्षमता उपयोग  
( प्रतिशत )



तेल घटक को पृथक करती है, तेजी से कम होकर जून, 2016 में 5 प्रतिशत से जून 2017 में 3.9 प्रतिशत पर आ गई। (चित्र 51)

1.172 वित्त वर्ष 2015 के अंत में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई और समूचे वित्त वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक उपभोक्ता वस्तु कीमतों में गिरावट जारी रही। वैश्विक उपभोक्ता वस्तु कीमतों तथा आधार प्रभाव ('बेस एफेक्ट') (गत वर्ष कम मुद्रास्फीति) में उछाल से वित्त वर्ष 2017 के दौरान थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि हो गई। फुटकर एवं थोक मुद्रास्फीति में अन्तर की भिन्नता से अन्य बातों के साथ-साथ खासतौर से वित्त वर्ष 2016 में राष्ट्रीय लेखों में गंभीर खामियां मिली; जो अब दूर हो गई हैं। (चित्र 52) (परिशिष्ट 3)

चित्र 51. कोर एण्ड रिफाइन्ड कोर सीपीआई  
मुद्रास्फीति ( प्रतिशत )



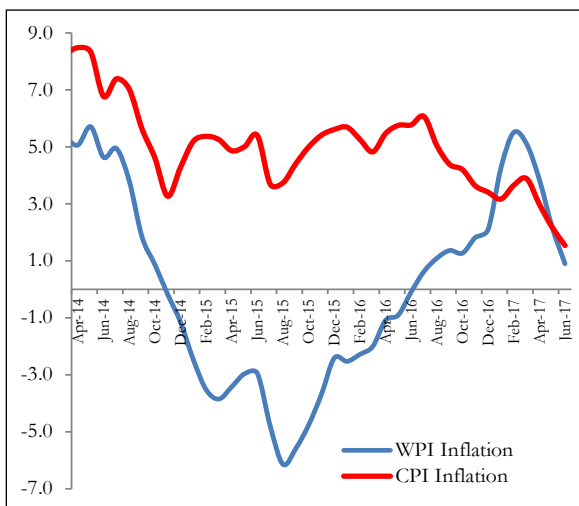
में एक स्थान पर संक्षेप में यह बताया गया है कि प्रयुक्त संकेतकों एवं अपस्फीतिकारी तथा सामान्य एवं वास्तविक परिकलन को स्पष्ट करते हुए प्रमुख उपक्षेत्रों में से प्रत्येक में किस प्रकार राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए जाते हैं।)

### वैदेशिक क्षेत्र

1.173 व्यापारी माल तथा सुदृढ़ पूंजी प्रवाह में जो प्रतिलाभ धीरे-धीरे प्रत्यक्ष हो रहे हैं उससे बाह्य स्थिति भी सुदृढ़ होती प्रतीत हो रही है जिसे अन्य बातों सहित बढ़ते आरक्षित भंडार तथा मजबूत होती विनिमय दर में भी देखा जा सकता है।

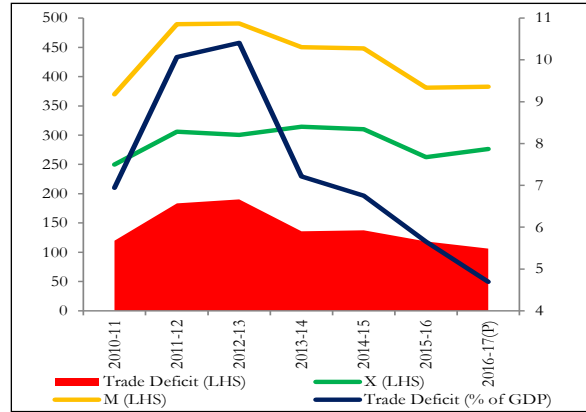
1.174 व्यापार घाटे में तीव्र संकुचन निवल अदृश्य में गिरावट को भी पार कर गया जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा विगत वर्ष के जीडीपी का 1.1 प्रतिशत घटकर 2016-17 में जीडीपी का 0.7 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 53 एवं 54)। निवल सेवाओं तथा निवल निजी अंतरणों दोनों में ही गिरावट के कारण निवल अदृश्य प्राप्तियां 97.1 बिलियन अमरीकी डॉलर पर वित्तीय वर्ष 2017 में 10 प्रतिशत तक गिर गईं। स्रोत देशों विशेषकर खाड़ी क्षेत्रों में मंद गतिविधि ने काफी हद तक भारत में निवल प्रेषणों के प्रवाह को कम कर दिया है जो 2015-16 में 63.1 बिलियन अमरीकी डॉलर था 2016-17 में घटकर

**चित्र 52. डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति एवं सीपीआई मुद्रास्फीति**

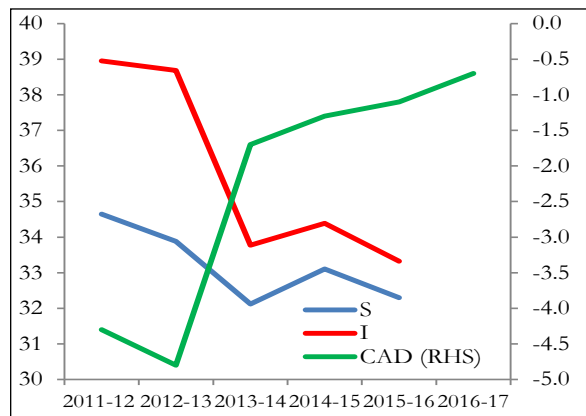


स्रोत: एमओएसपीआई

**चित्र 53. निर्यात एवं आयात ( बिलियन अमरीकी डॉलर में ) तथा व्यापार संतुलन ( बिलियन अमरीकी डॉलर तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में )**



**चित्र 54. बचत ( एस ) एवं निवेश ( आई ) दर तथा चालू खाता घाटा ( सीएडी ) जीडीपी के प्रतिशत के रूप में**



56.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।

1.175 दो वर्षों के अंतराल के पश्चात् निर्यात ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है वहीं दूसरी ओर आयात संकुचित होकर कम हो गया है जिसके कारण भारत का व्यापार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में 6.2 प्रतिशत (130.1 बिलियन अमरीकी डॉलर) से घटकर जीडीपी का 5.0 प्रतिशत हो गया (112.4 बिलियन अमरीकी डॉलर)। कई तिमाहियों के पश्चात् निर्यात फरवरी 2016 से निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज कर रहा है जबकि आयात में सकारात्मक वृद्धि अक्टूबर 2016 से देखने को मिली है। अगस्त 2016 से सोने का आयात बढ़ गया है जो संभवतः जीएसटी के तहत सोना एवं आभूषण पर लगने वाले कर में अपेक्षित वृद्धि से

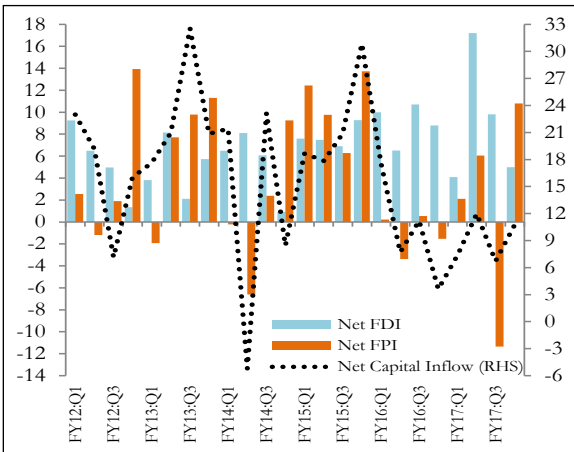


पूर्व जौहरियों द्वारा खरीद को दर्शाता है। (चित्र 60)।

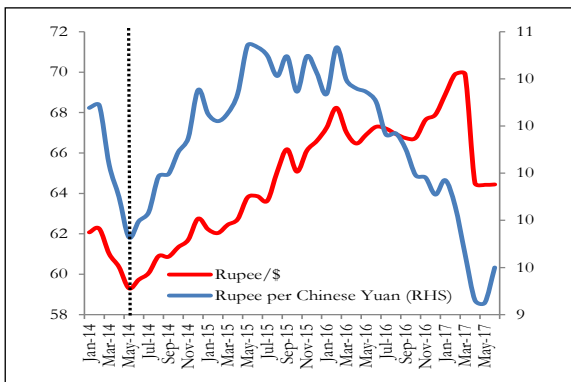
1.176 मुख्यतः प्रवासी भारतीय जमा में गिरावट के कारण विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017 में निवल पूंजी प्रवाह पिछले वर्ष जीडीपी 1.9 प्रतिशत (40.1 बिलियन अमरीकी डालर) से कुछ हद तक घटकर जीडीपी का 1.6 प्रतिशत (36.8 बिलियन अमरीकी डालर) हो गया जो विगत 2016 में एफसीएनआर (बी) की बड़ी वापसी को दर्शाता है (चित्र 55)। हालांकि निवल विदेशी मुद्रा भंडार वित्तीय वर्ष 2017 में 35.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर सुदृढ़ रहा तथा चालू खाता घाटे को भी पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करता रहा।

1.177 पूंजी खाता अधिशेष के चालू खाता घाटे से अधिक होने ने भंडार संचयन (भुगतान शेष आधार पर)

चित्र 55. पूंजी प्रवाहों के मुख्य घटकों की प्रवृत्ति ( बिलियन अमरीकी डॉलर में )

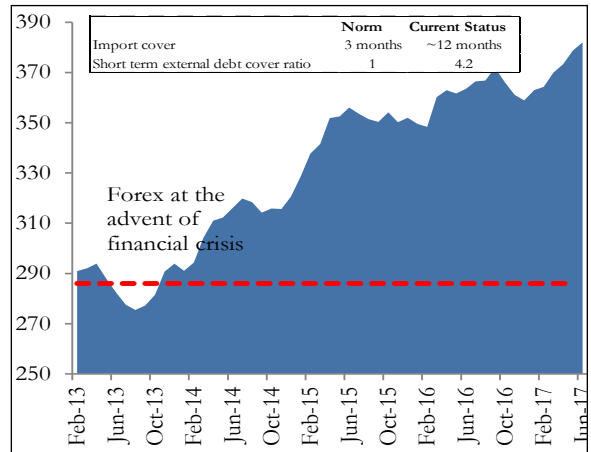


चित्र 57. विनिमय दर: रुपया डालर एवं रुपया युआन

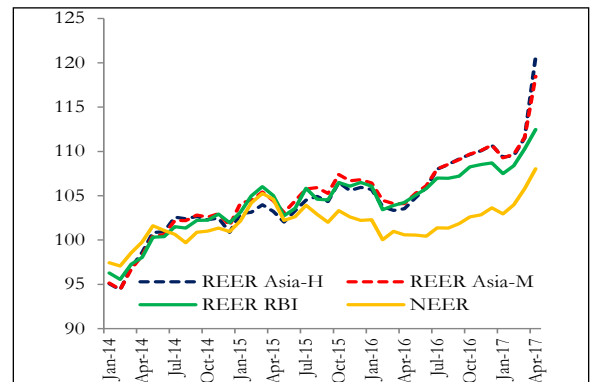


को 2016-17 में 21.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक बढ़ा दिया जो वित्तीय वर्ष 2016 की 17.9 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि की तुलना में अधिक था। मार्च 2016 की समाप्ति की तुलना में मार्च 2017 की समाप्ति में विदेशी मुद्रा भंडार 360.2 बिलियन से बढ़कर 370 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। (चित्र 56)। अप्रैल 2017 की समाप्ति तक विदेशी मुद्रा भंडार 13.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि के साथ 386.4 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर तक पहुंच गया जो बढ़े हुए भंडार को दर्शाता है। परिणामस्वरूप अधिकतम भंडार आधारित बाह्य क्षेत्रों के प्रवणता सूचक बेहतर हो गए हैं। व्यापक अग्रवर्ती बाजार हस्तक्षेप (जिसे सफलतापूर्वक निष्कीरित कर दिया गया) विमुद्रीकरण के

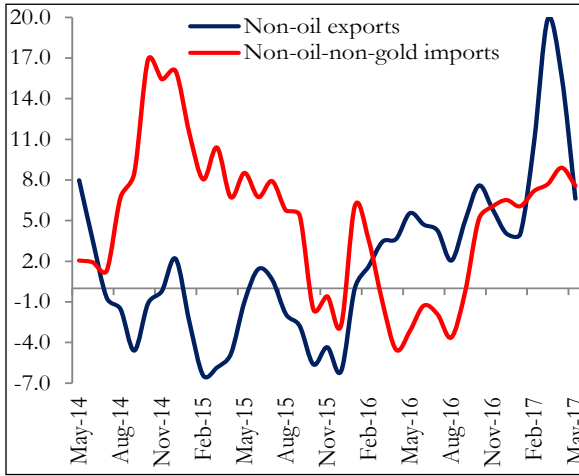
चित्र 56. विदेशी मुद्रा भंडार ( बिलियन अमरीकी डॉलर में )



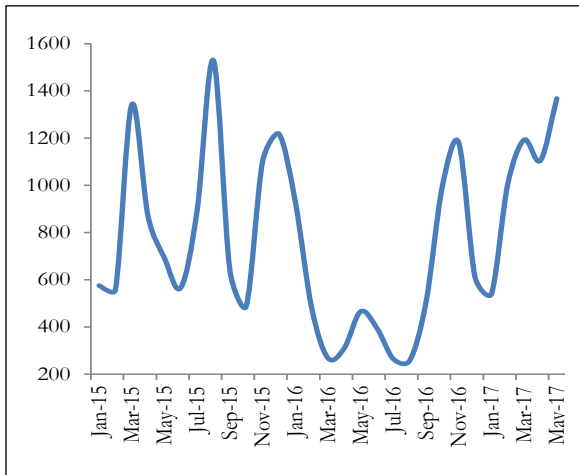
चित्र 58. अंकित प्रभावी विनिमय दर एवं वास्तविक प्रभावी विनिमय दर: ( 2014=100 )



**चित्र 59. निर्यात तथा आयात वृद्धि ( प्रतिशत )  
( 3 माह का चल औसत )**

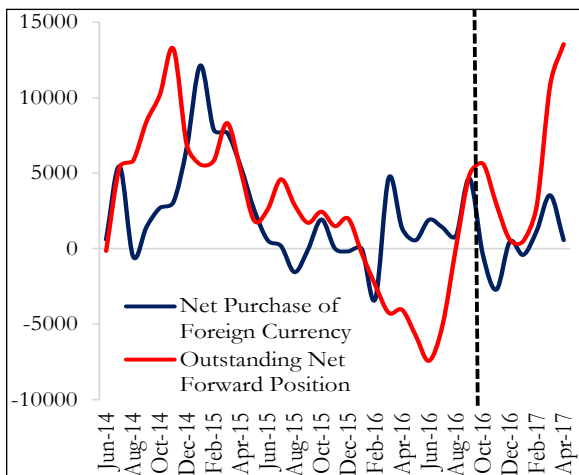


**चित्र 60. स्वर्ण आयात ( .00 किग्रा. )**



चित्रों के स्रोत: आरबीआई, सीएसओ, डीजीसीआईएस तथा सर्वेक्षण गणना

**चित्र 61. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री एवं खरीद ( मिलियन अमरीकी डॉलर, हजार )**



परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिक नकदी के प्रबंध की ओर किए गए प्रयत्न को दर्शाता है।

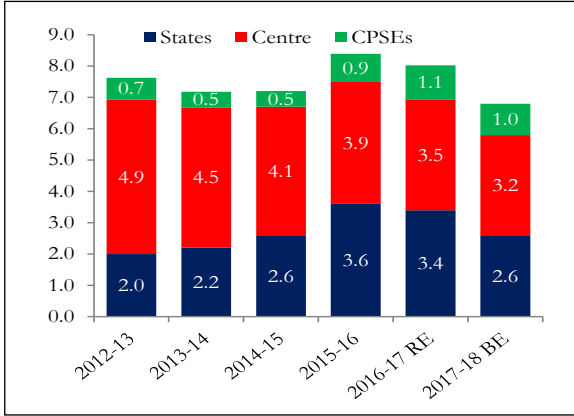
1.178 अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों जिसने विश्व भर में बड़े पैमाने पर मुद्राओं के मूल्यहास को जन्म दिया, तथा इससे उपजी अनिश्चितता का भारतीय रुपए पर क्षणिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। विश्वव्यापी जोखिम के कम होने के कारण शेयर समूह (पोर्टफोलियो) प्रवाह ने सकारात्मक रुख अपना लिया, इससे अमरीकी नीतियों की अवधारणा में बदलाव आ गया, उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) चुनावों के परिणामस्वरूप सरकारी नीतियों के प्रति विश्वास जागृत हुआ तथा राजनैतिक स्थिरता आई इन्हीं सब कारणों के परिणामस्वरूप दिसम्बर 2016 से रुपए का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है तथा फरवरी 2017 से यह और मजबूत हो गया है। वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान रुपया ₹65.9 से ₹68.1 प्रति अमरीकी डॉलर के स्तर पर स्थिर रहा तथा 2015-16 से 2016-17 के मध्य औसतन 2.4 प्रतिशत ही रुपए का मूल्य घटा है। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संबंध में रुपए के मूल्य का बढ़ना निर्यात के कुछ हद तक कम प्रतिस्पर्धात्मक होने को दर्शाता है (चित्र 58)। चीनी युआन के हास के कारण एशियाई मुद्राओं की तुलना में रुपए की मूल्यवृद्धि का परिमाण कहीं अधिक है। (चित्र 57)।

#### iv. राजकोषीय घटनाक्रम

1.179 सातवें वेतन आयोग तथा डिफेंस वन रैंक वन पेंशन स्कीम के कार्यान्वयन के कारण व्यय संबंधी दबाव के बावजूद केन्द्रीय बजट 2017-18 राजकोषीय स्थिति को समेकित करने की दृष्टि से लक्षित था। वर्ष के अंत में सरकार ने राजकोषीय घाटे के अपने लक्ष्य को बनाये रखा (चित्र 62), जबकि स्पेक्ट्रम नीलामी तथा विनिवेश प्राप्तियां लक्ष्य से कम रहीं।

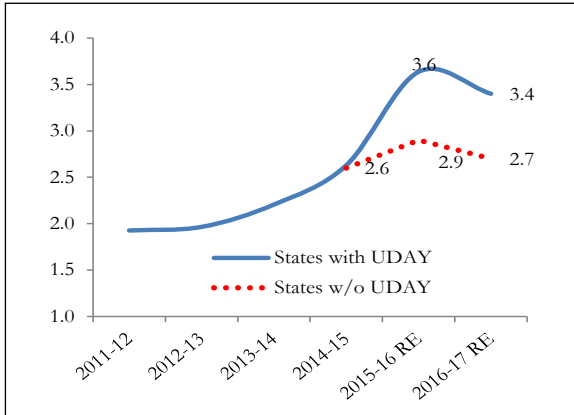
1.180 वित्त वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार का समग्र राजकोषीय परिणाम राजस्व कर में वृद्धि और पेट्रोलियम पर उत्पाद कर से प्राप्त राजस्व से गैर-वेतन तथा पेंशन राजस्व व्यय तथा उधार के समेकन से सुदृढ़ रहा। उत्पाद कर तथा सेवा कर से अतिरिक्त कर संसाधन जुटाने के प्रयास से विगत दो वर्षों में कर संग्रह में वृद्धि से पर्याप्त

चित्र 62. केन्द्र, राज्य तथा सीपीएसई से उधार (जीडीपी का प्रतिशत)



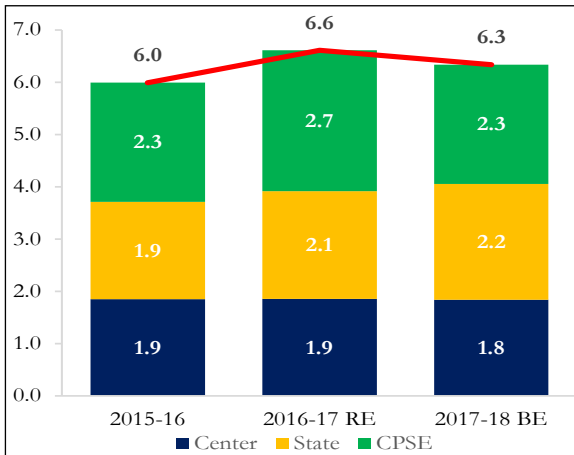
स्रोत: केन्द्र तथा राज्यों के बजट, भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 63. राज्यों का राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

चित्र 64. केन्द्र, राज्य और सीपीएसई द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय (प्रतिशत जीडीपी)



स्रोत: सर्वेक्षण गणना

मदद मिली। स्वच्छ भारत कर तथा कृषि कल्याण कर से संग्रह सेवा कर संग्रह में वृद्धि का एक तिहाई बैठता है। पेट्रोलियम पदार्थों से संग्रह में वृद्धि कुल उत्पाद कर संग्रह में वृद्धि की दो-तिहाई से अधिक रही।

1.181 विगत 2 वर्षों में उदय कार्यक्रम के अन्तर्गत डिस्काम परिकल्पित देयताओं को दर्शाते हुए हाल के वर्षों में राज्यों की घाटे की स्थिति क्रमशः कम रही है। वित्त वर्ष 2016 के दौरान राज्यों का संचित राजकोषीय घाटा लगभग 1 प्रतिशतांक बिंदु तक घट गया (चित्र 63)। बहरहाल, उदय (UDAY) को शामिल करते हुए राज्य का संचित राजकोषीय घाटा 0.2 प्रतिशतांक बिंदु तक संतुलित रहा अर्थात् जीडीपी के 3.6 प्रतिशत से 3.4 प्रतिशत तक यूडीएवाई बान्ड वित्त वर्ष 2016 तथा वित्त वर्ष 2017 में अनुमानतः 0.7 प्रतिशत बैठते हैं।

1.182 2016-17 में सीपीएसई द्वारा किए गए तीव्र प्रयासों की पृष्ठभूमि में केन्द्र, राज्य तथा सीपीएसई द्वारा किए गए प्रयासों से सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी हुई (चित्र 64)। सर्वेक्षण परिकलन से पता चलता है कि सार्वजनिक निवेश वृद्धि के ऊंचे स्तर के बावजूद निर्धारित निवेश दर में गिरावट अविश्वसनीय बनी रही (चित्र 50)। जीडीपी की तुलना में सरकार का निवेश खर्च 2017-18 में कम होने की संभावना है।

1.183 केन्द्रीय बजट 2017-18 में कई प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं। प्रथमतः रेलवे बजट की 1924 से जारी परिपाटी को पीछे छोड़ते हुए इसे केन्द्रीय बजट के साथ जोड़ा गया, और इस प्रकार रेलवे की वित्त बजट व्यवस्था को मुख्य धारा में लाया गया। दूसरे केन्द्रीय बजट को 1 फरवरी को पेश किया गया लगभग एक माह पूर्व, ताकि केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को वित्त वर्ष के आरंभ से अपना पूरा बजट खर्च कर सकें, जबकि पहले बजट को विधायी स्वीकृति के लिए वित्त वर्ष में पर्याप्त (मई-अंत) इंतजार करना पड़ता था। तीसरे आर्थिक रूप से और अधिक लाभप्रद पूंजी राजस्व भिन्नता पर ध्यान देने की दृष्टि से 'आयोजना' एवं 'आयोजना-भिन्न' व्यय के वर्गीकरण को समाप्त किया गया। चौथे बहुवर्षीय बजट व्यवस्था के अग्रदूत

के रूप में मध्यावधि व्यय ढांचा विवरण का पुनर्गठन किया गया ताकि आगामी दो वित्तीय वर्षों की प्रत्येक मांग हेतु अनुमानित व्यय (राजस्व तथा पूंजीगत) का ब्यौरा दिया जा सके।

1.184 केन्द्रीय बजट 2017-18 में स्थिर समेकन के मार्ग का चयन किया गया। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2017 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5 प्रतिशत के परिणाम की तुलना में वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा कम होकर जीडीपी के 3.2 प्रतिशत पर आ जाने की संभावना

है। केन्द्र सरकार द्वारा अंगीकृत समेकन मार्ग ने प्रतिस्पर्धी उद्देश्यों में विवेकपूर्ण ढंग से संतुलन कायम किया है। एक तरफ तो चक्रिय रूप से कमजोर होती अर्थव्यवस्था जो दोहरे तुलनपत्र की समस्या से ग्रस्त थी तथा जो निवेश और ऋणवृद्धि में गिरावट में दिखाई दी, की जरूरतें थीं जिनके लिए प्रति चक्रिय नीति अपनाने के पक्ष में दलील दी जा सकती है और दूसरी ओर विशेषकर राज्य सरकार के वित्त साधनों पर सम्भावित अड़चनों को देखते हुए विश्वसनीयता बनाए रखने की आवश्यकता ने समेकन को जारी रखना जरूरी बना दिया।

## परिशिष्ट 1. किसान ऋणग्रस्तता: मूलभूत तथ्य

कृषि ऋण की मात्रा और वितरण से संबंधित जानकारी क्या है?

इस प्रश्न के उत्तर के लिए वर्ष 2012-13 के राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण कार्यालय के कृषि से संबंधित परिवारों की स्थिति के आंकलन सर्वेक्षण का सहारा लेना है, जो बकाया कृषि ऋण की संरचना का विस्तृत आंकलन प्रस्तुत करता है<sup>22</sup>।

कृषि से जुड़े हुए परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि किसी परिवार को 3000 रुपए से अधिक वार्षिक उत्पाद मूल्य कृषि गतिविधियों-संबद्ध गतिविधियां भी इसमें शामिल हैं- से प्राप्त होता है और परिवार के कम से कम एक सदस्य ने कृषि को मुख्य रूप से अथवा गौण रूप से पिछले 365 दिनों में अपने रोजगार के रूप में अपनाया है।

नीचे दी गई सारणी-1 और 2 में वर्ष 2016-17 में राज्य द्वारा दिए गए कृषि ऋण के अनुमान और भूमिधारिता का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए इंगित संख्या वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान की अवधि की सीपीआई मूल्यवृद्धि द्वारा इनफ्लेट किया गया है। कुछ तथ्य इसमें शामिल नहीं हैं।

समग्र रूप से भारत के संबंध में कुल कृषि ऋण लगभग 5.5 लाख करोड़ का है, जिसमें से 3.25 लाख करोड़ (60 प्रतिशत) औपचारिक संस्थाओं द्वारा दिया गया है और शेष अनौपचारिक संस्थाओं द्वारा दिया गया है। लगभग 2.4 लाख करोड़ अथवा कुल औपचारिक ऋण का लगभग 75 प्रतिशत छोटे किसानों (जिनकी भूधारिता 2.5 हेक्टेयर से कम है) का है। लेकिन समस्त अनौपचारिक ऋणों का 85 प्रतिशत भी छोटे किसानों का है। बड़े किसानों, जिनके पास कुल अनौपचारिक ऋणों का केवल 25 प्रतिशत है, की तुलना में छोटे किसान प्रायः अनौपचारिक क्षेत्र का सहारा लेते हैं।

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान अधिक मात्रा में औपचारिक क्षेत्र कृषि ऋण वाले (पूर्णरूप से) राज्य हैं। शायद यह आश्चर्य की बात है कि पंजाब और हरियाणा उच्चतम कृषि ऋण वाले राज्यों में शामिल नहीं हैं। हालांकि, केरल और आंध्र प्रदेश के साथ, पंजाब का कृषि ऋण स्तर जीएसडीपी की तुलना में उच्च है।

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना उच्चतम रूप से अनौपचारिक कृषि ऋण परिचालन करने वाले राज्य हैं। औसतन रूप से कम विकसित राज्यों में उच्चतर मात्रा में अनौपचारिक क्षेत्र ऋण की प्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, इन चार राज्यों में अनौपचारिक ऋण एक लाख करोड़ के नजदीक है जो किसानों की समग्र ऋणग्रस्तता का 56 प्रतिशत बैठता है। सरकारी ऋण माफी के बावजूद अधिसंख्यक किसान ऋणी बने रहेंगे।

<sup>25</sup> भारतीय रिजर्व बैंक वैकल्पिक एवं और अधिक अद्यतन आंकड़ों का स्रोत है लेकिन यह फॉर्म साइज अनौपचारिक क्षेत्र उधार अभिग्रहण से पृथक नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि ऋण संबंधी संख्या एनएसएसओ अध्ययन से प्राप्त संख्या से अधिक है क्योंकि एनएसएसओ गणना नमूना आधारित है। तथापि आर्थिक समीक्षा 2014-15 में किए गए विचार विमर्श के अनुसार अध्ययन 5, बॉक्स 5.2, क आरबीआई का वास्तविक हिस्सा-परिभाषित कृषि संबंधी ऋण क्षेत्र में परिदृष्ट नहीं होते हैं।

परिशिष्ट सारणी 1

वर्ष 2016-17 के लिए भू-धारिता आकार द्वारा अनुमानित बकाया ऋण और ऋण का स्रोत ( करोड़ रुपये में )

	भूमिहीन और छोटा किसान			मध्यम			बड़ा			कुल योग		
	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल
उत्तर प्रदेश	32,246	24,061	56,308	5,376	356	5,732	1,662	111	1,773	39,284	24,529	63,813
आंध्र प्रदेश	18,727	25,872	44,599	3,439	3,949	7,388	2,986	2,556	5,542	25,152	32,377	57,529
तमिलनाडु	26,649	16,619	43,269	3,144	682	3,826	1,380	250	1,631	31,174	17,552	48,726
राजस्थान	14,948	27,597	42,544	6,221	2,649	8,870	4,626	3,215	7,841	25,795	33,461	59,255
कर्नाटक	24,949	16,230	41,179	4,943	2,773	7,716	3,815	737	4,552	33,706	19,740	53,447
केरल	32,529	3,901	36,429	1,900	32	1,932	407	53	461	34,835	3,986	38,821
महाराष्ट्र	22,292	8,352	30,645	8,426	2,129	10,554	7,777	1,372	9,149	38,495	11,853	50,348
तेलंगाना	9,075	17,925	27,000	991	1,565	2,556	555	642	1,197	10,620	20,133	30,753
मध्य प्रदेश	9,094	7,627	16,720	4,064	1,693	5,756	1,951	528	2,480	15,109	9,848	24,957
ओडिशा	4,811	10,020	14,830	1,009	22	1,030	419	161	579	6,238	10,202	16,440
बिहार	3,912	10,511	14,423	295	63	358	129	100	229	4,336	10,675	15,010
पश्चिम बंगाल	8,295	6,034	14,329	116	50	166	107	41	148	8,518	6,125	14,643
पंजाब	8,167	4,480	12,647	5,643	1,183	6,825	1,829	522	2,351	15,638	6,185	21,823
हरियाणा	9,023	3,588	12,611	1,526	1,192	2,718	605	141	746	11,154	4,922	16,075
गुजरात	8,707	3,586	12,293	3,766	438	4,204	2,905	19	2,925	15,378	4,044	19,422
उत्तराखंड	3,522	639	4,161	331	4	335	228	165	393	4,081	808	4,889
हिमाचल प्रदेश	2,548	485	3,033	74	8	83	58	28	87	2,681	522	3,202
छत्तीसगढ़	1,762	1,242	3,004	284	35	319	71	2	73	2,116	1,280	3,396
झारखंड	416	1,173	1,588	37	6	43	5	-	5	458	1,178	1,636
कुल	41,670	189,942	31,612	51,583	18,829	70,412	31,515	10,645	42,160	324,768	219,417	544,185

स्रोत: कृषि परिवारों के संबंध में स्थिति आंकलन सर्वेक्षण से संबंधित यूनिट स्तर डाटा से अनुमानित

टिप्पणी: ( 1 ) भूधारिता श्रेणी "खुद की ज़मीन" और इसमें वासभूमि भी शामिल है, पर आधारित है।

( 2 ) वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान वर्ष 2012-13 की संख्या पर आधारित है। वर्ष 2012-13 की संख्या सीपीआई मूल्यवृद्धि से इनफ्लैटेड है।

( 3 ) औपचारिक ऋण में बैंकों, सहकारी समितियों और सरकार से प्राप्त ऋण शामिल हैं।

परिभाषा भूमि का आकार

भूमिहीन और छोटा - 2.5 हेक्टेयर तक

मध्यम - 2.5-5.5 हेक्टेयर

बृहद् - >5.5 हेक्टेयर

## परिशिष्ट सारणी 2

वर्ष 2016-17 के लिए भू-धारिता आकार द्वारा अनुमानित बकाया ऋण और ऋण का स्रोत (2017-18 जीएसडीपी का %)

	भूमिहीन और छोटा किसान			मध्यम			बड़ा			कुल योग		
	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल	औपचारिक	अनौपचारिक	कुल
उत्तर प्रदेश	2.3	1.7	4.0	0.4	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	2.8	1.7	4.5
आंध्र प्रदेश	2.4	3.4	5.8	0.4	0.5	1.0	0.4	0.3	0.7	3.3	4.2	7.5
तमिलनाडु	1.8	1.1	2.9	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	2.1	1.2	3.2
राजस्थान	1.8	3.3	5.1	0.8	0.3	1.1	0.6	0.4	0.9	3.1	4.0	7.2
कर्नाटक	1.9	1.3	3.2	0.4	0.2	0.6	0.3	0.1	0.4	2.6	1.5	4.2
केरल	4.3	0.5	4.9	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	4.7	0.5	5.2
महाराष्ट्र	0.9	0.3	1.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4	1.5	0.5	2.0
तेलंगाना	1.2	2.4	3.6	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	1.4	2.7	4.1
मध्य प्रदेश	1.2	1.0	2.3	0.6	0.2	0.8	0.3	0.1	0.3	2.1	1.3	3.4
ओडिशा	1.2	2.4	3.6	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	1.5	2.5	4.0
बिहार	0.6	1.7	2.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.4
पश्चिम बंगाल	0.8	0.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	1.4
पंजाब	1.6	0.9	2.5	1.1	0.2	1.4	0.4	0.1	0.5	3.1	1.2	4.3
हरियाणा	1.5	0.6	2.0	0.2	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1	1.8	0.8	2.6
गुजरात	0.7	0.3	1.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	1.2	0.3	1.5
उत्तराखंड	1.6	0.3	1.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	1.8	0.4	2.2
हिमाचल प्रदेश	1.8	0.3	2.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	1.9	0.4	2.3
छत्तीसगढ़	0.6	0.4	1.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	1.2
झारखंड	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.2	0.4	0.5
कुल	1.5	1.2	2.7	0.3	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3	2.0	1.4	3.4

स्रोत: कृषि परिवारों के संबंध में स्थिति आंकलन सर्वेक्षण से संबंधित यूनिट स्तर डाटा से अनुमानित

टिप्पणी: (1) भूधारिता श्रेणी "खुद की ज़मीन" और इसमें वासभूमि भी शामिल है, पर आधारित है।

(2) वर्ष 2016-17 के लिए अनुमान वर्ष 2012-13 की संख्या पर आधारित है। वर्ष 2012-13 की संख्या सीपीआई मूल्यवृद्धि से इन्फ्लैटेड है।

(3) औपचारिक ऋण में बैंकों, सहकारी समितियों और सरकार से प्राप्त ऋण शामिल हैं।

परिभाषा भूमि का आकार

भूमिहीन और छोटा - 2.5 हेक्टेयर तक

मध्यम - 2.5-5.5 हेक्टेयर

बृहद् - >5.5 हेक्टेयर



## परिशिष्ट-2. चयनित फसलों की कीमतों, मात्राओं और आगम के अनुमान के लिए उपयोग किए गए डाटा का ब्यौरा

कृषि क्षेत्र के तनाव से संबंधित खंड में चित्र 13 के लिए डाटा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि मार्केटिंग सूचना नेटवर्क (एजीएमएआरकेएनईटी) से प्राप्त किया गया है। यह डाटा देश में फैले हुए मुख्य कृषि उत्पाद बाजारों, राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्डों और निदेशालयों से लिंक करता है और प्रमुख कृषि वस्तुओं के लेन देन के संबंध में प्रमुख बाजारों के लिए विविध मूल्य और आगमन रूझान का विश्लेषण करता है। इसका कवरेज राज्य एवं अखिल भारतीय दोनों स्तरों का प्रतिनिधित्व करता है।

हम कीमत एवं आगमन डाटा का उपयोग भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के लिए करते हैं। हमने राज्यों के संबंध में एक संतुलित पैनल बनाए रखने के लिए इसमें केवल ऐसे राज्यों को शामिल किया है, जिनके आंकड़े सभी वर्षों में उपलब्ध हैं। ऐसे राज्यों को उत्पाद नमूने में शामिल नहीं किया गया है, जिनके एक वर्ष का उत्पाद आगमन डाटा उपलब्ध नहीं है। सारणी-1 में दी गई सूची प्रत्येक उत्पाद के संबंध में शामिल नहीं किए गए राज्यों को दर्शाती है।

उत्पाद	शामिल नहीं किए गए राज्य
प्याज	अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा
आलू	अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडू
मूंग	अंडमान एवं निकोबार, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल
तूर	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, तेलंगाना, त्रिपुरा
गेहूं	अंडमान एवं निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, तमिलनाडू, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा

संतुलित पैनल की हमारी अपेक्षा से मिस्सिंग डाटा से परिणामों में कोई बाधा नहीं होती है। नमूने से छोड़े गए राज्य प्रत्येक उत्पाद के कुल आगमन के केवल नगण्य हिस्सा हैं। उदाहरणार्थ, बिहार के संबंध में दो वर्षों में गेहूं नमूने के लिए आंकड़ा प्राप्त न होने के कारण इस संबंधित नमूने से बिहार राज्य को छोड़ा गया है। तथापि, वर्ष 2013 जिसे वर्ष के लिए गेहूं के संबंध में बिहार से डाटा उपलब्ध है, उस वर्ष में भी बिहार में कुल आगमन का प्रतिशत केवल 0.009 प्रतिशत है। इसी प्रकार, आलू के संबंध में नमूने से बिहार को छोड़ा गया है लेकिन वर्ष 2014, जिस वर्ष के संबंध में आंकड़ा उपलब्ध है, उस वर्ष बिहार में कुल आगमन का प्रतिशत केवल 0.027 प्रतिशत है।

### पशिष्ट 3. जीवीए तथा जीडीपी के तिमाही और वार्षिक अग्रिम अनुमानों के निर्धारण की पद्धति

नीचे दी गई सारणी सेक्टरों/उप सेक्टरों के लिए प्रयोग किए गए संकेतकों और अपस्फीतिकारक अथवा संस्फीतिकारक के साथ-साथ, राष्ट्रीय अकाउंट के तिमाही एवं वार्षिक अग्रिम अनुमानों की पद्धति को दर्शाती है।

सेक्टर (क्षेत्र)	जीवीए शेयर	प्रयोग किया गया मुख्य सूचक	क्या सूचक नॉमिनल अथवा वास्तविक	नॉमिनल को वास्तविक में परिवर्तित करने हेतु अपस्फीतिकारक/वास्तविक को नॉमिनल में परिवर्तित करने का संस्फीतिकारक
कृषि	13.3	उत्पादन आंकड़ा-फसल एवं मवेशी (अंडा, दूध, मांस)	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-फसल एवं डब्ल्यूपीआई (मवेशी उत्पाद)
वन उद्योग	1.3	पिछला वृद्धि रुझान	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-औद्योगिक लकड़ी
मछली पकड़ना	0.8	इनलैंड और समुद्री मछली उत्पादन	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-मछली (इनलैंड व समुद्री)
खनन एवं उत्खनन	3.1	कोयला उत्पादन, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, आईआईपी खनन सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	वास्तविक नॉमिनल	कोयला, कच्चा तेल, लोह संबंधी एवं अन्य खनिज और खनिज तेल की भारत औसत डब्ल्यूपीआई
विनिर्माण	13.7	सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल वास्तविक	डब्ल्यूपीआई-विनिर्मित उत्पादन (श्रेणी वार संकलित)
	4.1	क्वासी कार्पोरेट और असंगठित क्षेत्र के लिए आईआईपी विनिर्माण		
बिजली	1.6	अपाईआईपी-बिजली	वास्तविक	डब्ल्यूपीआई बिजली
गैस एवं जल आपूर्ति	0.4	पिछला वृद्धि रुझान (3-4 वर्ष)	वास्तविक	
निर्माण	8.4	पक्के निर्माण के लिए: सीमेंट का उत्पादन, स्टील, आईआईपी अन्य गैर मेटैलिक खनिज उत्पादों का उपभोग; कच्चा निर्माण के लिए पिछला वृद्धि रुझान	वास्तविक	कुल डब्ल्यूपीआई
व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	10.9	वार्षिक अनुमान: के लिए प्रयुक्त सूचक ये हैं: (क) निजी कार्पोरेट क्षेत्र के लिए सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि (ख) असंगठित क्षेत्र के लिए मोटर वाहनों की बिक्री और सेवा कर (मरम्मत सेवाओं के लिए) तथा बिक्री कर (थोक बिक्री और खुदरा व्यापार के लिए) तिमाही अनुमानों के लिए प्रयुक्त सूचक सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) और सेवा कर से निजी कार्पोरेट वृद्धि है।  सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि और बिक्री कर तिमाही अनुमान के लिए सूचक के रूप में प्रयुक्त है।	नॉमिनल (कार्पोरेट वृद्धि, कर) और वास्तविक (मोटर वाहनों की बिक्री)	व्यापार की गई वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई
होटल व रेस्टोरेंट	1.1	सूचीबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल	व्यापार की गई वस्तुओं की डब्ल्यूपीआई

सेक्टर (क्षेत्र)	जीवीए श्रेयर	प्रयोग किया गया मुख्य सूचक	क्या सूचक नॉमिनल अथवा वास्तविक	नॉमिनल को वास्तविक में परिवर्तित करने हेतु अपस्फीतिकारक/वास्तविक को नॉमिनल में परिवर्तित करने का संस्फीतिकारक
रेल परिवहन	0.8	नेट टन कि॰मी॰ और यात्री कि॰मी॰	वास्तविक	सीपीआई परिवहन और संचार (सीपीआई-टीसी)
अन्य परिवहन	4.2	कॉर्पो संचालन (जल परिवहन के लिए यात्री वाहन और कॉर्पो संचालन (वायु परिवहन) वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री संबंधी डाटा का प्रयोग करते हुए सड़क पर मौजूद वाणिज्यिक वाहनों का अनुमान लगाया जाता है।	वास्तविक	सीपीआई-टीसी
संचार व प्रसार	2.0	वार्षिक अनुमानों को संकलित करने के लिए प्रयुक्त सूचक ये हैं, सूचिबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि, उपयोग संबंधी मिनुट्स (दूरसंचार के लिए) और सेवाकर (कोरियर और केबिल सेवाओं के लिए अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि को उपयोग करते हुए क्वार्टर्राईज किया जाता है।	नॉमिनल (कार्पोरेट वृद्धि कर) और वास्तविक (उपयोग संबंधी मिनुट्स)	सीपीआई-टीसी
बैंकिंग	5.5	तिमाही की समाप्ति पर कुल क्रेडिट एवं जमा में वृद्धि	नॉमिनल	गैर वित्तीय क्षेत्र जीवीए अपस्फीतिकारक
बीमा	0.9	जीवन/गैर जीवन पॉलिसियों के लिए संकलित निवल प्रिमियम	नॉमिनल	गैर वित्तीय क्षेत्र जीवीए अपस्फीतिकारक
रियल एस्टेट	0.9	सूचिबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल	सीपीआई (विविध)/कुल डब्ल्यूपीआई (निजी कार्पोरेटीड क्षेत्र)
आवास मालिकाना	6.5	वार्षिक अनुमान ग्रामीण व शहरी आवासों की संख्या में वृद्धि का उपयोग करते हुए किया जाता है। 4 तिमाहियों में समान रूप से वितरित किया जाता है।	वास्तविक	संगत सीपीआई
व्यावसायिक सेवाएं	8.1	सूचिबद्ध कंपनियों (बीएसई/एनएसई) से निजी कार्पोरेट वृद्धि	नॉमिनल	सीपीआई (विविध)/कुल डब्ल्यूपीआई (निजी कार्पोरेटेड क्षेत्र)
लोक प्रशासन एवं रक्षा	5.4	केंद्र और राज्यों की मासिक कर राजस्व वृद्धि	नॉमिनल	सीपीआई सामान्य सूचक (संयुक्त)
अन्य सेवाएं	6.8	(क) निजी क्षेत्र के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्येतर उपभोक्ता व्यय में होने वाली वृद्धि, जो एनएसएस उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण और सेवाकर से प्राप्त सूचना के अनुसार संकलित है, का उपयोग करते हुए वार्षिक अनुमान तैयार किया जाता है। इस वार्षिक अनुमान को चार तिमाहियों में समान रूप से वितरित किया जाता है।  (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, लोक प्रशासन और रक्षा हेतु प्रयुक्त वही सूचकों को आधार बनाया जाता है।	नॉमिनल	संगत सीपीआई

सेक्टर ( क्षेत्र )	जीवीए शेयर	प्रयोग किया गया मुख्य सूचक	क्या सूचक नॉमिनल अथवा वास्तविक	नॉमिनल को वास्तविक में परिवर्तित करने हेतु अपस्फीतिकारक/वास्तविक को नॉमिनल में परिवर्तित करने का संस्फीतिकारक
अप्रत्यक्ष कर		केन्द्र तथा राज्यों के कर राजस्व संबंधी मासिक आंकड़े	नॉमिनल	उत्पादों पर करों की स्थिर कीमत का अनुमान बहिर्वेशन मात्रा द्वारा संकलित किया जाता है, विभिन्न उत्पाद करों के लिए बहिर्वेशन मात्रा की गणना अलग से की जाती है। विनिर्माण की आऊटपुट मात्रा में वृद्धि, सेवाएं (लोक प्रशासन एवं रक्षा को छोड़कर) और आयात बहिर्वेशन के लिए प्रयुक्त सूचक है।
सब्सिडी		केंद्रीय सरकार के लेखों से उपलब्ध प्रमुख सब्सिडियों पर व्यय को सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है।	नॉमिनल	जीवीए अपस्फीतिकारक

टिप्पणी: 1. एमसीए ( कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ) के डाटाबेस को प्रथम संशोधित अनुमान के रूप में उपयोग किया जाता है और अग्रिम और तिमाही अनुमानों के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है।

## परिशिष्ट 4. एमएनआरईजीए पर विमुद्रीकरण के प्रभाव और प्रतीपगमन (रिग्रेशन) के परिणामों के आकलन के लिए पद्धति

हम एमजीएनआरईजीएस के तहत सृजित श्रम दिवसों पर विमुद्रीकरण के प्रभाव मापने का प्रयास कर रहे हैं जो परिकल्पना जांच के रूप में है कि विमुद्रीकरण सामाजिक इश्योरेंस के लिए अधिक मांग का कारण बन गया। ऐसा करने के लिए हम भिन्न रणनीति अपनाते हैं<sup>26</sup> हम नवंबर 8 के पश्चात् और नवंबर 8 के पूर्व के सप्ताह में एमजीएनआरईजीएस श्रम दिवसों की तुलना करते हैं और अध्ययन करते हैं क्या यह अंतर पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में विशेष रूप से अधिक था। वर्ष 2016-17 में विमुद्रीकरण के पूर्व और पश्चात् मानव दिवसों में इस प्रकार हुए बदलाव से संबंधित स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट होना चाहिए कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में ऐसा अंतर क्यों हुआ। ये रिग्रेशन जिलों को विभिन्न रूप से प्रभावित कारकों को भी नियंत्रित करते हैं।

औपचारिक रूप से हम एस्टीमेट करते हैं:

$$\text{Log}(\text{Man-days})_{d,w} = \alpha_1(\text{Post}) + \alpha_2(\text{Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_3 \text{FE}_{d,m} + \alpha_4 \text{FE}_{d,y} \quad (1)$$

यहां Log(man-days) किसी जिले में, किसी निर्दिष्ट सप्ताह में सृजित मानव दिवसों के स्वह मूल्य को दर्शाता है; d,w,m और y क्रमशः जिला, सप्ताह, महीने और वर्ष का संकेत करते हैं। Post एक डमी है जो सभी सप्ताहों (वर्ष के विचार किए बिना) के लिए एक का मूल्य रखता है। विमुद्रीकरण एक डमी है जो वर्ष 2016-17 में सभी सप्ताहों (जब विमुद्रीकरण हुआ है) के लिए एक का मूल्य रखता है। FE<sub>d,m</sub> जिला, महीना स्थिर प्रभावों का संकेत करते हैं। FE<sub>d,y</sub> जिला-वर्ष के स्थिर प्रभावों का संकेत करते हैं। मानक गलतियों का जिला माह स्तर पर क्लस्टर किया गया है, ऐसा सहसंबंध आंकलन की जा रही गलतियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है।

ब्याज का गुणांक 2 - है जो विमुद्रीकरण अवधि का औसतन प्रभाव है।

हमारी पूर्व-विंडो में विमुद्रीकरण के पहले के 8 सप्ताह शामिल है। इसको इसलिए चयन किया गया था कि वर्ष 2016-17 में 25 सप्ताह में सृजित मानव दिवस पूर्व चार वर्षों में सृजित मानव दिवसों के बिल्कुल समान है। हमारा अनुसंधान डिजाइन समांतर रुझान अनुमान के रूप में जो ज्ञात है उस पर आश्रित करता है। यह बताता है कि विमुद्रीकरण न होने की स्थिति में, पूर्व वर्षों की तुलना में वर्ष 2016-17 में भी प्रवृत्ति उसी प्रकार समान रूपी बनी रही होती। 8 सप्ताह कट ऑफ इस मापदंड को पूरा करने के लिए है। लेकिन, जहां हम इस विंडो का विस्तार एवं संकुचन दोनों करते हैं वहां परिणाम भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त, चित्र 24-27 का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि समांतर प्रवृत्ति अनुमान उत्तर प्रदेश, जहां वर्ष 2016-17 में वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्षों की तुलना में एमजीएनआरईजीएस का उपयोग बहुत ज्यादा था, पर प्रभावी नहीं है। इसलिए, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तर प्रदेश के बिना हमें मजबूती के लिए जांचना चाहिए।

हम इस प्रकार भी एस्टीमेट करते हैं:

$$\text{Log}(\text{Man-days})_{d,w} = \alpha_1(\text{Post}) + \alpha_{21}(4 \text{ weeks-Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_{22}(5-10 \text{ weeks-Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_{23}(\text{Beyond 10 weeks-Post} * \text{Demonetization}) + \alpha_3 \text{FE}_{d,m} + \alpha_4 \text{FE}_{d,y} \quad (2)$$

इस स्पेसिफिकेशन में, विमुद्रीकरण के बाद की अवधि को तीन विंडो में विभाजित किया गया है। क्या समय के साथ प्रभाव में भिन्नता हुई है, इसके आकलन करने के लिए ऐसा किया है।

सारणी 1 और 2 क्रमशः स्पेसिफिकेशन 1-2 के लिए हमारे प्रतिगमनों के परिणामों को औपचारिक रूप से प्रस्तुत

<sup>26</sup> Bertrand, M., Duflo, E., Mullainathan, S., "How much should we trust in difference-in-difference estimates?", Quarterly Journal of Economics (2004), 249-275. [http://www.utdallas.edu/~d.sul/Econo2/Marianne\\_etal\\_QJE\\_04.pdf](http://www.utdallas.edu/~d.sul/Econo2/Marianne_etal_QJE_04.pdf)

करती हैं।

अतः बेस लाईन में जो समग्र देश को कवर करता है हम यह देख सकते हैं कि विमुद्रीकरण से एमजीएनआरईजीएस रोज़गार के लिए मांग 10 प्रतिशत तक बढ़ गई (कॉलम-1)। इस नमूने को कम विकसित राज्यों (कॉलम-2) तक सीमित करते हुए यह पाया जाता है कि 39 प्रतिशत एमजीएनआरईजीएस विमुद्रीकरण का प्रभाव अधिक था। कॉलम-3 में हम नमूने को उत्तर प्रदेश तक सीमित करते हैं और जिस पर कोई प्रभाव नहीं है। हम, कॉलम-4 में चार सप्ताहों तक सिकुड़ते हुए और कॉलम-5 में 12 सप्ताह तक विस्तार करते हुए कॉलम 4 और 5 में फ्री विंडों में परिवर्तन करते हैं। परिणाम क्रमशः सुदृढ़ और कमजोर नजर आते हैं। कॉलम-6 में विमुद्रीकरण के पश्चात् पांच सप्ताहों के लिए निरीक्षण करते हैं और यह पाया जाता है कि सकारात्मक प्रभाव जारी रहता है। कॉलम-7 में, नमूने से दो सूखे वर्षों को ड्राप करते हैं जो इसी प्रकार के कृषि संबंधी वर्षों तक तुलना को सीमित रखने के लिए है और इसका परिणाम सांख्यिकीय तरीके से महत्वपूर्ण नहीं होता है।

विमुद्रीकरण अवधि को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने को छोड़कर सारणी-2 सारणी-1 के समान है। 3 अलग-अलग अवधियों का सबूत है: प्रथम चार सप्ताह की 'घोक' अवधि जिसमें एमजीएनआरईजीएस के लिए मांग में गिरावट (बेसलाइन में 25 प्रतिशत तक) हुई, उसके बाद छः सप्ताह का 'वसूली' चरण, जिसमें एमजीएनआरईजीएस के लिए कोई देखने लायक मांग नहीं है और आखिर में बाद के 10 सप्ताहों के गतिवर्धन का चरण, जिसमें एमजीएनआरईजीएस

सारणी 1: एमजीएनआरईजीएस रोज़गार पर विमुद्रीकरण का संभावित प्रभाव

	(1) बेसलाइन	(2) कम विकसित राज्य	(3) केवल उत्तर	(4) सप्ताह 29 से प्रदेश	(5) सप्ताह 21 से	(6) ड्रॉपिंग सप्ताह 33-36	(7) सूखे वर्षों को छोड़ते हुए
विमुद्रीकरण प्रभाव	0.10*** (0.02)	0.39*** (0.03)	0.04 (0.07)	0.23*** (0.03)	-0.05** (0.02)	0.20*** (0.02)	0.02 (0.02)
आर-स्कोर	0.81	0.81	0.77	0.83	0.8	0.82	0.84
# प्रेक्षण	82607	28631	9688	69844	95397	69874	49425

सारणी 2: एमजीएनआरईजीएस रोज़गार पर विमुद्रीकरण का संभावित प्रभाव: विमुद्रीकरण के सभी विन्डो के संबंध में

	(1) बेसलाइन	(2) कम विकसित राज्य	(3) केवल उत्तर	(4) सप्ताह 29 से प्रदेश	(5) सप्ताह 21 से	(6) सूखे वर्षों को छोड़ते हुए
विमुद्रीकरण से पहले 4 सप्ताहों में हुआ प्रभाव	-0.25*** (0.03)	-0.09** (0.04)	-1.11*** (0.10)	-0.12*** (0.03)	-0.39*** (0.03)	-0.28*** (0.03)
विमुद्रीकरण से 5-10 सप्ताहों में हुआ प्रभाव	0.00 (0.03)	0.25*** (0.04)	-0.27*** (0.09)	0.13*** (0.03)	-0.14*** (0.03)	-0.06** (0.03)
10 सप्ताहों के बाद विमुद्रीकरण का प्रभाव	0.27*** (0.02)	0.63*** (0.04)	0.60*** (0.07)	0.41*** (0.03)	0.13*** (0.02)	0.19*** (0.03)
आर-स्कोर	0.81	0.82	0.8	0.83	0.8	0.85
# प्रेक्षण	82607	28631	9688	69844	95397	49425

की मांग में 27 प्रतिशत की भारी उछाल दिखाई दी।

यह सभी परिणाम सूचक हैं, निष्पक्ष नहीं हैं। इसके व्यापक परिणाम रोचक एवं संकीर्ण दोनों हैं और विमुद्रीकरण-एमजीएनआरईजीएस के संबंध को सुलझाने के लिए और अनुसंधान की आवश्यकता है।

मापे गया परिणाम प्रति सप्ताह प्रति जिला मानव दिवसों का लॉग है। सभी प्रतिगमन (रिग्रेशन) सभी जिलों के लिए है। प्रत्येक वित्त वर्ष के सप्ताह 25-52 को कॉलम (1) में बेसलाइन स्पेसीफिकेशन में एक बार विचार किया गया है। हमने इस प्रकार इसलिए किया कि सप्ताह 25 में, चालू वर्ष में औसतन व्यय तथा पिछले वर्षों के औसतन व्यय बिल्कुल समान रहे। सभी प्रतिगमनों (रिग्रेशन) से हमने सप्ताह 40 और सप्ताह 41 को छोड़ दिया है क्योंकि वे पूर्व-2016 के वर्षों में मानव दिवसों में अस्पष्ट रूप से नीचे दिखाने का स्वभाव है। विमुद्रीकरण सप्ताह 33 को हुआ। अतः विमुद्रीकरण के पश्चात होने वाली भिन्नता वर्ष 2016 में सप्ताह 33 के दौरान तथा उसके पश्चात की अवधि के लिए मानव दिवसों के लॉग पर अंतर लाने वाला प्रभाव दर्शाती है। कॉलम (2) में केवल बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान राज्यों के जिले शामिल हैं। कॉलम (3) में केवल उत्तर प्रदेश के जिलों से संबंधित प्रतिगमन (रिग्रेशन) दिखाता है। कॉलम (4) में 29-52 के बीच के सभी सप्ताह शामिल हैं। कॉलम (5) में 21-52 के बीच के सभी सप्ताह शामिल हैं। कॉलम (6) में सारणी 1 में 33-36 सप्ताह को छोड़ा गया है, विमुद्रीकरण के पश्चात 4 सप्ताहों में मानव दिवसों में हुई असाधारण कमी को दिखाने के लिए ऐसा इसलिए किया गया। सारणी 1 में कॉलम 7 तथा सारणी 2 में कॉलम 6 में वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 के 2 सूखे वर्षों को छोड़ा गया है ताकि तुलना को अच्छे मानसून वर्षों में सीमित रखा जा सके। जिला-वर्ष और जिला-महीना सहित सभी प्रतिगमनों (रिग्रेशन) को नियत प्रभाव हैं। सभी मानक त्रुटियों को जिला-महीने स्तर पर क्लस्टर किया गया है, जो इन त्रुटियों के परस्पर संबंध से बचने के लिए है।

*\*p<0.01, \*\*p<0.05, \*\*\*p<0.01*



**परिशिष्ट 5. सेक्शन VI.5 में वृद्धि संरूपण प्रक्रिया के लिए उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं का नमूना।**

- 
1. अर्जेंटिनिया
  2. कोरिया
  3. बोलिविया
  4. चिली
  5. भारत
  6. ब्राजील
  7. इंडोनेशिया
  8. मलेशिया
  9. मैक्सिको
  10. फिलिपिन्स
  11. साउथ अफ्रीका
  12. थाइलैंड
  13. तुर्की
  14. वियतनाम
  15. कॉलम्बिया
  16. चीन
  17. पॉलैंड
  18. रूमानिया
  19. पेरू
  20. बंगलादेश
  21. ईजिप्ट
  22. इजराइल
  23. मोरिशस
  24. सिंगापुर
-